श्री उपसभापतिः दोनों मिनिस्टर्स आए हुए हैं। **...(व्यवधान)...** आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** Both are here. ...(*Interruptions*)... Now, Mr. A.U. Singh Deo, you can start. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM: Please direct the Minister not to say 'you sit down'. That is not the responsibility of the Minister. We have a right to say things. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Agreed; now, Shri A.U. Singh Deo to start the Short Duration Discussion.

सुश्री उमा भारतीः सर, मेरा आपके माध्यम से...

श्री उपसभापतिः हो गया, हो गया। **...(व्यवधान)...**

सुश्री उमा भारतीः उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से हाउस से एक निवेदन है कि हमको कहा गया, मुझे भी और राधा मोहन जी को भी कि हम उपस्थित रहें। मुझे भी कहा गया कि आप जवाब देने के लिए उपस्थित रहें। मेरा मानना है कि **...(व्यवधान)...**

श्री नीरज शेखरः उपसभापति जी, इस चर्चा का जवाब कौन देगा? **...(व्यवधान)...**

सुश्री उमा भारतीः मैं आपको बता रही हूं। सर, मेरा आपके माध्यम से हाउस से कहना है, यह तो वरिष्ठ जनों की सभा है। मेरा इनसे निवेदन है कि मैं यहां मौजूद हूं और कृषि मंत्री जी भी मौजूद हैं। आप बता दीजिए कि आपको किससे उत्तर चाहिए? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापतिः आप दोनों बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...** मंत्री जी, आप बैठ जाइए। **...(व्यवधान)...**

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, इनको राधा मोहन सिंह जी का जवाब पूरा सुनना पड़ेगा। **...(व्यवधान)...**

SHORT DURATION DISCUSSION

Serious situation arising out of prevailing drought and heat wave conditions and resultant water crisis in country

SHRI A. U. SINGH DEO (Odisha): Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir. I beg to move a grave matter prevailing in the country today in terms of agricultural problems, farmers' problems and water shortages in our country today. Sir, before I proceed, I would like to know how much time you have allotted me.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your party's time is only four minutes. Being the initiator, you will get maximum 15 minutes. But all others will stick to their party's time.

SHRI A. U. SINGH DEO: Sir, as per the data consolidated by the Central Government, around 33 crore people, or 25 per cent of the total population living in 2.55 lakh villages in 254 districts of 10 States, are affected due to drought. This is the information with me. The number will possibly increase. Perhaps, Bihar and Haryana have not yet declared drought despite shortages of rainfall.

Sir, India has been a victim of two consecutive droughts. In 2015, rainfall was deficient by 14 per cent. In 2014, the rainfall was deficient by 12 per cent. The drought caused severe damages to Rabi and Kharif crops. Estimated crop loss of Rabi in 2015 alone is around ₹ 20,453 crores. Sir, this is, perhaps, the third time in the last century that the country has experienced consecutive droughts. Thirty-nine per cent of the land area was affected in 2015, that is, approximately 1.9 crore hectares of land. Scant and deficient rainfall continued even after the monsoons.

सर, मानसून के बाद 2014-2015 में rainfall scanty रहा, groundwater कम हो गया। Water availability जो Indian reservoirs में थी, वह 29 per cent पर आ गई, the lowest in the decade. Meteorological Department ने last year predict किया था कि September में rain कम होगी । सरकार ने इसमें नोटिस नहीं लिया। मैं तो समझता हूं कि अब यह कुम्भ का मेला नहीं रहा, जो 12 साल में एक बार आता है। यह लगातार साल-दर-साल आ रहा है। मैं तो ऐसे मौके पर यह कहूंगा कि सरकार को एक नया Department बनाना चाहिए। वह drought, flood, national disasters, earthquakes, climate change इत्यादि को एक Department में consolidate करे और उसमें अध्ययन किया जाए और यह कोशिश की जाए कि इसको कैसे सुधारें।

सर, आपकी कृपा से और सदन की कृपा से एक National Platform for Disaster Risk Reduction में मुझे मेम्बर बनाया गया है। सर, मुझे खेद है कि डेढ़ साल में इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। सर, मैं आपके through सरकार को remind कराना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे मौके पर तो मीटिंग बुलाई जाए, जिसमें हम सभी लोग अपनी राय दे सकें। सर, relief क्या है? हम जो relief देते हैं, वह stopgap measures पर सरकार देती है। They are not compensation packages. हम अगली crop कैसे बनाएं, उस पर relief मिल जाती है, but payback of loans, drinking water, buying fodder for animal इसमें कुछ नहीं है। सर, मैं आपको ओडिशा सरकार का एक example देता हूं। 2015 में ओडिशा ने डिमांड की थी for ₹ 2,344.99 crores from the Central Government from the National Disaster Relief Fund. ये finances मांगे थे crop loan के लिए, revival of minor irrigation के लिए, projects के लिए, food assistance के लिए, fodder for cattle के लिए, तो उसमें हमको 815 करोड़ दिया गया input subsidy के लिए। बाकी जो हमारे हैड्स थे, हमें उसमें कुछ नहीं मिला, जैसे conversion of crop loan, revival of minor irrigation projects, provision of fodder for cattle, food assistance, drinking water इत्यादि। सर, long-term planning होनी चाहिए। हमें यह Short-term planning दिखती है। हम relief determine कैसे करते हैं relief determine करने के लिए हर स्टेट का अपना हिसाब-किताब है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का यह है कि दो हेक्टेयर से ज्यादा relief नहीं देंगे, चाहे आपके पास 3 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर जमीन क्यों न हो। हमें इसे ओर broad-base करके देखना चाहिए। हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर relief examine करने का

[Shri A. U. Singh Deo]
हिसाब-किताब लगाना चाहिए। सर, हम अपनी स्टेट्स में जो farmer's loss measure करते हैं, कोई स्टेट ब्लॉक्स को यूनिट बनाता है, कोई सब डिविजन को यूनिट बनाता है।

कोई eye estimation में जाता है, कोई पटवारी को भेजता है। इसमें एक disparity आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असेसमेंट दूसरा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का असेसमेंट दूसरा होता है। Lack of standardization for declaring drought relief creates space for the Centre and the States to blame each other for poor relief. सर, फिलीपीन्स वगैरह में drought assess करने के लिए unmanned vehicles, aerial vehicles, drones technology लगायी जाती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भेदभाव होने की संभावना नहीं रहती।

To increase the relief, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। Earlier, the farmers were not eligible for relief. पहले 50 परसेंट डैमेज पर उनको रिलीफ मिलती थी, आजकल 33 परसेंट पर मिलती है। Compensation for crops in areas with assured irrigation has increased by fifty per cent. 1982 में 2,200 रुपए per bigha रिलीफ मिलती थी, आज उसे 3,300 रुपए per bigha कर दिया गया है। सर, आप inflation value देखिए। Accounting for inflation shows that ₹ 2,200 in 1982 would be equivalent to ₹ 20,209 now - an increase of 9.2 times or 820 per cent. इसे सेंट्रल गवर्नमेंट को rationalize करना होगा। सर, फंड्स को रिलीज़ करने में बहुत delay होता है। Accelerated Irrigation Benefit Programme में ओडिशा गवर्नमेंट ने 2015-16 में 1,889 करोड़ रुपए मांगे थे। इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को 743.40 करोड़ रुपए उनके शेयर के लिए सब्मिट किए गए, लेकिन हमें अभी तक केवल 286.50 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। इसमें हमने यह anticipate करके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ देगी, अपने पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। हम खर्च करते चले गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है — यह बड़े दुख की बात है। KBK (Koraput-Bolangir-Kalahandi) District in Odisha is treated at par with North-Eastern Region Districts as a special category District and avails ninety per cent grant under Centrally-Sponsored Schemes. How is that under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, the funding pattern for KBK has been reduced to sixty per cent? हमें क्यों मार्क किया जा रहा है? वह इस कंट्री का सबसे गरीब एरिया है। We should be treated at par with the North-Eastern States. हमें इसमें unnecessarily मार्क किया जा रहा है। It is a matter of concern. I would request the hon. Minister and the Government to look into the matter.

सर, 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस आया था। तीस साल बाद आज भी ये statistics हैं कि only twenty per cent of the farmers have access to the crop insurance. इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इस पर अध्ययन करे और एक रास्ता निकाले।

ओडिशा में एक के बाद एक natural calamities आती रहती हैं। In 2013, Odisha was devastated by cyclone Phailin. The Government of Odisha sought assistance of ₹ 5,832.50 crores. However, assistance of only ₹ 750 crores was received. The Government of Odisha then lodged a protest with the Central Government for more funding. फिर इन्होंने हमें 399.33 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 149.11 करोड़ रुपए अभी भी बाकी हैं।

हमने अपने resources में से 216 करोड़ रुपए खर्च किए। इस प्रकार ये जो ओडिशा की समस्याएं हैं, इन्हें कौन संभालेगा? ऐसी और भी स्टेट्स होंगी। In 2014, Odisha suffered due to cyclone Hudhud. Both the cyclones were followed by heavy and incessant rainfall causing flash floods. In 2015, the Odisha State Government declared 123 blocks spread over 14 Districts to be affected by drought. गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने 2,344 करोड़ रुपए की डिमांड की है, लेकिन अभी तक हमें केवल 815 करोड़ रुपए ही मिले हैं। Further, the Central Government unilaterally amended the provision to deduct fifty per cent of SDRF balance as on date of approval of scheme from the SDRF balance on 31st March of the preceding financial year without consulting the State Government. इससे हमारी स्टेट ओडिशा को 202.77 करोड़ का लॉस हुआ है। इसे देखा जाए। आज, 2016 में हमने 29,176 villages of 3,832 Gram Panchayats under 235 blocks डिक्लेयर किए हैं, इसे देखा जाए।

हमने एमरजेंसी वाटर सप्लाई के लिए पैसे मांगे हैं, इसे देखने की जरूरत है। Sir, State Governments have lack of funds. The first responder in the case of any disaster is the State Government. The State Governments do not have active funds. As mandated by the Finance Commission, States are required to deal with drought and such other disasters through State Disaster Relief Fund (SDRF). The total funding allocated to SDRF for all States for five years is about ₹ 61,000 crores. Therefore, it comes to ₹ 12,000 crores per year for all States. The estimated crop loss to the Rabi crop alone in 2015 was ₹ 20,000 crores. ये पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा?

सर, हमें क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने की जरूरत है। Drought-resilient crops like jowar, bajra, oilseeds like groundnut and sunflower have replaced water- guzzling crops like cotton, sugarcane, soyabean, etc. जब हम इसे चेंज करेंगे, बदलेंगे तथा जो और क्रॉप्स लाएंगे, उसमें ज्यादा पानी खर्च नहीं होता, वह हमारे लिए लाभदायक होगा। Government should not allow farmers to grow sugarcane in drought-affected areas. Farmers should be encouraged to shift from mono-cropping to intercropping. This will minimize risk of farmers and drastically reduce water consumption.

सर, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है, उसमें हम अपने देश में देख रहे हैं कि आज फ्लड्स, ड्राउट्स, साइक्लोन्स इत्यादि बहुत जोर से आते हैं। यह हमारे ऊपर क्लाइमेट चेंज की निशानी है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से आज तक कोई एलोकेशन नहीं मिला for the National Adaptation Fund on Climate Change for the year 2015-16 and 2016-17. यह एक बड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा खाली भारत में ही नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर प्रधान मंत्री और हमारे कंसन्ड्र मंत्री भी देश-विदेश जा चुके हैं। हम इसको सीरियसली, academically ले रहे हैं। **...(समय की घंटी)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have two more minutes.

SHRI A. U. SINGH DEO: Yes, Sir. I am finishing. हम उसको बिल्कुल एक्शन में नहीं ला रहे हैं। The Government must develop a long-term action plan. The Central

[Shri A. U. Singh Deo]

Government must consider creating a separate Ministry to address the problems like climate change.

Sir, in 2013-14, person days of employment offered under MGNREGA went down from 220 crore person days to 166 crore person days in 2014-15. इस पर भी इफेक्ट आ रहा है। In drought-affected States, employment generation came down from 96 crores person days in 2013-14 to 67 crore person days in 2014-15. सर, हमारे पास जो करेंट तथ्य है, इसमें Central Government owes about ₹ 7,983 crores to rural workers in wages for the last year और फंड्स काम करने के बाद रिलीज़ होते हैं। तब स्टेट्स के पास फंड्स होते नहीं हैं, इसलिए हर चीज़ में डिले होता चला जाता है। ...**(समय की घंटी)**...

सर, आपने दो बार घंटी बजा दी है, I won't take more of your time as I had enough time. I really feel, हमें एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर क्लाइमेट चेंज़, फूड्स, फ्लड्स और ड्राउट इत्यादि विषय एक मंत्रालय में रहें, जिसमें फंडिग हो, अध्ययन हो और टेक्नोलॉजी लगे। उसमें सभी स्टेट्स भाग लेने की कोशिश करें, उन्हें चांस मिले, जिसमें वे अपने सजेशन्स दे सकें और हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। सर, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, hon. Members, Shri Sharad Pawar has to go early. So, with your consent, I am calling his name. Shri Sharad Pawar.

श्री शरद पवार (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदय, आज देश के सामने सूखे का एक बहुत बड़ा संकट आया है। मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में कई साल सूखे की परिस्थिति सँभालने के लिए कुछ न कुछ कोशिश की है। जब मैं राज्य में जिम्मेदारी सँभालता था, तब भी ऐसी स्थिति मेरे सामने पैदा हुई थी और पिछले 10 साल जब मैंने भारत सरकार में काम किया, तब भी ऐसी परिस्थिति आई थी, मगर आज जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति को देखने के बाद और खास तौर से देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/प्रिंट मीडिया जिस तरह से इस स्थिति के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि यह वास्तविकता से बहुत दूर है। आप कोई भी टेलीविजन चैनल देखिए, तो महाराष्ट्र के सूखे की परिस्थिति सामने आती है। लातूर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम कई जगह बार-बार आता है। यह बात सच है कि वहां की स्थिति गम्भीर है, मगर पूरे देश के सूखे के बारे में स्थिति जानने की कोशिश करने के बाद और राज्यों से सम्पर्क साधने के बाद उन्होंने जो information दी, उससे एक पक्की बात सामने आती है कि इस साल का सूखा कुछ दो-तीन-चार राज्यों तक सीमित नहीं है। यह सूखे की परिस्थिति इस समय देश के 11 स्टेट्स में पैदा हुई है। जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कई बार हमने इस स्थिति पर ध्यान दिया था, मगर तब स्थिति ऐसी थी कि यह स्थिति कभी झारखंड में थी, कभी महाराष्ट्र में थी, तो कभी गुजरात के सौराष्ट्र या कुछ एरिया में थी, मगर अभी देश के 11 राज्यों में यह परिस्थिति पैदा हुई है और सबसे भीषण परिस्थिति उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 50 डिस्ट्रिक्ट्स affected हैं। यह Government of India का official statement

है, जिसमें 72,014 villages are affected and 9 करोड़ 80 लाख की आबादी इसमें फँसी है। जब एक ही राज्य में 9 करोड़ 80 लाख की आबादी इसमें फँसती है, तो यह संकट की स्थिति कहां तक गम्भीर है, यह बात हम लोगों के सामने आती है।

दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। हम हमेशा सोचते थे कि नर्मदा के पानी का सवाल खत्म होने के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश की परिस्थिति में बहुत बदलाव आ गया है। हमें दो-तीन बार अखबार में कुछ स्टेटमेंट्स भी मिलीं कि मध्य प्रदेश और गुजरात में agricultural growth देश की growth से दोगुनी हो गई है, मगर वहां जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में 51 डिस्ट्रिक्ट्स में से 46 डिस्ट्रिक्ट्स में आज drought की परिस्थिति पैदा हुई है, जिसमें 42,829 villages have been affected and 4 crore population आज इस संकट में फँसी हुई है।

तीसरा राज्य है महाराष्ट्र। वहां 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जहां सूखे की स्थिति है, जिसमें 15,700 villages affect हुए हैं और 3 करोड़ 70 लाख आबादी इस परिस्थिति का सामना कर रही है।

इसके बाद कर्णाटक है, जहां 3 करोड़ 11 लाख लोग इस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। कर्णाटक के 30 डिस्ट्रिक्ट्स में से 27 डिस्ट्रिक्ट्स affected हैं। आंध्र प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे से अफेक्टेड हैं, जहां 2 करोड़ 35 लाख की आबादी इस संकट का सामना कर रही है। इसके बाद, छत्तीसगढ़ में हमें सूखे की स्थिति देखने को मिलती है, जहां 27 डिस्ट्रिक्ट्स में से 25 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे से ग्रस्त हैं। वहां पर 16,900 गांवों में, 1 करोड़ 99 लाख 44 हजार की आबादी सूखे की परिस्थिति का सामना कर रही है। ऐसी ही स्थिति झारखंड में भी है, जहां 24 में से 22 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे से ग्रस्त हैं। वहां 3 करोड़ 17 लाख की आबादी सूखे की चपेट में फंसी है। तेलंगाना की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 डिस्ट्रिक्ट्स सूखे की स्थिति से गुजर रहे हैं। वहां पर 1 करोड़ 80 लाख की आबादी सूखे से प्रभावित है। राजस्थान की स्थिति भी ऐसी ही है और राजस्थान से कुछ ही कम सूखे की स्थिति गुजरात में है। इस तरह आज 11 राज्यों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो अथवा अलग-अलग राजनैतिक दल हों, हम सभी के सामने बहुत बड़े संकट की स्थिति पैदा हो गई है। आज हम सब लोगों को राजनीति छोड़कर, राजनीति से ऊपर उठकर इस परिस्थिति का सामना करने की आवश्यकता है। हमारे कई साथी सूखे के संकट से ग्रस्त हैं, इसलिए हम लोगों को सिर्फ उनके बारे में सोचने की जरूरत है कि उनको हम किस तरह से मदद दे सकते हैं।

हमने देखा, तीन साल पहले हिन्दुस्तान के किसानों ने हमें इतनी पैदावार दी, जितनी इससे पहले कभी नहीं दी थी। आज हिन्दुस्तान में अनाज की स्थिति अच्छी है, देश में अनाज की कमी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह के कदम उठाए गए थे, उनके नतीजे हम आज देख रहे हैं। हमारे अनाज के भंडार आज भी भरे हुए हैं।

मुझे याद है, 1972 में भी हमारे यहां सूखा पड़ा था, उस समय मैं राज्य में काम करता था, लेकिन तब अनाज की परिस्थिति बहुत गंभीर थी। उस समय हमारा पूरा ध्यान कनाडा, अमरीका या विदेशों से आने वाले अनाज पर रहता था। जब मुम्बई के पोर्ट पर जहाज लगता था, तो हम लोगों का ज्यादा ध्यान इसी चीज़ पर रहता था कि कैसे वहां से जल्दी से जल्दी हम अनाज को

[श्री शरद पवार]

बाहर निकालें और कैसे उस अनाज को जल्दी से जल्दी गांवों तक पहुंचाएं। उस समय अनाज का भंडार कम था, लेकिन पीने के पानी की स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। इस साल पहली बार हम यह देख रहे हैं कि सभी राज्यों में पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। कई सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों में देखा होगा और कई लोगों ने टेलिविज़न पर देखा होगा कि अगर कहीं से पानी का कोई टैंकर आ गया, तो लोग उस टैंकर का घेराव कर लेते हैं। मैंने अपने राज्य महाराष्ट्र में देखा कि जहां टैंकर आते हैं, जहां टैंकरों में पानी भरने की जगह है, वहां महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि पानी के कारण वहां पर एक तरह के संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए पानी की समस्या पर हमें पूरा-पूरा ध्यान देना पड़ेगा।

जैसा मैंने बताया कि इतने सारे राज्यों में सूखे की स्थिति है, उन राज्यों में पीने के पानी की स्थिति और भी अधिक खराब है। हम लोगों को सूखे की समस्या से उबरने के लिए long term and short term measures अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले पानी की समस्या के समाधान के लिए immediate measures अपनाने की आवश्यकता है। टैंकर के बिना पानी नहीं दिया जा सकता है। अकेले मेरे स्टेट में 4,000 से ज्यादा टैंकर हैं, जिनमें एक-एक टैंकर हर दिन तीन-तीन, चार-चार ट्रिप देता है और वहां के लोगों तक पानी पहुंचाने का प्रबंध करता है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे यहां नासिक और मनमाड़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां रेलवे का बड़ा जंक्शन है। वहां की आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है, लेकिन वहां पर 30 दिन में सिर्फ एक बार पानी मिलता है। Only once in 30 days! इसी तरह दूसरे कई डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे लातूर है। मैं भारत के रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सूखे के क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए कृष्णा रिवर से वहां तक के लिए रेलगाड़ी का प्रबंध कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर हर दिन पानी की जितनी जरूरत है और वहां पर जितना पानी सप्लाई होता है, वह सिर्फ 33 प्रतिशत के आसपास है। उनके लिए वह पानी पूरा नहीं पड़ता है और वहां के नागरिकों को एक बार पानी मिलने के बाद अगली बार पानी लेने के लिए कम से कम 20 दिन तक राह देखनी पड़ती है।

कई ऐसे शहर हैं, जहां इसके लिए 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 30 दिनों तक रुकना पड़ता है। आज उन सब लोगों का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि मैं पानी कैसे लाऊँगा, कैसे सम्भालूँगा और अगले दिन ठीक तरह से पानी सम्भाल कर मैं कैसे इस्तेमाल कराऊँगा। ऐसे में हम ड्रिंकिंग वॉटर के बारे में क्या-क्या कर सकते हैं, यह देखने की बहुत आवश्यकता है। कई जगहों पर हम जमीन से ज्यादा पानी निकालते हैं। आज हमें वॉटर कंजर्वेशन के लिए सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता है कि बारिश में जो पानी आता है, इसकी हरेक बूँद को हम कैसे रोक सकते हैं। छोटे-छोटे तालाब बनाकर, सर्फेस वाटर लेवल बढ़ा कर वहां के पीने के पानी की परमानेंट समस्या कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इस देश में इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स बहुत लिए गए हैं। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स में आज दो किस्म की परिस्थितियां सामने आती हैं। कई राज्य ऐसे हैं कि वहां इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स पूरे तो हुए हैं, मगर वहां बारिश नहीं हुई, जिसके कारण वहां डैम्स में पानी नहीं है और कई राज्य ऐसे हैं कि वहां पिछले 25 सालों से इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स का काम चालू ही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। अभी जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अवधि अगर देखें, तो यह जो नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम्स है, इस नेशनल रिजस्टर में there are 312 projects which

are incomplete for the last 25 years. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को बाकी सब कार्यक्रमों को रोक कर ये जो incomplete इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हम जल्दी से जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए। मैंने जो 312 की यह फिगर आपको बताई, इनमें से 240 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जो सिर्फ 5 राज्यों में हैं। ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। इन 5 राज्यों में 240 प्रोजेक्ट्स पिछले 25 सालों से आज तक अधूरे हैं। वहां ज्यादा मदद करने की आवश्यकता है। बाकी प्रोजेक्ट्स इस देश में बड़े पैमाने पर हुए हैं, मगर इसमें एक ऐसा इंप्रेशन है कि कई राज्यों में इसका इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि कहीं-कहीं पर पानी का इस्तेमाल करने के बारे में किसानों का ध्यान बड़ा अच्छा होता है। वे पानी के इधर-उधर जाने का कभी मौका ही नहीं देते और पानी की हर बूँद वे किस तरह से सम्भाल सकते हैं, सम्भालते हैं और इस पर उनका ध्यान हमेशा रहता है।

आज महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक इंप्रेशन बना है, जैसा अभी जब मेरे एक साथी बोले तो उन्होंने कहा कि कौन सी फसल लेने की आवश्यकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश में अलग-अलग किस्म की फसलों की आवश्यकता होती है। अनाज पैदा करना हो, तो चाहे गेहूँ की आवश्यकता होती है या चावल की आवश्यकता होती है और हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, गन्ने की भी आवश्यकता होती है। मगर अभी हम लोगों को सोचना होगा कि यह पानी हम किस तरह से और कौन सी फसल के लिए लेते हैं और कुछ फसलों के ऊपर जो एक तरह का क्रिटिसिज्म होता है, वहां की भी स्थिति क्या है, यह समझना चाहिए। देश के कृषि मंत्री जी ने कल कहीं बयान दे दिया और आज के अखबार में आया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इरिगेशन के कुछ जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, वे प्रोजेक्ट्स सिर्फ चीनी मिल्स के लिए हो गए हैं, लेकिन इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स चीनी मिल्स को पानी नहीं देते हैं। इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से होता है। इनका इस्तेमाल या तो ड्रिंकिंग वॉटर के लिए करते हैं या अलग-अलग फसलों के लिए करते हैं। इसमें गन्ने की फसल भी है, यह बात सच है, मगर मुझे मालम नहीं कि देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने यह तय किया है कि इस देश में इसके बाद गन्ने की फसल नहीं लेनी है। गन्ने की फसल हम लेते हैं, तो इसमें एक इंप्रेशन यह है कि इसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। परन्तु महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में इसमें ज्यादा पानी लगता है, यह सच्चाई नहीं है। इस देश में कोयम्बटूर में एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका पूरा डिवोशन सिर्फ शुगरकेन के लिए है। उसने जो इन्फॉमेशन दी है, तो उसकी इन्फॉमेशन और उसकी रिसर्च यह बताती है कि ट्रॉपिकल एंड सब-ट्रॉपिकल एरिया में, जहां गन्ना उगाते हैं, साउथ के सभी क्षेत्रों में गन्ने के लिए कम से कम पानी का इस्तेमाल करके वहां एक किलो चीनी बनाने के लिए या एक किलो गन्ना बनाने के लिए कितना पानी लगता है। यानी पानी कम लगता है। इसलिए गन्ने के लिए पानी का इस्तेमाल कर दिया, यह कोई बहुत गलत काम किया, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मालूम नहीं, शायद सरकार की नीति बदली होगी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को यह लगता है कि इससे बड़ा नुकसान होगा, मुझे मालूम नहीं। कल उन्होंने लोक सभा के एक सदस्य को फोन किया या मैसेज भेजा। मैसेज कितने बजे भेजा? मुझे बड़ी खुशी है कि रात-दिन वे काम करते हैं। महिला सदस्य को 11 बजे मैसेज भेजा। बहुत अच्छी बात है। महिला के बारे में आप इतना सम्मान करते हैं तथा उनके बारे में इतना ध्यान देते हैं तथा 11 बजे उनको संदेशा देते हैं। उनको आपने संदेशा दिया कि "It is quite natural that you will not agree with me." इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि in the interest of sugar industry, not for farmers. शुगर इण्डस्ट्री जो गन्ना

[श्री शरद पवार]

लगाता है, मुझे मालूम नहीं कि टाटा, बिड़ला का गन्ना होता है, ऐसा मुझे लगता नहीं। तो किसान नहीं मरना चाहिए। फिर उन्होंने यह भी कहा ...**(व्यवधान)**...

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): 10.40 बजे कोई मैसेज देता है और 11 बजे जवाब में मैं मैसेज देता हूं, और माननीय सदस्य महिला हैं या पुरुष, सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि 10.40 बजे पर भी मैसेज आता है और 11 बजे हम जवाब में मैसेज देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बाकी जब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा, तो बताऊंगा।

श्री शरद पवार: मैसेज यह देते हैं कि ड्राउट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, ऐसी सिफारिश कर रहा हूं। जरूर करिए। ध्यान दे रहे हैं इस बारे में, जिसकी मुझे खुशी है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो पूरे देश का नक्शा आपके सामने रखने का मौका मिलेगा। महोदय, मुझे यह लगता है कि जब हम इस सदन में बैठते हैं तो इस सदन में कोई इस सूबे का है, कोई तालुके का है, कोई गांव का है, कोई जिले का है, हम पूरे देश के लिए यहां बैठे हैं। समझदारी से इन सभी इश्यूज के बारे में देखने की आवश्यकता है। मुझे मालम नहीं कि यह कहां तक देखा गया।

दूसरी बात है कि आज इसका सामना करने के लिए हर राज्य की ओर से कहा गया कि इसमें भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, राज्य सरकार भी इसमें कुछ न कुछ ध्यान देती है। 2015-16 के बारे में जितनी डिमांड राज्यों से आई, और इस डिमांड के बारे में भारत सरकार ने स्टडी करके जो डिसीजन दिया, वह देखने के बाद कुछ अच्छा काम किया है। मगर कई जगहों पर मुझे लगता है कि राज्यों की जो डिमांड है तथा एक्च्युअली उनको सहायता देने के लिए जो कदम उठाए, वे अधूरे थे। कर्णाटक ने 3,830 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी और उनको एक्च्युअली जो पैसा रिलीज़ किया गया वह 1,540 करोड़ रुपए था। छत्तीसगढ़ में 6,093 करोड़ रुपए की डिमांड थी और उनको रिलीज़ किया गया 8,35 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश में 4,881 करोड़ रुपए की मांग थी, मगर 1,875 करोड़ रुपए मिले। महाराष्ट्र ने 4,002 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन उनको 2,500 करोड़ रुपए मिले। इस तरह से चाहे ओडिशा हो, तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो या राजस्थान हो, सभी राज्यों की यह स्थिति है कि राज्य सरकारों ने एक डिमांड की है और इसमें एक्च्युअली यहां से जो राशि दी गई, वह उनको 50 परसेंट भी नहीं दी गई। मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इसे आप दीजिए और एक तरह से उनको डॉयरेक्शन दीजिए कि इस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, पशुधन बचाने के लिए करना चाहिए, और लोगों को हम कितनी ज्यादा रोज़ी दे सकते हैं, इसमें करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक लांग-टर्म पॉलिसी तैयार करके सूखे का सामना करना हम सब लोगों का फर्ज़ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि इस पर एक लांग-टर्म पॉलिसी तैयार करके और उस पर अमल करने के लिए कोई प्रस्ताव आएगा, तो इस सदन के सभी सदस्य भारत सरकार को पूरी तरह से सहयोग देगा। यहां राजनीति लाने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह संकट की स्थिति है, देश भर में यह संकट है, इसलिए हम सब लोगों को मिल कर इसका सामना करने की आवश्यकता है। यही कह कर मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Sharad Pawarji, for your valuable suggestions. Shrimati Rajani Patil.

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र)ः सर, सदन में अकाल और पानी के संकट के विषय पर चर्चा करवा कर एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हमने बात करनी चाही है। इस बार पूरे देश में बहुत ही अभूतपूर्व स्थिति का निर्माण हुआ है। इस देश की आधी आबादी यानी 50 परसेंट पॉपुलेशन सूखे से प्रभावित है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Rajaniji, sorry to interrupt you. Your party's time is 40 minutes. There are six speakers. So, take only seven minutes.

श्रीमती रजनी पाटिलः ठीक है। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। उन्होंने केंद्र के लगातार ढीले रवैए को लेकर सवाल उठाया है और यहां तक पूछा है कि सूखे की हालत को आप गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे? यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)** *पीठासीन हुए*]

सर, इस सदन में आए हुए मुझे तीन साल हुए हैं और इन तीन सालों में मुझे तीन-चार बार बोलने का मौका मिला। मुझे हर समय सूखाग्रस्त एरिया, किसानों की समस्या जैसे विषयों पर ही बात करने का मौका मिला। मैं राधा मोहन सिंह जी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगी कि यही सीन हमेशा होता है कि हम यहां से भाषण करते हैं, आप सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, फिर आप सवाल का जवाब देते हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह सीन कितने दिनों तक चलता रहेगा? आप इसमें कुछ बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे? यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।

सर, मैं उस अकाल पीड़ित और पेयजल से जूझने वाले एरिया से आती हूँ, जिसको 'मराठवाड़ा' कहा जाता है। आजकल हमने उसको 'मराठवाड़ा' बोलना छोड़ दिया है। अब हम उसको 'मराठवाड़ा' नहीं बोलते हैं, बल्कि हम उसको 'टैंकरवाड़ा' बोलते हैं। चूंकि मेरे क्षेत्र के हर गांव में टैंकर से ही पानी दिया जाता है, इसलिए 'मराठवाड़ा' को हम 'टैंकरवाड़ा' बोलते हैं। इस संकट के कारण वहां से हजारों लोग माइग्रेट हो रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। अभी जो एक महीने का अवकाश काल था, हमारी छुट्टियां थीं, उस दौरान मैं खुद अपने क्षेत्र में टूर के लिए बाहर निकली, तो मैंने वहां पर दो चीजों को देखा, जिनको मैं भूल नहीं सकती हूँ। हमारे अम्बेजोगई तालुका में एक गांव है, उस गांव में किसान प्रकाश जगताप नाम का एक आदमी रहता था, मैं उसके घर गई। यह चार दिन पहले की बात है। जब उसके घर गई, तो पता चला कि जगताप ने विष पान करके यानी जहर पीकर आत्महत्या कर ली है। जब मैं उसके घर गई, तो उसकी लड़की ने बताया कि मेरी शादी तय हुई थी और शादी में दो लाख रुपए का खर्चा होना था। दो लाख रुपए के लिए मेरे पिताजी सब जगह गए, लेकिन पैसे का कोई इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए बेइज्जती से बचने से उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर, 27 तारीख यानी आज ही उसकी शादी हो रही है। हम सबने मिल कर चन्दा इकट्ठा करके उस फैमिली को दे दिया और उनको कह दिया कि आज ही शादी हो जाएगी, हम उसकी शादी रुकने नहीं देंगे।

सर, दूसरी घटना मेरे खुद के गांव की है। बीड जिले के केज तालुका में मेरा गांव है, वहां वीडा करके एक गांव है। वहां पर एक दस साल का बच्चा कुएं से पानी लेने के लिए गया था, पानी लेते समय वह कुएं में गिर गया। उसके माता और पिता, दोनों ही शुगरकेन लेबरर्स हैं। जब हम ऐसी परिस्थिति देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है और हमें वह संवेदनशीलता इस सरकार में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। न राज्य में दिखाई देती है और न केंद्र में दिखाई देती है। दोनों जगह बुरी हालत है।

[श्रीमती रजनी पाटिल]

सर, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। अभी दो महीने में यानी जनवरी और फरवरी में सिर्फ महाराष्ट्र में ही 57 आत्महत्याएं हुई हैं, जबकि पूरे देश में कुल 116 आत्महत्याएं हुई हैं। आज के पेपर में ही ये आंकड़े आए हैं। वर्ष 2015 में पूरे देश में 2,997 आत्महत्याएँ हुई थीं, जिनमें से 1,841 आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में हुई थीं। वर्ष 2014 में 2,115 आत्महत्याएँ हुई थीं, जिनमें से 1,207 आत्महत्याएँ महाराष्ट्र में हुई थीं।

सर, हमारे राधा मोहन सिंह जी ने कल ही एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसका जिक्र अभी शरद पवार जी ने भी किया है। किसान होने के नाते उस बयान को देखकर हमें बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि खास तौर से महाराष्ट्र में जो पानी का दुर्भिक्ष है, उसकी जिम्मेदारी पिछली सरकार की है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जो शुगर फैक्ट्रीज़ सहकारिता के अंदर हैं, उनके ऊपर उन्होंने यह जिम्मेदारी डाल दी कि उन्हीं शुगर फैक्ट्रीज़ की वजह से गन्ने को ज्यादा पानी देना पड़ा है। सर, राजनीति में accountability बहुत जरूरी है। आपको सत्ता में आए दो साल हो गए, लेकिन आप अभी भी पिछली सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं। जब भी कोई सवाल उठता है, तो पहले वाली सरकार ने किया, पहले वाली सरकार ने किया, ऐसा आप कहते हैं। ऐसा कहकर आप अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते। अगर आपको को-ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ की स्टडी करनी है तो आप महाराष्ट्र में आइए। पवार साहब यहां बैठे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में हमारा महाराष्ट्र एक नम्बर पर जाना जाने वाला स्टेट था, यह मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि को-ऑपरेटिव और सहकारिता में महाराष्ट्र ने इतनी बड़ी प्रगति की है, लेकिन हर बात की दूसरे पर जिम्मेदारी डालना आप छोड़ दीजिए।

सर, जब अकाल का नाम आता है तो लातूर का नाम भी आता ही है। जब लातूर का नाम आता है तो जिस प्रकार एक समय में लातूर भूचाल के लिए बड़ा फेमस हुआ था, उसी तरह से अब जब हम यह कहते हैं कि हम लातूर के नजदीक से आए हैं, तो लोग पूछते हैं कि जहां 40-40 और 50-50 दिन तक पानी नहीं मिलता है, जहां रेल से पानी लाया जाता है, आप उस क्षेत्र से आए हैं? हम उसी लातूर के नजदीक के क्षेत्र से आते हैं। वहां पानी का जो प्रश्न है, वह चरम सीमा पर है। रेल मंत्री जी अभी मिरज से लातूर पीने का पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा अभी कहा गया कि राजनीति इतनी दूर-दराज तक गई है कि वहां जो पानी की पहली ट्रेन गई, उसके डिब्बे पर कमल के फूल और "भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद" लिखा था। मुझे कहना है कि जब आप गरीबों को पानी पिला रहे हैं, तो उसमें भी आप राजनीति कर रहे हैं, इससे बड़ी बुरी बात और क्या हो सकती है? वहां धारा 144 लगानी पड़ती है। अगर वहां ज्यादा लोग जमा हो गए, तो पुलिस जाकर उनको मना कर देती है, ताकि वहां पानी की वजह से कोई मारा-मारी न हो, कोई झगड़ा न हो। ...**(समय की घंटी)**...

सर, इससे निपटने के लिए मुझे एक ही उपाय नजर आता है कि डीसिल्टेशन होना बहुत आवश्यक है। हमारे तालूक में जो मांजरा प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत बड़ा सिल्टेशन हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर 40 परसेंट से ज्यादा पानी रुकता नहीं है, इसलिए वहां डीसिल्टेशन होना आवश्यक है। जब यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी, तब उसने डीसिल्टेशन के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये अलग रखे थे और उस पैसे को अभी निकालना जरूरी है। उसे नियमों में बाँधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जब वहां के कलैक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि पैसा

तो है, लेकिन उसे देने की जो प्रक्रिया है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएँगे। उसके लिए आपको नियम में थोड़ी ढील देकर मदद करनी पड़ेगी। वहां डीसिल्टेशन से दो चीज़ें होंगी। डीसिल्टेशन से निकली मिट्टी जब खेतों में जाएगी, तो वह इतनी अच्छी होगी कि उससे हमारे खेत सोना उगलेंगे। उससे 10-15 साल तक हमारे किसानों के लिए अच्छे दिन आएँगे। उससे पानी भी बढ़ेगा। अगर किसी तालाब या मीडियम प्रोजेक्ट में 40 प्रतिशत पानी भी बढ़ता है, तो इसका मतलब यह है कि एक नये तालाब का निर्माण हुआ है। इसलिए वहां डीसिल्टेशन करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा, जो नदियां और छोटे-छोटे नाले होते हैं, उनको deepen करने की आवश्यकता है। उसके लिए वहां काम शुरू हुआ है। हमारे यहां कुछ एनजीओज़ ने भी यह काम शुरू कर दिया है। मैंने वहां खुद जाकर श्रमदान में हाथ बँटाया है और अपने एमपीलैड्ज़ फंड से वहां पैसे दिए हैं। लेकिन यह सब करने के लिए सरकार को आगे आने की बहुत आवश्यकता है और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट का जो रुख है, वह मदद करने का नहीं, बल्कि सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का है।

सर, अब मैं दो मिनट में देश के संबंध में बात करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि 40 फीसदी लोग इस crucial समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने "महात्मा गांधी नरेगा योजना" को कमजोर करने की कोशिश की है, उसके पैसे को कम करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि "मनरेगा" में कवर किए गए 10 सूखा प्रभावित राज्यों में सिर्फ 1.8 फीसदी घरों को ही 150 दिन का काम मिला है। मुझे लगता है कि नरेगा के अंतर्गत काम देना आवश्यक है क्योंकि लोगों की मांग ज्यादा है, किन्तु लोगों को उसके तहत काम नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि नरेगा के तहत इसका तत्काल प्रबंध किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तत्काल सभी डिस्ट्रिक्ट्स में लागू करना चाहिए। इसी प्रकार यूपीए गवर्नमेंट ने मिड-डे मील योजना बनायी थी। उसके अंतर्गत बच्चों को खाना देना जरूरी है, जब स्कूल खुल जाएंगे तो मिड-डे मील के तहत उन्हें खाना देना चाहिए।

सर, मैं लास्ट में दो ही चीज़ें कहना चाहूंगी। बहुत ही परेशान होकर हम यहां आए हैं। जब एक महीने की छुट्टियां हुई थीं, तब सब किसान मुझे बोल रहे थे कि आप जब जाएंगी, राज्य सभा शुरू हो जाएगी, तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी बात वहां पर रखेंगी। इसलिए मैंने आज़ाद साहब से यह रिक्वेस्ट की कि मैं उस क्षेत्र से आती हूं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, worst affected area in the country is Beed. इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाऊंगी और हमारे लोगों की बात यहां पर बताऊंगी, लेकिन यहां आने के बाद मुझे यह महसूस होता है कि हम नीरो राजा की जो कहानी सुनते थे...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude now.

श्रीमती रजनी पाटिलः जब नीरो राजा का राज्य जलता था तो वह खुद violin बजाता रहता था। इसी प्रकार मोदी राजा बैठे हैं, जो violin बजाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी काम नहीं करते। ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि उन्हीं के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बताया था कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज किसान कह रहा है कि आज सही मायने में मोदी सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर राजधर्म का पालन करना चाहिए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं, जय हिन्द।

3.00 P.M.

श्री अजय संचेती (महाराष्ट्र): सर, आज एक बहुत गंभीर विषय पर, सूखे पर जो चर्चा हो रही है, सूखे की इस परिस्थिति से पूरे देश में एक संकट का वातावरण बना हुआ है। ज्यादा बारिश, सूखा, अकाल – इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये एक तरह से मानवता पर कहर बनकर टूट पड़ती हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ समय में excessive monsoon के कारण जो तकलीफ हुई, उन सबकी उस तकलीफ को हम लोगों ने देखा है, वहां के लोगों ने उसको झेला है। सर, पिछले तीन वर्षों से सूखे की स्थिति को पूरा देश, specially कुछ राज्य बहुत ज्यादा भुगत रहे हैं। कहीं बारिश बिल्कुल नहीं है तो कहीं बहुत थोड़ी है। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि कौन सी सरकार ने क्या किया। सूखा कोई पोलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, सूखा देश की समस्या है। जो भी सरकार है, उसने उस समय जो भी उचित समझा, वह किया और पूरी ताकत से अपनी सारी मशीनरी इस स्थिति से निपटने के लिए लगा दी। सर, सम्माननीय प्रधान मंत्री जी के डायरेक्शन पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वॉटर रिसोर्सेज़ मिनिस्टर सारी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जो-जो मुमकिन सहायता उपलब्ध करानी है, वह करायी जा रही है। सर, देश के कई हिस्सों में बहुत विचित्र स्थिति है। खेती तो दूर, पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या हो गयी है, जैसा अभी रजनी ताई ने बताया। हम दोनों महाराष्ट्र से आते हैं। रजनी ताई का गुस्सा एक अलग बात पर हो सकता है क्योंकि वे डायरेक्ट लातूर से आती हैं, उस स्थिति को उन्हें डायरेक्टली सुबह-शाम लातूर और बीड जिले में देखना पड़ता है। पवार साहब किसी भी पोलिटिकल पार्टी से हों, लेकिन जब वे कुछ भी कहते हैं, तो हर सदस्य गंभीर रूप से उनकी बात को सुनता है, उनकी हर बात को सलाह के रूप में लिया जाता है। महाराष्ट्र में लातूर में इतनी गंभीर स्थिति थी कि ट्रेन से पानी भेजना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि हम रेल मंत्री को बधाई देते हैं। सूखे से निपटने के लिए वहां जो पानी भेजा जा रहा है, उसके लिए बधाई देने के बजाय मैं समयबद्ध तरीके से immediate action लेने के लिए सरकार की, रेल मंत्री की तथा महाराष्ट्र की सरकार की बहुत सराहना करता हूं। सर, जरूरत में अगर सरकार काम आती है तो लोगों के लिए इससे बड़ा कोई और काम नहीं हो सकता। सर, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न क्यों होती हैं, यह देखना होगा। जब-जब भी मुझे मौका मिला, मैं इस सदन में पहली बार आया हूं, जब-जब भी, जितने समय के लिए मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने हमेशा एक बात कहने का प्रयास किया कि समस्या आने पर निपटना एक चीज़ है, लेकिन why is this happening, जब तक हम लोग इस चीज़ को address नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों के बोलने की और समस्याएं आने की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका long-term solution बहुत जरूरी है। इसकी ये main problems हैं और environment को protect करना, urbanization को रोकना, river linking कराना, ये इसके long-term solutions हैं। अगर ये चीजें रुकती हैं, तो फिर हम नेचर पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। कई मैन-मेड प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कारण भी सूखे और ज्यादा बारिश की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम कितना भी प्रयास करें, अगर इन चीजों को नहीं रोकेंगे, तो कोई भी सरकार हो, उसके प्रयत्न कम ही पड़ेंगे। देश के अनेक राज्य सूखे की स्थिति से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थिति बहुत ही भयावह है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मैंने वहां पर आंखों से देखा है, विदर्भ और मराठवाड़ा में देखा है। मैं विदर्भ से आता हूं, लेकिन मुझे मराठवाड़ा का नाम आज विदर्भ से पहले लेना पड़ेगा। उसकी स्थिति बहुत भयानक है। वहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर है। वहां पर पानी की एक बूंद न जमीन में

है, न कुएं में है, न खेतों में है। लोगों ने पक्षियों को उड़ते हुए नीचे गिरते देखा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या किया, उसके आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या-क्या प्रयास किए हैं, कितना पैसा भेजा है, क्या-क्या टाइमली सपोर्ट किया है, यह सब उनके उत्तर में आ जाएगा। उसको रिपीट करने की या उससे पहले कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, न पीने का पानी है, न सिंचाई के लिए पानी है, ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, यह गंभीर समस्या बनी हुई है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लोगों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए जो-जो व्यवस्था कर सकती है, उसे वह पूरी ताकत से कर रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, हॉर्वेस्टिंग ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायर्नमेंट आदि विषयों पर स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि ये प्रयास आज से हो रहे हैं या पहले से हो रहे हैं, लेकिन किस गति से हो रहे हैं, किस स्पीड से हो रहे हैं, यह ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस गवर्नमेंट ने इरिगेशन का बजट multifold बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि वे अपने मंत्रालय के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा राज्यों को सहायता प्रदान कर सकें, ताकि पानी स्टोर करने में मदद मिल सके। रिवर लिंकिंग का विषय कई वर्षों से पेंडिंग पड़ा था, उसको भी बहुत तेजी से मोमेंटम मिल चुका है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस साल वर्षा अच्छी हो। सारे प्रयास करने के बाद भी ईश्वर से प्रार्थना करना तो हम लोगों का काम ही है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अजय संचेती: पिछले तीन-चार सालों से देश सूखे की समस्या से परेशान है। मैं इस सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कृषि मंत्री, वॉटर रिसोर्सेस मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इन सब को एक साथ बैठाकर कहा है कि यह एक मिनिस्ट्री का काम नहीं है, नोडल मिनिस्ट्री एक हो सकती है। अगर हम लोगों को इसमें काम करना है, इस समस्या से निपटना है, तो environment मिनिस्ट्री सहित इन चारों मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करना होगा। नीरज भाई, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इन चारों मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ मिलकर काम करना होगा। यह मैं long-term solution के लिए कह रहा हूं। जो समस्या आती है, उससे हर सरकार निपटती आई है, आज भी सरकार निपट रही है, पूरी ताकत से निपट रही है, लेकिन long-term solution के लिए इन चारों-पांचों मिनिस्ट्रियों को एक साथ बैठकर काम करना होगा, तभी इस समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो सकेगा, जो हमारे हाथ में है। मैं ईश्वर की बात इसलिए करता हूं, पहले हम अपना काम कर लें, उसके बाद वह क्या करे, उसकी अपेक्षा करें। हमारी सरकार जो भी प्रयास कर रही है, उसके लिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि इस गंभीर विषय पर सरकार के प्रयासों की सराहना करके, उसका समर्थन करके, नैतिक रूप से हम सरकार के साथ हैं, ऐसा विश्वास लोगों को दिलाएं, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि इस समस्या में हम सब एक साथ हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): नरेश अग्रवाल जी, आपके बोलने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है।

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): मैं आपसे खुद कह देता हूं कि मैं आपको कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी के दो सदस्य बुंदेलखंड से हैं, उनको ज्यादा बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात थोड़ी ही देर कहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप सुन लीजिए। आपकी पार्टी को 9 मिनट का समय एलॉट किया गया है और आपकी पार्टी के तीन speakers हैं। हमने अपनी पार्टी का टाइम sacrifice कर दिया, अगर वह समय भी इसमें जोड़ दिया जाता है, फिर भी आपको पांच मिनट से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि हमें घंटी न बजानी पड़े।

श्री नरेश अग्रवाल: मैं इतना कह दूं कि अभी तक जितने वक्ता बोले हैं, सब टाइम लिमिट से आगे बोले हैं। यह सूखा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल: यह राष्ट्रीय मुद्दा है और हम इसको राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलिए, बोलिए। समय की पाबंदी है, इसलिए मैंने आपसे कहा है।

श्री नरेश अग्रवाल: माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय शरद पवार जी ने बहुत विस्तृत से चीजों को कहा है और शायद उनसे ज्यादा तजुर्बा हममें से किसी को नहीं होगा। यह सही है कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के करीब 22 राज्य सूखे से प्रभावित हुए हैं। आज जब युग इतना advance हो गया, हमको आज मालूम है कि अगले पांच साल तक बरसात कितनी होगी, किस साल बरसात होगी या नहीं होगी, तब यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में कोई भी long-term planning किसी चीज के लिए नहीं होती है। हम हर साल अखबारों में पढ़ लेते हैं कि देश के इस हिस्से में सूखा पड़ा, इस हिस्से में बाढ़ आई, राज्य सरकार ने केंद्र से सहायता मांगी, केंद्र की टीम सहायता के लिए सर्वे करने एक महीने बाद गई, एक महीने बाद रिपोर्ट भेजी और जब आपने मदद की तब तक सूखे का समय खत्म हो गया और बाढ़ का समय आ गया। यह ऐसा तरीका है, जो बहुत लम्बा है। हमें तो immediate राहत देनी है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित है। उत्तर प्रदेश के 50 जिले प्रभावित हैं। हमारे प्रदेश की दस करोड़ आबादी प्रभावित है। हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश में बहुत बयान देते हैं। उमा जी ने उत्तर प्रदेश में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कलराज जी भी बहुत तेजी से बयान दे आते हैं। वे कहते हैं कि साहब, हम उत्तर प्रदेश की मदद कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र से मांगती नहीं है। वर्ष 2014-15 में हमने आपसे सूखे के लिए 4,819 करोड़ रुपएं मांगे थे। आपने हमें सिर्फ 490 करोड़ रुपए ही दिए, बाकी रुपया आज तक रिलीज़ नहीं हुआ है। हमने 2015-16 में आपसे 2,057 करोड़ रुपए मांगे, आपने हमें सिर्फ 934 करोड़ रुपए दिए। बाकी रुपया अभी भी पेंडिंग है। आप कहते हैं कि हमारा NDRF का पैसा राज्य सरकारों के पास है, आप राज्य सरकारों से क्यों नहीं ले लेते? हमने NDRF से भी पैसा लिया, लेकिन उसके बाद भी कमी पड़ गई। हमने आपसे 2015 में ओला वृष्टि के लिए 7,543 करोड़ रुपया मांगा और आपने हमें 2,801 करोड़ रुपया दिया। हम सारे संसाधन

तो राज्य सरकार के ही इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनैतिक बयान तो खूब हो जाते हैं, कभी गृह मंत्री जी लखनऊ में बयान दे देते हैं, कभी कलराज जी कहीं बयान दे देते हैं। चलिए, बयान तो राजनैतिक होते हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है या नहीं है। आज सूखे से चार-पांच प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। जैसा कि शरद जी बोल रहे थे कि पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है, आज वॉटर लेवल कितना नीचे चला गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिले तो डार्क जोन जिले हो गए हैं, जहां पर बोरिंग करने के लिए मना कर दिया गया। अगर यह स्थिति है, तो जो कहा गया है विश्व में अगर महायुद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, तो यह सत्यता प्रतीत होती दिख रही है। हमारे पास खाद्यान हैं, लेकिन हम खाद्यान कहां पहुंचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के लिए तमाम चीजों को लागू किया है, जिसमें वहां 24 घंटे बिजली, 'मनरेगा' को 100 से बढ़ाकर डेढ़ सौ दिन कर दिया गया है, चावल 2 रुपए किलो और गेहूं 3 रुपए किलो दे रहे हैं। हम वहां पर चारे की व्यवस्था भी कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि मंत्री जी, इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाकर, जो कमियां हैं, उनको स्वीकार करिए। इसमें क्या दिक्कत है? हम भी मंत्री थे और हम सदन में स्वीकार कर लेते थे कि यह कमी है। जब तक पांच मिनिस्ट्रीज़ की नोडल मिनिस्ट्री नहीं बनेगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

आखिर हमें किसी चीज़ को तो स्वीकार करना चाहिए। हमने जो कमियां बताईं, हमारी जो कमियां हैं, उन्हें देखना होगा। खाली यह कहना कि नहीं साहब, केंद्र की कोई कमजोरी नहीं है, इसलिए कि कहीं प्रधान मंत्री जी हमसे नाराज न हो जाएं, उनकी नाराजगी हमारे लिए बहुत कठिन होगी, तो प्रधान मंत्री की नाराजगी को देखने की जरूरत नहीं है, देश की नाराजगी देखने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि आप यहां पर एक बड़ा दिल रखें। आप और हम उत्तर भारतीय हैं, पूर्ण रूप से राजनीतिक हैं, आप बिहार से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। आप यहां पर बड़ा दिल करके ऐसी घोषणा करें, ऐसी योजना बनाएं, कोई ऐसा संकल्प लें कि यदि हिन्दुस्तान के सामने ये सब चीज़ें आएं, तो हम इनसे निपटने में सक्षम हों और देश यह महसूस कर सके कि हम जो सरकारें चुनते हैं, वे हमारे हित में निर्णय लेती हैं। महोदय, मुझे बस इतना ही कहना है, धन्यवाद।

श्री शरद यादव (बिहार)ः उपसभाध्यक्ष जी, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपका वायदा था कि खेत से पानी जोड़ेंगे। यह जान लीजिए कि जहां खेत से पानी जुड़ा है, जोड़ा गया है, वहीं इस देश के सबसे अंतिम आदमी की ज़िंदगी बदली है। आप तो कृषि मंत्री हैं, आप देश भर में घूमते हैं, लेकिन जहां नहर है, जहां पानी का इंतज़ाम है, जहां पानी को खेत से जोड़ने का काम हुआ है या किसी भी तरह की अन्य चीज़ हुई है, वहीं देश बदला है। आपने यह वायदा किया है। अभी जिस तरह से आपने पानी पर बजट का आवंटन किया है, वह ऊंट के मुँह में जीरा है। एक बात, जो शरद पवार जी बोल रहे थे, वह बात छूट गई है, मैं कहना चाहता हूं कि हमने पानी का इंतजाम किया। एक जमाना अंग्रेजों का था, उन्होंने भी इंतजाम किया था एक जमाना हमारा था, हमने भी इंतजाम किया। जहां हमने पानी का इंतजाम किया, वहां सबसे पहली जरूरत थी कि उस बड़े बांध से पानी मिले। मेरी राय है कि चाहे छोटा बांध, बड़ा बांध हो — देश के हर हिस्से में लगभग 13 लाख कुएँ थे, इस देश में लगभग 9 लाख तालाब थे, लेकिन आज कुएँ सूख गए, तालाब सूख गए। ये सब हमने सुखाए। हम कुएँ का पानी ट्रेनों से ढोकर ले जा रहे हैं, तब कहीं पर डाल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सर, मैं आपसे

[श्री शरद यादव]

यह निवेदन करना चाहता हूं — क्योंकि मेरी पार्टी के एक और साथी बोलेंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने "नमामि गंगे" नाम देकर गंगा का नाम तक बदल दिया। यद्यपि आप मना करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गंगा को उसके भ्रूण में, जहां वह पैदा होती है, आप उसकी हत्या करने का काम कर रहे हैं। आने वाला कल और इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। उमा भारती जी, गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जिस तरह से आप और आपकी सरकार अदालतों में बार-बार उनको बदलने का काम कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ा संकट गंगा पर है। आज गंगा पर पचास करोड़ लोग ही आश्रित नहीं हैं, लगभग आधी आबादी है। ये 11 सूबे की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं कि आज देश में लगभग आधी आबादी की बात है। भूख से तो आदमी कुछ दिन, पांच दिन, दस दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। घंटे भर में, डेढ़ घंटे भर में और गरमी के दिनों में तो और जल्दी पानी चाहिए। इस सरकार ने कई तरह के नारे लगाए। मैंने आपसे फिर कहा कि आपका एक वायदा बहुत बड़ा वायदा है। हिन्दुस्तान की तक़दीर, हिन्दुस्तान की सब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन यह जो—"मेक इन इंडिया", "स्टार्ट-अप", "सिट डाउन" और "हेड डाउन" है, इससे देश नहीं बनेगा। देश बनेगा जब हिन्दुस्तान के गांव का जो खेत है, उसमें पानी ले जाएंगे। हिन्दुस्तान उसी दिन से बनना शुरू होगा, जिस दिन से आप पानी ले जाने का काम करेंगे। यह वेस्टर्न यू.पी. है। हमारे साथी के. सी. त्यागी जी वहां से हैं, वे अभी इस पर बोलेंगे कि कौन सी जगहें हैं। मैं जहां रहता हूं, वहां मैंने अपने बचपन में भूखे मरते लोग देखे हैं, लेकिन जैसे ही वहां पर तवा नदी पर एक डैम बन गया, वहां पर पंजाब से ज्यादा उपज हो रही है। हिन्दुस्तान के उत्तर भारत का क्षेत्र हो, चाहे दक्षिण भारत का क्षेत्र हो, जहां पानी चला गया, वहां हिन्दुस्तान का जो अंतिम आदमी है, जो सबसे ज्यादा लाचार और बेबस है, दिहाड़ी मजदूर है, यदि उस दिहाड़ी मजदूर की कहीं ज़िदगी बदली है, तो हरियाणा के खेत में बदली है।

जहां सिंचाई हुई है, वहां उसकी जिन्दगी बदली है। पंजाब में जिंदगी बदली है। जहां पानी गया है, वहां जिंदगी बदली है। मैं नहीं मानता कि हमारे पास दुनिया का चार फीसदी पानी है। हमारी जो नदियां हैं, हमने उनका गला घोंट दिया, नाला बना दिया। आपने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन 'नर्मदा बचाओ आन्दोलन' के जो लोग हैं, वे बिल्कुल सही हैं। मेरे जबलपुर में डैम बना है, कोसी के इलाके में डैम बना है। मैं हिन्दुस्तान के तीन सूबों से जीता हूँ और तीनों जगह नहर है। आपने बड़ा डैम बनाने के पहले जो उजड़ने वाले हैं, उनको बसाने का काम नहीं किया। उसमें आपका भी बहुत बड़ा दोष है। यह आपकी तरफ से भी हुआ है और इनकी तरफ से भी हो रहा है। यदि आप डैम बनाना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, मैं तो मानता हूँ कि किसी तरह का barrier नहीं होना चाहिए। तालाब हो, कुआँ हो, बावड़ी हो, चेकडैम हो, किसी तरह का भी काम हो, वह पानी किस तरह से preserve किया जाए और किस तरह से water level को maintain किया जाए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, पर यह तबाही और बरबादी के कगार पर चला जा रहा है। जमीन से इतना पानी निकल रहा है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में 'Make in India' बेकार है, जब आप पानी खेत में ले जाएँगे, तो हिन्दुस्तान जरूर बनेगा। आपने यह काम नहीं किया है, आप यह

काम करिए। आपने सिंचाई का जो वादा किया, वह वादा पूरा करिए। यह नदी अभी आपसे नहीं जुड़ने वाली है। कुआँ है, चेकडैम है, बावड़ी है, जिन तालाबों पर कब्जा हो गया है, आप डंडा मारिए। पानी आज Concurrent List में है। मैं आज इसीलिए बोलना चाहता था कि पानी, जो Concurrent List में है, आप इसके बारे में तत्काल इस सदन में तय करिए कि इसको Central List में आना चाहिए, नहीं तो देश की तबाही हो जाएगी, बरबादी हो जाएगी। मैं इसीलिए आज खड़ा होकर बोलना चाहता हूँ कि इसको Concurrent List में नहीं होना चाहिए। हमारे पुरखों ने गलत काम किया है। हमारे पुरखों ने ठीक काम नहीं किया। आज हर सूबे में लड़ाई हो रही है। हर सूबे का केस अदालत में फँसा हुआ है। यह लड़ाई चारों तरफ से जिस दिन ऐसे कगार पर पहुँचेगी, तो सूबे के लोग आपस में लड़ेंगे। इसलिए इस सदन में इस संकट के समय मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, मेरे साथी को इस विषय पर बोलना है, क्योंकि उन्होंने नोटिस दिया था। मुझे इस विषय पर बोलना था कि इसको Concurrent List से निकालिए। इस सदन के सारे लोग इस पर एक राय हैं, नहीं तो गृह युद्ध दुनिया में बाद में होगा, जो नरेश अग्रवाल जी ने कहा, हिन्दुस्तान में गृह युद्ध पहले हो जाएगा, यदि हमने इसको Concurrent List से निकाल कर Central List में नहीं डाला। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, मैं इसी बात के लिए खड़ा हुआ था। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती): उपसभाध्यक्ष जी, एक मिनट, I am on a point of clarification.

सर, मैं आपके माध्यम से सदन के अपने वरिष्ठ सदस्य, श्री शरद यादव जी से कहना चाहती हूँ कि वे मेरे लिए राजनीति के प्रेरणा बिंदु भी रहे हैं और गंगा, हिमालय, पर्यावरण के लिए जिन लोगों ने मेरे लिए गुरुतुल्य मार्गदर्शन किया है, उनमें से एक जयराम रमेश जी भी यहां पर विद्यमान हैं। मैं एक clarification देना चाहती हूँ कि मेरे मंत्रालय की तरफ से, जिसमें गंगा है, कोई भी इस प्रकार का affidavit कोर्ट में नहीं गया है। एक affidavit पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से गया, जिस पर हमारी तरफ से एक additional subject साथ में गया, जिसमें हमने स्पष्ट कहा है कि हिमालय में कोई भी नदी, जिस पर पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उस पर एक हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी जहां छोड़ा जाएगा, वहीं पर हम उसको सहमति देंगे, अन्यथा उसको सहमति नहीं मिलेगी। इस प्रकार से इसको सुनिश्चित किया गया है कि गंगा तो क्या, अन्य नदियों की भी भ्रूणहत्या वहां पर न हो।

दूसरा, माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी जानकारी यहां दे दी है कि पानी को Central List में लाया जाए। मैं डर रही थी और अपने मंत्रालय में इसकी समिति भी नहीं बना रही थी कि कहीं यह बात विवाद का विषय न बने। आज उनसे मुझे बहुत बड़ा संबल प्राप्त हो गया है और अब हम इस विषय पर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे।

श्री शरद यादव: सर, प्लीज, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): हम इस पर दूसरे दिन चर्चा करेंगे।

श्री शरद यादव: सर, मैं उनसे एक ही बात कह रहा हूँ।

[श्री शरद यादव]

उमा भारती जी, गंगा अकेले आपके हाथ में नहीं है। इसमें Environment Minister भी शामिल हैं। यह मान लीजिए, मेरे पास पक्की खबर है। हिमालय में कच्चा पहाड़ है। आप चाहे जिस तरह का barrier लगाइए, वहां डैम बनाना ठीक नहीं है। आप उत्तराखंड को भले compensate कर दीजिए, लेकिन हिमालय के कच्चे पहाड़ में जिन नदियों से गंगा बनती है, उनके ऊपर डैम नहीं बनना चाहिए, यह पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। यही एक रास्ता हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है।

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, आपने मुझे इस ज्वलंत विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही मैं अपनी नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, बहन कुमारी मायावती जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से किसान के बेटे को इस लायक बनाया कि आज मैं इस सदन में किसानों की समस्याओं पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हो सका हूं।

महोदय, आज भारत में 11 राज्य भीषण सूखे की समस्या से जूझ रहे है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्णाटक, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल को सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की स्थिति बहुत ही भयावह और दयनीय है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में विभाजित है। आज यह क्षेत्र पूर्ण रूप से सूखे की चपेट में है, जिसके कारण किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में वहां से पलायन कर रहे हैं। अपने परिवारों को बचाने के लिए अब तक वहां से लगभग 62 लाख मजदूर पलायन कर चुके हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए जो किया है, वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। मध्य प्रदेश के 5 जिले व उत्तर प्रदेश के झांसी संभाग के सभी जिले बुंदेलखड में आते हैं। 1.60 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के इस इलाके की आबादी लगभग 3 करोड़ से अधिक है। इस इलाके की 86 प्रतिशत आबादी खेती के सहारे ही जीवन-यापन करती है। बुंदेलखंड में आज जिस तरह के हालात हैं, वैसे इससे पहले कभी भी नहीं थे। यहां औसत वर्षा होती थी, जो उन लोगों की खेती के लिए पर्याप्त थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जिस तरह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई हुई है, उसने यहां के पर्यावरण को पूरी तरह नष्ट कर दिया है।

जल संरक्षण के उपायों के अभाव एवं जल संरक्षण के परम्परागत तरीकों के प्रति उदासीनता ने इस संकट को और बढ़ावा दिया है। कम बारिश होने के कारण बुंदेलखंड के कुएं, तालाब इत्यादि तो सूख ही गए हैं, फसलों के लिए जीवनदायिनी नदियों एवं बांधों में भी पानी की बेहद कमी है। सिंचाई के लिए पानी की कमी, जल का गिरता स्तर और सूखे की मार की वजह से बुंदेलखंड में कृषि संकट बढ़ता जा रहा है। किसानों की खेती बिगड़ने से उसके परिवार के अर्थशास्त्र पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लागत के अनुपात में फसल की उपज न के बराबर होने के कारण किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीते सालों में यहां के 3,223 किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

महोदय, देश के कई राज्यों में सूखे की भीषण स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाए और कहा कि जब कई राज्यों में सूखे के गंभीर हालात हैं, तो ऐसे में सरकार लोगों की दिक्कतों पर आंख मूंदकर

नहीं बैठ सकती है। इतना ही नहीं, सरकार की उदासीनता को देखते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर समस्या की अनदेखी नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बुंदेलखंड व मराठवाड़ा के हालात पर कड़ी चिंता जाहिर की है।

महोदय, बुंदेलखंड के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि में पानी को लेकर खून-खराबे तक की नौबत आ गई है। अभी रजनी जी बता रही थीं कि लातूर में पानी को लेकर जो हिंसक घटना हुई, उसे देखते हुए वहां धारा 144 लगानी पड़ी।

महोदय, मैंने अखबारों में एक बात पढ़ी है, हालांकि पूरी बात तो वहां के लोग ही जानते होंगे, रजनी जी भी महाराष्ट्र से ही हैं। मैंने पढ़ा है कि महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी की वजह से लोग एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं। जब एक पत्नी घर व बच्चों को संभालती है, तो दूसरी पत्नी सिर्फ पानी लाने का काम करती है, क्योंकि महिलाओं को कई मील पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): इन्हें बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजपाल सिंह सैनीः मान्यवर, विडम्बना देखिए, एक तरफ तो हमारे देश के अंदर कई राज्य सूखे के कारण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मुम्बई में आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर मैदान में लाखों लीटर पानी की बरबादी की गई है। मुम्बई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को आईपीएल मैच के आयोजन के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैच वहां करवाइए, जहां पर ज्यादा पानी है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे लिए सूखा ज्यादा बड़ी समस्या है या आईपीएल? मैं पूछना चाहता हूं कि लोगों को पीने के लिए, मवेशियों को खिलाने-पिलाने के लिए, खेतों को सींचने के लिए और बिजली घरों को चलाने के लिए पानी दिया जाना जरूरी है या आईपीएल के मैचों के लिए स्टेडियम तैयार किए जाने के लिए पानी देना ज्यादा जरूरी है? दरअसल आईपीएल इंडिया में, इंडियंस के मनोरंजन के लिए होता है, जबकि सूखा भारत में पड़ता है। इंडिया बड़े-बड़े स्मार्ट शहरों का देश बनने जा रहा है, जबकि भारत छोटे-छोटे गांवों का देश है। इंडिया विकास के इस छोर पर है, तो भारत दूर, बहुत दूर, उस छोर पर है। इसलिए देश का 40 प्रतिशत भू-भाग, 10 राज्य और 250 से अधिक जिले अगर सूखे की भयंकर चपेट में हैं और देश में इस पर कोई चिन्ता नहीं हो रही है, तो मान्यवर, हैरानी कैसी? ...**(समय की घंटी)**...

महोदय, अगर मौजूदा जल-संकट की बात करें, तो देश के 91 बड़े जलाशयों में कुल क्षमता का 29 प्रतिशत पानी है। देश में करीब 50 प्रतिशत ग्राउंड वॉटर प्रदूषित है। देश के 91 बड़े जलाशयों में पानी 10 साल के निचले स्तर पर पहुँच गया है।

महोदय, नयी सरकार से लोगों ने हालात सुधारने की उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन इस सरकार से भी कोई बदलाव नहीं आया है। अभी यहां हमारे दो मिनिस्टर्स, वॉटर रिसोर्सेज़ और कृषि मंत्री जी बैठे हैं। विचारणीय है कि जब सूखा हमारे देश में एक स्थायी त्रासदी बन गई है, तो क्या उसका स्थायी समाधान निकालना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में शामिल नहीं होना चाहिए? महोदय, अफसोस की बात है कि इस दिशा में सरकारी प्रयास महज 'पानी की बूँद-बूँद कीमती है', 'जल ही जीवन है', 'जल है, तो कल है', जैसे नारे दीवारों पर लिखने या अखबारों में छपवाने तक सीमित रह गए हैं, जबकि सूखे से निपटने के लिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल प्रबंधन की भी समग्र रणनीति बनाकर उस पर सख्ती से अमल करने की आवश्यकता है।

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

महोदय, बुन्देलखंड के मौजूदा हालात को देखते हुए सबसे पहले वहां ग्राम और कृषि आधारित आजीविका की आवश्यकता है, ताकि पलायन को तुरन्त रोका जा सके। सरकार को बुन्देलखंड के लिए अलग से ऐसी कृषि नीति घोषित करनी चाहिए, जो इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को नुकसान न पहुँचाए। जो भी नीति बने, उससे पशुपालन और वानिकी के साथ जोड़ा जाए। सरकार राष्ट्रीय बैंकों को सिंचाई के परम्परागत साधनों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दे।

अंत में महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि बुन्देलखंड व अन्य राज्यों को सूखे से उबारने के लिए जरूरी है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): ठीक है।

श्री राजपाल सिंह सैनी: और भू-जल संकट का समाधान किस प्रकार हो सकता है, समय रहते इस पर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए। आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): श्री तपन कुमार सेन।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...**(व्यवधान)**... माननीय राजपाल सिंह सैनी जी ने अभी अपनी बात रखते वक्त कहा कि ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Under which Rule?

श्री हुसैन दलवई: सर, रूल तो ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप रूल बताइए। ...**(व्यवधान)**... आप रूल बताइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: सर, यह बिल्कुल गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: यह मराठवाड़ा के लोगों की बेइज्जती है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप प्लीज़ बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: इसलिए उसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दीजिए। ...**(व्यवधान)**... यह मराठवाड़ा के लोगों की बेइज्जती है। ...**(व्यवधान)**... सर, यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री राजपाल सिंह सैनी: सर, मैंने जो कहा है, वह अखबार में छपा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: वह अखबार में छपा है, इसलिए आप यहां कहेंगे? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप मेरी बात सुनिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप भी बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री हुसैन दलवई: यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ...**(व्यवधान)**... बिल्कुल गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजपाल सिंह सैनीः वह अखबार में छपा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): राजपाल जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... ठीक है, ठीक है। ...**(व्यवधान)**... हम रिकॉर्ड वेरिफाई करेंगे। अगर कुछ भी ...**(व्यवधान)**... राजपाल जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... राजपाल जी, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... अगर किसी ने कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। श्री तपन कुमार सेन।

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. I will try to restrict myself within the time available to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Your time is only five minutes.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, I will try to restrict myself within that. But, at the same time, I seek your indulgence. This is number one. Number two, I think, a number of speakers have already spoken that the country has fallen into a very deep crisis due to drought. I think, it need not be further explained. So many data, etc., have been quoted, and it is also very clear by the very fact that 33 crores of people are affected in more than eleven States covering more than 300 districts. The figure, by itself, is quite alarming, though by Nature's cruelty, such a situation has taken place, particularly, in our agrarian areas. But the fact remains that it is not just the Nature's cruelty. It is the Nature's cruelty plus successive *ad hocism* by the successive Governments in addressing the recurrence of Nature's cruelty in a cyclical manner, sometimes drought, sometimes flood. That is going on, and if you kindly consider, if you really go through our agrarian economy, so far as the State of the people depending on the agriculture is concerned, depending on the rural occupations is concerned, they are in real distress, at least, since more than a decade. Almost every year in this House we have discussed this question of agrarian distress a number of times for this reason or that reason.

This time, the drought has also brought forth a grim reality. Firstly, instead of going into details such as the real impact of the drought, which the previous speakers have spoken about, actually the situation demands immediate action. The first step is immediate relief and the next is a long-term approach in addressing the issue at the root. Now, what could be an immediate relief measure? Nareshji rightly said that by the time this Committee studies the situation and sends its Report, rains would come. That has been happening through successive years! That approach must go. Let me tell you, at this time when people are losing not just their lands but also their crops, if we consider that population which is losing its crops alone to be affected by drought, it will be wrong because a bigger number is dependent on land as agricultural labour. Also, the entire rural economy depends on various

[Shri Tapan Kumar Sen]

occupations. When drought kills the crops, the whole rural society is affected. People flock to the towns for work and join the vast army of the unemployed. This makes the condition of informal labour in the urban areas acute too. So, there is a very wide social impact, which is not just limited to agriculturists alone. When they think about relief, I urge upon the Government, do take into account the problem in its entirety. One of the important and immediate instruments available is the utilization of MNREGA. But, Sir, what is the state of affairs right now? I had the occasion to personally visit some of the districts in the State of Maharashtra which are very badly affected. One such district is Beed. There, the Collector and the *Kisan* Organizations told us that the MNREGA workdays had increased to 55,000 from 10,000. But, what is the reality? We had the occasion to meet some of the villagers. They said, no work is available. In some of the villages where work is available, wages have not been paid for more than two months. Is that the approach to providing relief? Does it carry any relief to them? This is the reality.

When you are talking in terms of relief, this is the reality. And this is creating a serious crisis even in the availability of drinking water, particularly in those areas. This has even extended to some of the urban areas. Some days back, I had the occasion to meet the concerned authority in SAIL. The Rourkela Steel Plant township is completely dried up because the Koel river water, which supplies water to that steel township, has completely dried up. The dam is not operational and the township is suffering. I am not just talking about the rural areas. This crisis has extended to towns as well. So, you must go to the root in all these areas and address the issues. The reality is that most of the dams in the drought-affected areas, wherever they are, at this moment, are operating at three per cent of their capacity. Of the total storage capacity, just three per cent water is there in most of the dams in the drought-affected areas. So, in these areas, some immediate arrangement must be made to give them employment, keeping in view not only the agriculturists but the entire population, the entire society, affected by that as well. An aggressive programme of MNREGA and also supply of water must be taken up on a war-footing. At least, the availability of drinking water must be taken care of urgently. Secondly, in terms of long-term projects, we are suffering from extreme *ad hocism*. It was shocking when Shri Sharad Pawar said that more than 240 irrigation projects were lying incomplete for two-and-a-half decades. At the top level, we decide about irrigation projects with a long-term approach.

But when it goes down, which contractor is playing where is not known. Some of the contractors are also here in this House. Who is playing in what line and how market forces are playing in between? How could it happen that irrigation projects

which were conceived are lying incomplete for two-and-a-half decades? Does this discussion in this House make any sense? Who are involved? We all are involved in the system, from top to bottom. Who will address this? At least, we will urge the Government, better late than never, to address the issue seriously. Only sound bite cannot help unless these basic issues are addressed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Rush in immediate relief and also seriously address the question of these issues. It is a recurrent natural crisis such as flood and drought which is creating a crisis in our economy. Address this at the root through proper scientifically-conceived projects and lead them to their completion within a time-frame. On these, I think, we have to work on a war footing simultaneously. I may urge the Government to rush immediate relief, respond to the needs and the urgent demands made by different State Governments. Respond in a positive manner. Instead of calculating on Finance Commission's recommendation, please rush. And also let us collectively try to address this issue on a long-term basis. Fix the responsibility for the projects which are lying incomplete for more than two-and-a-half decades. This is an unpardonable offence. And, I think, this House must collectively address this issue. Thank you.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Sir, thank you for permitting me to speak on this grave humanitarian crisis that is affecting over 33 crore Indians in over 13 States, almost one-quarter of our population. Sir, I have been in Parliament for ten years now and I have heard almost every year a discussion discussing the drought condition and the serious sufferings of our farmers in rural communities around the country. With great respect, I say, Sir, that I have heard very similar speeches being made every year and I have referred to many years of speeches on drought and it is not unsurprising that again this year we are making points that have been made many many times over the last several years. I say this with all seriousness, Sir, that it seems to me that we are all sitting and being mute spectators to this annual spectacle and annual tragedy that is playing out every year. We believe that we have three seasons, that is, summer, monsoon, and winter. But most of India sees this as summer, drought, monsoon and winter. And I say this as somebody who is not an expert in the subject, but I believe that it is my responsibility to speak. I think, Sir, we must move beyond the rhetoric and the politics of drought. There is an interesting book, as I was going through the research, that says 'Everybody loves a good drought'. I think, Sir, we must move beyond the governance of politics to governance of solutions. And, Sir, it is in that

[Shri Rajeev Chandrasekhar]
context I will make two broad points. One is that we must address the current crisis and we must address this proactively and completely. And the second point, and I think some of my colleagues have alluded to this, is that we must develop a long-term strategy and a medium-term strategy to the issue of water to ensure, at some point, that we don't sit around and remain mute spectators to the sufferings year on year. So, one is an immediate short-term plan and the second is a medium to long-term strategy to address this with solutions.

Sir, I come from Karnataka and I would like to draw the attention of the House, as part of my point number one, to the crisis unfolding in my State as well. Districts of North Karnataka, Kalaburagi, Yadgir, Belgaum Bidar, Raichur, Vijayapura, Bagalkot and Uttara Kannada are amongst districts that are reeling under harsh drought conditions. In Uttara Kannada alone, Sir, 197 villages are facing water scarcity. Staples including major crop paddy have been damaged due to scarcity of water. More importantly, people are selling the cattle and property at throw away prices and are migrating.

The farmers are leaving homes for long periods and are not returning even at the risk of losing the farm land, and these have very medium-term cascading effects on the overall economy of the region and to the problem in terms of going forward. Sir, the drought and water situation has only worsened in Karnataka in the last eight weeks after the Central Team survey and I would make a request to the Government to consider immediate financial assistance of providing water and fodder to the drought-hit districts not only in my State but in all 13 affected States.

Sir, I will just briefly touch upon the issue of medium to long-term strategy. I think the Government must address this and we must create a national water strategy or a national water management strategy. A comprehensive strategy for improved management of drought in India should be our priority. While train loads of water could be immediate relief, better investment in rural infrastructure, a Central water management policy, focus on climate change and extensive use of technology — now, with satellite imaging and other technological tools, we can predict drought, we can plan for this in advance — innovative water conservation methods such as those adopted in Israel like desalination of sea water for coastal areas should be studied and implemented to meet such crisis in future.

I will just end by urging upon the Centre to look upon the current crisis as a national calamity, create a special task force to initiate urgent and viable steps which can be enforced in collaboration with the State Governments to support an anguished one-fourth of India that looks to the rest of us in this time of need. Thank you, Sir. Jai Hind.

श्री मोहम्मद अली खान (आंध्र प्रदेश)ः महोदय, आज आपने मुझे हिन्दुस्तान के अंदर जो क़ेहेत का मामला है, उस पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की सदर मोहतरमा सोनिया जी को और अपने लीडर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। शायद आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब हिन्दुस्तान के अंदर इतना भयानक क़ेहेत आया। मैं जिस तेलंगाना रियासत से ताल्लुक रखता हूँ, वहां पर भी तकरीबन 450 मंडलों में से 370 मंडल क़ेहेत से भयानक रूप से मुतास्सिर हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि रियासती सरकार ने इस क़ेहेत से निपटने के लिए मरकज़ से जो इमदाद मांगी थी, उसके जवाब में मरकज़ ने रियासती सरकार को मदद देने में कोताही की। मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का रुक्न हूँ, हमने अवाम की खिदमत के लिए कभी भी सियासी दावँ-पेंच का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे वह यूपीए सरकार हो या किसी भी सरकार में हमने काम किया हो, लेकिन जब अवाम की मदद की जरूरत आई, तो हमने सियासत से बालातर होकर हर सियासी जमात की रियासतों को मदद की। लेकिन आज देश में जो हालात हैं, वह मुझे यह बोलने को मजबूर करते हैं कि मरकज़ी सरकार सिर्फ कागज़ों तक ही अपने बजट को मख़सूस रखती है। अवाम की मजबूरी को देखते हुए और आज जो क़ेहेत का हाल है, उसको देखते हुए ग्रांट की मंजूरी के लिए यह प्लान बनाती है। आपने जो प्लान बनाया, मुझे उसमें कोई शक नहीं है। आपने अपना प्लान बनाया होगा, लेकिन मैं एक दफा वज़ीर-ए-मौसूफे-ज़रात से जानने की कोशिश करूँगा कि आप यह देखिए कि हिन्दुस्तान के अंदर क़ेहेत से मुताल्लिक जितने स्टेट्स हैं, उनको आपने जिस चीज़ की मदद की है, वह गरीब अवाम जो सफेगुर्बत से नीचे हैं, क्या उन तक वह मदद पहुँची है? अगर उन तक वह मदद पहुँचती तो आज चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो या इस मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, वह आज जिस हालत में क़ेहेत से मुतास्सिर है, उस अवाम को किसी तरह की भी मदद पहुँचने की उम्मीद नहीं हो रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे अपील करूँगा कि अभी भी मौका है। आज किसान बेहाल हो रहा है और वह सुइसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है। आज किसान मजबूरी से आपकी तरफ देख रहा है। मैं अभी इक्तिदार पार्टी के एक रुक्न को बात करते हुए सुन रहा था। जब यह सरकार इक्तिदार में आई थी, तो अवाम से कहती थी कि हम आपके वायदे और फलाहो बहबूद के लिए काम करेंगे।

लेकिन अभी मैं ट्रेज़री बेंचेज़ से एक रुक्न-मौसूफ को बात करते सुन रहा था। जब अवाम की मदद की बात आयी तो आप खुदा को याद करके खुदा से मांगने की बात कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं, मैं भी खुदा को मानने वाला हूं, खुदा भी यह कहता है कि मुझे मानने से काम नहीं होगा, आपको अपनी मेहनत से काम करके, दो कदम आगे बढ़कर अवाम की खिदमत करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरकज़ी सरकार ने जो स्कीम बनायी है, आज हालत बहुत बुरी है। तेलंगाना के अंदर रियासती सरकार जो मुतालबा कर रही है, मैं चाहता हूं कि Telangana, हर रियासत को आपने केहेत से निपटने के लिए जो प्रोग्राम दिया है, आप दिल खोलकर उन्हें पैसा दीजिए और देखिए कि अवाम की खिदमत के लिए आप कहां तक जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज सिर्फ अखबार के बयानों की हद तक, पेपर की हद तक एनडीए सरकार महदूद होकर रह गयी है। चूंकि मैं एग्रीकल्चर कमेटी में हूं, मुझे किसानों से मिलने का मौका मिलता है, मैं उनसे भी

[श्री मोहम्मद अली खान]

मिलते रहता हूं। किसानों के पास ज़मीन के साथ जो alternative होता है, उसकी जानवर को पालने की भी जिम्मेदारी होती है। इस देश का किसान अपने बीवी-बच्चों को जिस क़दर, जिस इज़्ज़त से, जिस नफ्स के साथ, इज़्ज़त के साथ पालता है, अपने जानवर को भी उसी हिफाज़त के साथ रखता है, लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर उसकी एक बदकिस्मती है। मैं खुदा से दुआ करता हूं, जुस्तजू करता हूं और मेरी पार्टी ऐहद करेगी कि इस अवाम की खिदमत को पार लगाने के लिए, इस मुसीबत से बाहर आएं। दुआ से काम नहीं होता है। दुआ के साथ-साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। दुआ के साथ सच्चे दिल से आपको गरीबों की मदद करने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। जब वोट मांगने का वक्त आया था तो आपने अवाम से वोट मांगा, लेकिन जब अवाम को मदद की जरूरत पड़ी तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप खुदा और भगवान को याद करने की बात करते हैं। यह बात अच्छी नहीं है। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, अपने आपको तेलंगाना की हद तक महदूद करते हुए आपसे एक बात की अपील करना चाहता हूं कि तेलंगाना के अंदर चाहे करीम नगर हो, चाहे महबूब नगर हो, चाहे वरंगल हो, चाहे निज़ामाबाद हो, चाहे हैदराबाद सिटी हो – हैदराबाद में भी पीने के पानी का बहुत क़ेहेत है, आदिलबाद में भी बहुत क़ेहेत है। वहां पर जानवरों का बुरा हाल है। किसान के घर में जब एक मय्यत होती है, उस समय वह जितना रोता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, उसके घर में अगर एक जानवर भी मरता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी की आमदनी खत्म हो जाती है। प्रधान मंत्री ने बीमा योजना का एलान किया। मैं सरकार से अपील करता हूं कि बीमा योजना को आप इस तरीके से करने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरह से यूपीए गवर्नमेंट में डा. मनमोहन सिंह जी ने अपनी वज़ारत के अंदर एलान किया था कि किसानों के लोन को हम माफ करेंगे, आज हिन्दुस्तान में यह समय है, किसानों का लोन माफ करने का। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप खुदा को, भगवान को देखने की बात अवाम से मत कीजिए। आप खुद आगे आइए, प्रधान मंत्री जी को आगे आना चाहिए, इस सरकार को आगे आना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी आपसे अपील है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आपसे मदद की अपील की थी, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप सियासी इक़दार से आगे हटकर — चाहे किसी जमात का आदमी हो, जमात को नहीं, सियासत को नहीं, पार्टी को नहीं, इंसानियत को देखते हुए मदद करेंगे, तभी आप मुल्क की खिदमत के लिए आगे आ पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

†جناب محمد علی خان (تلنگانہ) : مہودے، آج آپ نے مجھے ہندوستان کے اندر جو قحط کا معاملہ ہے، اس پر بولنے کا موقع دیا ہے، اس کے لئے میں اپنی پارٹی کی صدر محترمہ سونیا جی کو اور اپنے لیڈر کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں۔ شاید آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان کے اندر اتنا بھیانک قحط آیا۔ میں جس تلنگانہ ریاست سے تعلّق رکھتا ہوں، وہاں پر بھی تقریبا 450 منڈلوں میں سے

† Transliteration in Urdu script.

370 منڈل، قحط سے بھیانک روپ سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ریاستی سرکار نے اس قحط سے نپٹنے کے لئے مرکز سے جو امداد مانگی تھی، اس کے جواب میں مرکز نے ریاستی سرکار کو مدد دینے میں کوتاہی کی۔ میں یہی امید کرسکتا ہوں کہ میں سیاسی وابستگی سے بالاتر ہوکر، کیوں کہ میں کانگریس پارٹی کا رکن ہوں، ہم نے عوام کی خدمت کے لئے کبھی بھی سیاسی داؤ-پیچ کا استعمال نہیں کیا۔ چاہے وہ یو.پی.اے. سرکار ہو یا کسی بھی سرکار میں ہم نے کام کیا ہو، لیکن جب عوام کی مدد کی ضرورت آئی، تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کر ہر سیاسی جماعت کی ریاستوں کو مدد دی۔ لیکن آج دیش میں جو حالات ہیں، وہ مجھے یہ بولنے کو مجبور کرتے ہیں کہ مرکزی سرکار صرف کاغذوں تک ہی اپنے بجٹ کو مخصوص رکھتی ہے۔ عوام کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور آج جو قحط کا حال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے گرانٹ کی منظوری کے لئے یہ پلان بناتی ہے۔ آپ نے جو پلان بنایا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے اپنا پلان بنایا ہوگا، لیکن میں ایک دفعہ وزیر موصوف زراعت سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہندوستان کے اندر قحط سے متعلّق جتنے اسٹیٹس ہیں، ان کو آپ نے جس چیز کی مدد کی ہے، وہ غریب عوام، جو صف غربت سے نیچے ہیں، کیا ان تک وہ مدد پہنچی ہے؟ اگر ان تک وہ مدد پہنچتی تو آج چاہے مہاراشٹر ہو، تلنگانہ ہو یا اس ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، وہ آج جس حالت میں قحط سے متاثر ہے، اس عوام کو کسی طرح کی بھی مدد پہنچنے کی امید نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آپ سے اپیل کروں گا کہ ابھی بھی موقع ہے۔ آج کسان بےحال ہو رہا ہے اور وہ سوسائڈ کرنے کے لئے مجبور ہو رہا ہے۔ آج کسان مجبوری سے آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں ابھی اقتدار پارٹی کے ایک رکن کو بات کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ جب یہ سرکار

اقتدار میں آئی تھی، تو عوام سے کہتی تھی کہ ہم آپ کے وعدے اور فلاح و بہبود کے لئے کام کریں گے۔

لیکن ابھی میں ٹریزری بنچوں سے ایک رکن موصوف کو بات کرتے سن رہا تھا۔ جب عوام کی مدد کی بات آئی تو آپ خدا کو یاد کرکے خدا سے مانگنے کی بات کررہے ہیں، بھگوان کو یاد کررہے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، میں بھی خدا کو ماننے والا ہوں، خدا بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے ماننے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو اپنی محنت سے کام کرکے، دو قدم آگے بڑھکر عوام کی خدمت کرنے کے لیے آگے آنا پڑے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مرکزی سرکار نے جو اسکیم بنائی ہے، آج حالت بہت بری ہے۔ تلنگانہ کے اندر ریاستی سرکار جو مطالبہ کررہی ہے، میں چاہتا ہوں، کہ ناٹ تلنگانہ، ہر ریاست کو آپ نے قحط سے نپٹنے کے لیے جو پروگرام دیا ہے، آپ دل کھولکر انہیں پیسہ دیجئیے اور دیکھیئے کہ عوام کی خدمت کے لیے آپ کہاں تک جاسکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہورہا ہے۔ آج صرف اخبار کے بیانوں کی حد تک، پیپر کی حد تک این ڈی اے سرکار محدود ہوکر رہ گئی ہے۔ چونکہ میں ایگریکلچر کمیٹی میں ہوں، مجھے کسانوں سے ملنے کا تجربہ ہے، میں ان سے بھی مل رہا ہوں، کسانوں کے پاس زمین کے ساتھ جو متبادل ہوتا ہے، اس کی جانور کو پالنے کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس دیش کا کسان اپنے بیوی بچوں کو جس قدر، جس عزت سے، جس نفس کے ساتھ، عزت کے ساتھ پالتا ہے، اپنے جانور کو بھی اسی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن ہندستان کے اندر اس کی ایک بدقسمتی ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں، جستجو کرتا ہوں اور میری پارٹی عہد کریگی کہ اس عوامی خدمت کو پار لگانے کے لیے، اس مصیبت سے باہر آئیں۔ دعا سے کام نہیں ہوتا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دعا کے ساتھ سچے دل سے آپ کو غریبوں کی مدد کرنے

کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے۔ جب ووٹ مانگنے کا وقت آیا تھا تو آپ نے عوام سے ووٹ مانگا، لیکن جب عوام کو مدد کی ضرورت پڑی تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ خدا اور بھگوان کو یاد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی نہیں ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو تلنگانہ کی حد تک محدود کرتے ہوئے آپ سے ایک بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ کے اندر چاہے کریم نگر ہو، چاہے محبوب نگر ہو، چاہے وارنگال ہو، چاہے نظام باغ ہو، چاہے حیدرآباد سٹی ہو۔ حیدرآباد میں بھی پینے کے پانی کا بہت قحط ہونے والا ہے، عادل آباد میں بھی بہت قحط ہونے والا ہے۔ وہاں پر جانوروں کا برا حال ہے۔ کسان کے گھر میں جب ایک میّت ہوتی ہے، اس وقت وہ جتنا روتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اس کے گھر میں اگر ایک جانور بھی مرتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی آمدنی ختم ہوجاتی ہے۔ پردھان منتری نے بیما یوجنا کا اعلان کیا۔ میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ بیمہ یوجنا کو آپ اس طریقے سے کرنے کی کوشش مت کیجئیے۔ جس طرح سے یوپی اے گورنمنٹ میں ڈاکٹر منموہن سنگھ جی نے اپنی وزارت کے اندر اعلان کیا تھا کہ کسانوں کے لون کو ہم معاف کریں گے۔ آج ہندستان میں یہ وقت ہے، کسانوں کا لون معاف کرنے کا۔ میں آپ سے اپیل کرونگا کہ آپ خدا کو، بھگوان کو دیکھنے کی بات عوام سے مت کیجئے۔ آپ خود آگے آئیے۔ پردھان منتری جی کو آگے آنا چاہئے، اس سرکار کو آگے آنا چاہئے اور ان کی مدد کرنی چاہئے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ تلنگانہ کے مکھیہ منتری نے آپ سے مدد کی اپیل کی تھی، مجھے ایسی مید ہے کہ آپ سیاسی اقدار سے آگے ہٹ کر - چاہے کسی جماعت کا آدمی ہو، جماعت کو نہیں، سیاست کو نہیں، پارٹی کو نہیں، انسانیت کو دیکھتے ہوئے مدد کریں گے، تبھی آپ ملک کی خدمت کے لئے آگے آ پائیں گے۔ آپ نے مجھے وقت دیا، اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں، جے ہند، جے بھارت۔

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): माननीय उपसभापति जी, आज अकाल और पानी का अभाव विषय पर चर्चा हो रही है। मैं दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अकाल और पानी के अभाव के साथ-साथ जैसे अधिक धूप से ओडिशा और उसके आसपास के इलाके में अभी तक लगभग 100 के करीब लोग मर गए हैं, मुझे डर लगता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत में आने वाले मई और जून माह में कई राज्यों में बहुत गंभीर स्थिति आ सकती है और मरने वालों की संख्या हजारों तक जा सकती है। इसको रोकने के लिए सार्वजनिक रूप से लोगों में जागृति लाने की दृष्टि से क्या करना चाहिए, इसके बारे में सरकार और थोड़ा सीरियसली सोचे। अभी तो लोगों की राहत के लिए सरकार मदद कर रही है, उसके साथ-साथ आने वाले महीने में लू की गर्मी के कारण जब लोग मरते हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इसके बारे में सीरियसली सरकार सोचे, यह मेरी विनती है।

साथ ही साथ जितने भी काम चल रहे हैं, लेकिन for the time being जितनी पानी की आवश्यकता है, सरकार उसकी पूर्ति करने का काम करे और जानवरों को चारा देने का काम करे। जो बात चर्चा में आई है, वह यह है कि इस प्रकार के संकट को दूर करने के लिए एक combined effort होना चाहिए, जैसा कि आदरणीय शरद यादव जी ने कहा कि इसको Concurrent List से बाहर लेकर आइए। अगर नहीं, तो पानी के लिए सारे राज्यों के बीच में झगड़ा होगा। जैसे माधायी का पानी गोवा से समुद्र में चला जाता है, बाजू में कर्णाटक से पानी लेने में हम असफल हैं, वैसे ही सहयाद्री घाट से लगभग दो हजार क्यूसिक वॉटर बड़ी मात्रा में समुद्र में चला जाता है, उसको रोकने की कोई नई खोज हम नहीं कर पाते हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले इनलैंड वॉटर बिल को पास किया है, जिसमें नितिन जयराम गडकरी जी ने भारत की नदियों को जहाजी मार्ग से जोड़कर पानी की सतह को बढ़ाने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि जल संसाधन मंत्री और कृषि मंत्री साथ मिलकर उसको और गति देंगे, तो भारत के अंदर हम पानी का स्तर बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए और पानी का स्तर ऊंचा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

हमारे देश में और भी समस्याएं हैं। हमारा समाज कुछ गलत रास्ते पर जा रहा है। एक तरफ लातूर में पीने के लिए पानी नहीं है, ऐसा कहते हैं। मैं उस लातूर जिले में होकर आया हूं। उसी लातूर के अंदर राजशेखर पाटिल नाम का एक व्यक्ति है। उसने अपने पुरुषार्थ से, अपनी 10 एकड़ जमीन के अंदर हरियाली पैदा की हुई है। उसने काफी पानी इकट्ठा करके रखा है। मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है? मैं उसी लातूर से प्रेरणा पाकर आया हूं कि कम से कम अगर 100 मिलीलीटर पानी भी होता है, तो एक एकड़ जमीन के अंदर दो करोड़ लीटर पानी पड़ता है, अगर उसमें हम 50 लाख लीटर पानी भी बचा सकेंगे, तो अलग-अलग प्रकार के खेती के माध्यम से, कॉटन क्रॉप के माध्यम से कम से कम किसान इज्जत से जी सकता है। ऐसी कोई लम्बी सोच नहीं है। टाइम आया, तो बोरवैल मारो और कुछ करो, उधर से लाओ, ऐसे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बन रहे हैं। जैसा कि शरद यादव जी ने कहा कि 13 लाख कुएं कहां पर हैं, पता नहीं है, 9 लाख तालाब कहां पर हैं, पता नहीं है? जिस बेंगलुरु सिटी के अंदर लगभग 70 तालाब थे, आज चार तालाब नहीं बचे हैं। जब बोरवैल से नीचे का पानी खींचेंगे, तो ऊपर कहां से पानी आएगा? इसीलिए एक समग्र सोच होनी चाहिए। तात्कालिक समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ इस दिशा में पार्टी से भी ऊपर उठकर हम राजनीति के कारण time being किसी

के लिए taunt कर सकते हैं, लेकिन यह जिंदगी को लम्बे समय तक खुश नहीं रख सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ और बात सोचें। जैसे अभी आईपीएल की बात आई, आईपीएल के मैदान के लिए पानी जाता है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। नरेश जी, हमारे देश के अंदर यह जो आईपीएल आ गया है, यह बात बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि कम से कम इसके जुए के अंदर 20 हजार करोड़ से ज्यादा पैसा गांव वाले डाल रहे हैं, जवान बच्चे डाल रहे हैं, उनकी जिंदगी बरबाद हो रही है, इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। एक तरफ लोग भूखे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लातूर में पीने के लिए पानी नहीं है, वहां पर भी लाख लीटर पानी की बोतलें बिकती हैं। कहीं न कहीं हमारे मानवीय संबंध का प्यार में अभाव निर्माण हुआ है। इसके बारे में हमें सोचना होगा। एक तरफ आदमी टैंकर से पानी के लिए लालायित हैं, तो दूसरी तरफ लोग 15-20 रुपये देकर बोतल का पानी पी रहे हैं।

इसीलिए हमारे कृषि के पैटर्न में बदलाव लाना चाहिए और उस सम्पत्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर हम यह नहीं करेंगे, तो गांव मरेगा, तो देश मरेगा। आज बचे हुए गांवों की दयनीय स्थिति अनेक प्रकार की बुरी आदतों के कारण गांवों में निर्मित हुई है। इसलिए यहां उपस्थित माननीय कृषि मंत्री जी और उमा भारती जी, साथ ही साथ नितिन जयराम गडकरी जी और पर्यावरण के सभी मंत्री, आपस में मिलकर कुछ टाइम बाउंड करना है, करिए। हमारी कर्णाटक सरकार ने केंद्र से 1,400 करोड़ रुपए की मांग की थी, तो केंद्र सरकार ने लगभग साढ़े सात सौ करोड़ रुपए दिए हैं। यदि और भी जरूरत पड़ी, तो केंद्र सरकार जरूर देगी, लेकिन इसके साथ-साथ दूरगामी योजना बननी चाहिए। जो कर्णाटक के जिले हैं, इनमें बेलगाम, गुलबर्गा, बीदर, रायचूर, कोप्पल, उत्तर कर्णाटक, धारवाड़ और हुबली है, ये सभी जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं। इसलिए वहां पर इन सभी परिस्थितियों से निपटने का काम होना चाहिए। मुझे शरद पवार जी की एक बात याद आती है कि कई बार मीडिया हमें आवश्यकता से अधिक भड़का देता है। मुझे मालूम है कि एक जगह इतना ज्यादा चारा जमा करके रखा गया है कि उसको ले जाने वाला कोई किसान ही नहीं है। कई बार पेपर में आने के बाद सरकार घबराकर सब सामान ले जाकर रख देती है, लेकिन वहां अकाल ही नहीं पड़ता है, तो लोग उसको लेकर क्या करेंगे? इसलिए मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि यदि कहीं कोई घटना घटती है, तो उसे छिपाकर रखे, लेकिन उसको बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए। मीडिया को इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि पैसा अनावश्यक जगह पर जाकर बरबाद न हो जाए। एक बार कर्णाटक में फ्लड आया तो मेरे एक मित्र ने तहसील में बताया, चारों तरफ से लोग सहायता देने के लिए आए। उस तीन महीने में सबसे ज्यादा बिजनेस कहां हुआ? आपको जानकार आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा बिजनेस शराब की दुकान पर हुआ। ऐसी कई सामाजिक विकृतियां हैं, यदि हम इनको समाज से बाहर नहीं निकालेंगे, तो इसका दुरुपयोग करने वाले ही लाभ लेंगे। इसको रोकने के लिए सरकार एक दूरगामी योजना बनाए और साथ ही साथ उसका समयबद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। जिन-जिन प्रदेशों में इसका अभाव दिख रहा है, माननीय सदस्यों ने जो राय दी है, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, वे आपस में मिलकर समस्या का निराकरण करें। इसके साथ ही ये कोई दूरगामी योजना भी बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)ः मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज देश के सामने जो बहुत बड़ी आपदा है, मुझे उस पर बोलने का आपने अवसर दिया। चूंकि हम

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

4.00 P.M.

इस समस्या से लगातार जूझ रहे हैं, इसलिए हमने निवेदन किया है। हमारे पूर्वज़ कहा करते थे,

'बुंदेलों की सुनो कहानी,
बुंदेलों की बानी में,
पानीदार यहां का पानी,
आग यहां के पानी में।'

आज भले ही पानी हमारे पास नहीं है, आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वहां के लोग स्वाभिमानी हैं, वहां के लोग वीर हैं, वहां के लोग अच्छे तरीके से संघर्ष करना जानते हैं।

मान्यवर, आज पूरे देश में 11 राज्य सूखे से प्रभावित हैं, लेकिन मैं ज्यादा बात न करके अपने उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड तक ही सीमित रहना चाहता हूं। आज बुंदेलखंड की जो समस्या है, वह किसी से छिपी नहीं है। बुंदेलखंड में आज तालाबों में पूरे तरीके से पानी सूख गया है। बांध पूरे तरीके से सूख गए हैं, हैंडपम्प में पानी नहीं आता है, कुएं में पानी नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलकर वहां सबसे बड़ा बांध राजघाट बांध बना है, जिसकी क्षमता 70TMC पानी की है, लेकिन आज उसमें मात्र 6TMC पानी उपलब्ध है। माताटीला बांध में भी आज मात्र 2 TMC पानी उपलब्ध है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 100 बांध हैं। उन सौ बाँधों में से चौंतीस बांध केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज सारे के सारे बांध सूखे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है, उस मध्य प्रदेश के हिस्से में जो सबसे ज्यादा बांध हैं, वे बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हैं, लेकिन वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। हमारी बहिन उमा भारती जी बैठी हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र से ही आती हैं, वहां इनका गृह जनपद भी है, मैं बताना चाहता हूं कि टीकमगढ़ को पांच दिन में एक बार पानी मिलता है, शिवपुरी का पानी लेने का नंबर आठ दिन में आता है, दमोह का सात दिन में पानी मिलने का नंबर आता है। आज ऐसी परिस्थितियां लगातार बनी हुई हैं। मान्यवर, एक तरफ बुंदेलखंड में पानी नहीं है और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या है, वह जानवरों की समस्या है। वहां पर जानवरों के खाने के लिए चारा नहीं है, उनके पीने के लिए पानी नहीं है, यहां तक कि जो जंगली जानवर हैं, वे भी पानी पीने के लिए गांव की तरफ भागते हैं। वे जहां भी थोड़ा-बहुत हरा-भरा क्षेत्र देखते हैं, उसको उजाड़कर चले जाते हैं। वे आज घरों में घुसकर पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

श्रीमान् जी, मैं इस भीषण समस्या के मौके पर अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए जो प्रयास किए हैं, वे सराहनीय हैं। हमारे आदरणीय अग्रवाल जी ने भी अपनी बात रखी है, लेकिन आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पैकेट गरीबों को बांटा है, जिसमें 15 किलो आटा है, 2 किलो चावल हैं, दाल है, घी है, तेल है, हल्दी है, मिर्च और दूध का पैकेट भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब लोगों को इतना सारा सामान फ्री में बाँटने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से उनको यह लगातार चार महीने तक देने की व्यवस्था की है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 2.5 लाख लोगों को "समाजवादी पेंशन योजना" के तहत कम से कम पांच सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की व्यवस्था की है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, हमारे युवा मुख्यमंत्री

जी ने गांव-गांव जाकर बुंदेलखंड का दौरा किया। क्योंकि एक दिन अखबार में एक खबर छपी थी, किसी मीडिया के साथी ने यह खबर छापी थी कि लोग घास की रोटियां खा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस गांव में, उस घर में गए। उन्होंने उस घर में जाकर परिवार के लोगों से मिलने का काम किया, उनकी समस्याओं को जानने का काम किया। उन्होंने जहां लोगों की समस्या को जाना, वहीं प्रशासन को भी निर्देश दिया कि बुंदेलखंड का कोई भी व्यक्ति भुखा न सोए, कोई भी व्यक्ति भुख के कारण अपनी जान न गँवाए। यह जिम्मेदारी ज़िले के प्रशासन की होगी, इसको सुनिश्चित किया। इसलिए मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार की मदद करनी चाहिए। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मात्र 777 करोड़ रुपये दिए, इस बार भी लगभग 2,100 करोड़ रुपये मांगे थे, लेकिन मात्र 934 करोड़ रुपये ही उत्तर प्रदेश की सरकार को उपलब्ध हो पाए हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बुंदेलखंड का सूखा आपके लिए ख़बर हो सकती है, किसानों की बदहाली आपके लिए ख़बर हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे युवा मुख्यमंत्री काम करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके हाथ मत बांधिए, उनको स्वच्छंद कीजिए और आप देखिए कि बुंदेलखंड में किसी के सामने समस्या न आए, किसी के सामने पीने के पानी की दिक्कत न आए, इसके लिए व्यवस्था कीजिए। मान्यवर, आप जितने ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, आपको कराने चाहिए। मैं आज इस मौके पर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): धन्यवाद।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव: आपने जो संसाधन दिए हैं, वे ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर हैं, इसलिए आपको इसके लिए मदद देनी चाहिए। मैं आज के अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ सुझाव जरूर देना चाहता हूं कि इसका एक स्थायी हल निकालने की आवश्यकता है। यह समस्या कोई रातों-रात की समस्या नहीं है, एक लंबी अवधि की समस्या है। यह समस्या देश की आज़ादी के अवसर से लगातार चली आ रही है, क्योंकि बुंदेलखंड की लगातार उपेक्षा की गई है। जो लोग सत्ता में रहे हैं, उन्होंने बुंदेलखंड को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने "बुंदेलखंड विकास निधि" की स्थापना करके बुंदेलखंड के लोगों की मदद करने और बुंदेलखंड को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया। मान्यवर, मैं आज के मौके पर निवेदन करना चाहता हूं, यहां बहिन जी मौजूद हैं, हमारी उस दिन इनसे मीटिंग में भी बात हुई थी कि बुंदेलखंड में एक चंदेलकालीन तालाब है, वहां पर थोड़े-बहुत तालाब नहीं हैं, बल्कि हज़ारों की तादाद में तालाब हैं, जिनका एरिया एक हज़ार एकड़ तक का है। अगर उनकी डीसिल्टिंग करा दी जाए, खुदाई करा दी जाए और उनको पानी से भरने के लिए एक लिंक बना दिया जाए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बुंदेलखंड की एक-एक इंच जमीन को सिंचित किया जा सकता है। इससे बुंदेलखंड में वह हरियाली आ सकती है कि हम बुंदेलखंड की पैदावार के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को खिलाने का काम कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था

[डा. चंद्रपाल सिंह यादव]

होनी चाहिए, जैसे पशुपालन है, वाणिकी है, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन के कारण खेती खराब हो जाए, तो कम से कम उनके पास ऐसी आमदनी रहे, जिससे वे अपने बच्चों और परिवार का पेट भर सकें।

मान्यवर, अगले वर्षों में बुवाई होगी, लेकिन बुवाई के लिए बीज नहीं होगा। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगले वर्षों में बीज की बुवाई के लिए किसानों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और गरीब किसानों के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। श्रीमान जी, वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मैं आज केंद्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड जैसे उपेक्षित और गरीब क्षेत्र में अगर SEZ बना कर वहां उद्योग-धंधे लगाए जाएँ, तमाम पैसे का निवेश करने वाले लोग बुंदेलखंड पहुँचें और केंद्र की सरकार उनको सुविधाएँ प्रदान करे, तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार मिल सकता है और लोग खुशहाल हो सकते हैं। ...**(समय की घंटी)**...

मान्यवर, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पीने के पानी की समस्या है। पीने के पानी के लिए आप इसे भगवान के ऊपर छोड़ कर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हिन्दुस्तान के एक-एक व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध हो। श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूँ...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः यादव जी, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, चूँकि आप प्रभावित क्षेत्र से हैं, इसलिए मैंने आपको 8 मिनट बोलने दिया, हालांकि आपकी पार्टी का टाइम 9 मिनट का है।

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः सर, आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय)ः ठीक है, आप एक मिनट और ले लीजिए।

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब लोक सभा का चुनाव हो रहा था, तो देश की जनता ने सोचा था कि—

"कहां तो तय था कि चिराग हरेक घर के लिए,
लेकिन आज स्थिति यह है कि
मयस्सर नहीं चिराग एक शहर के लिए।"

आज लोग सोच रहे हैं कि—

"यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है,
चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए।"

धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Thank you, Sir. The drought situation has shown how vulnerable our country is to weather and climatic changes. Maharashtra, Karnataka,

Telangana and Andhra Pradesh have excellent rivers and advanced irrigation system, yet, the reality is that they are suffering from the most serious consequences of drought today. The media has pointed out that all reservoirs have dried up. Even the drinking water is not available.

Sir, there is the story of transporting drinking water to drought hit State of Maharashtra by Railway wagons. I congratulate the Railway Minister, Shri Suresh Prabhu for his effort. But it is a sorry story that we have to transport drinking water by Railway wagons.

Sir, in the short term, I address the Minister and the Government that they must meet the drinking water needs of both the people and the animals today. The Government also has to provide food, work and fodder for the entire rural population, both people and cattle.

Sir, we need very long term and short term plans. We should not suffer from drought of ideas. We should not suffer from drought of action. We should have long term and short term plans. Sir, the attitude should not be that you would wait and watch how monsoons are going to be. That would be disastrous for the rural people. The damage is so severe that the Government must act and there must be urgent economic relief for the people living in the rural areas and also partly for the urban areas.

Sir, we talk about natural disasters. But the entire machinery of the Government does not have a plan how to counter this kind of a massive drought which spread almost across 12 States.

Where is the disaster response from the Government? Frequently, the Government issues advertisements, but is that enough? It was, again, the Supreme Court which took up the issue and commanded the Government to respond immediately. The Government, in fact — I will use the word — 'failed' to anticipate the serious drought situation and it had absolutely no plans to mitigate the sufferings of the people.

Sir, the Ministry of Agriculture, the Department of Rural Development and the other Ministries seem to have ignored the consequences of the natural disaster. Sir, I might add, at this point, that drought is sending the rural people into the hands of moneylenders. The Government banks are not meeting the needs of poorer Indians who are farmers, small and marginal farmers, and the landless farmers. Using the RBI's present attitude, the public sector banks have distanced themselves from lending to the rural poor. Therefore, they have no alternative but to go to a private moneylender. Sir, just now, Sharad Pawarji called me and said farmers' suicides was a matter of serious concern. He gave me certain figures. In 2013, in Maharashtra, the number of suicides reported was 1,296; in 2014, 1981, in 2015, 3,228. These are the

[Shri D. Raja]
figures given by Shri Sharad Pawar. He called me and told me, this is the situation in Maharashtra. Sir, we recently observed the 125th Anniversary of Dr. Ambedkar. It is interesting to note here that, in 1938, Dr. Ambedkar was MLC in the Bombay Legislative Council. He had sensed the sufferings of the farmers and rural people at that point of time; they were at the mercy of moneylenders. Sir, it was Dr. Ambedkar who had introduced the Bombay Moneylenders Act. Sharad Pawarji agrees with me that it was Dr. Ambedkar who did it. Now, the same situation prevails today. There are reports that rural people, poor people, are committing suicides because they are in the clutches of private moneylenders. Their indebtedness is the primary or the root cause for their suicides. The Government should evolve certain schemes to provide debt relief to the rural poor, farmers and agricultural workers.

Sir, coming to certain immediate steps, I would quote what today's *The Hindu* had carried as an article written by a very known and reputed economist, Jean Dreze.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Sorry, your time is over.

SHRI D. RAJA: He suggests that MNREGA must be strengthened and expanded. The money earmarked from the Budget is not adequate. It should be increased. In the same way, the Public Distribution System must be strengthened. National Food Security Schemes must be strengthened in order to mitigate the effect of the drought.

Sir, lastly, I would like to draw the attention of the Government to one serious issue. Everybody talked of protecting the water bodies. Everybody talked about rainwater harvesting. It is now accepted that India does not follow an agro-climatic suitability in growing of crops. We grow crops which are totally unsuitable to our weather, soil and monsoon compatibility. Sir, I would quote this and end. To grow one kilogram of sugar, we need 6,000 litres of water; to grow one kilogram of rice, we need 7,000 litres of water. This needs to be examined by the Government. Can we grow water-guzzling crops in such a fashion? And do we need to move towards conservation of water, preservation of our water bodies, change of crop patterns and technology in agriculture? All these will have to be addressed by the Government. Finally, Sir, agricultural workers are the most vulnerable sections. They happen to be the Dalits and the Adivasis, and the Government should give them attention...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): You may give your suggestions to the hon. Minister separately.

SHRI D. RAJA: I am asking the Minister to take note of this. The plight of agricultural workers is miserable and the Minister should take up their issues on a war-footing basis. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Dr. Sanjay Sinh. Not present. Shri Bhupender Yadav.

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान)ः सम्माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हर वर्ष हम लोग सूखे की चर्चा करते हैं, लेकिन जो सूखे का संकट है, वह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश का जो जल संसाधन मंत्रालय है, उसके एक आंकड़े के अनुसार भारत में 21 अप्रैल, 2016 तक जलाशयों की जो कुल क्षमता है, उसका 22 प्रतिशत जल ही उपलब्ध है, जबकि पिछले वर्ष यह कुल संग्रहण का 65 प्रतिशत और पिछले 10 वर्षों में यह 76 प्रतिशत था। इस समय सूखे के संकट का जो ज्यादा समाचार आ रहा है, वह महाराष्ट्र से ज्यादा आ रहा है, लेकिन पिछले 67 सालों में महाराष्ट्र में जो जल प्रबंधन का कार्य हुआ है और जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से तो महाराष्ट्र में जो बड़े जल प्रबंधन के बांध बने हैं, वे 1,845 बने हैं। इसलिए एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या में बांध बनने के बाद भी, जो 15 मीटर ऊँचे हैं और लगभग 600 लाख क्यूबिक मीटर के बांध बने हैं, उसके बाद भी हम सूखे के संकट का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

मुझे ध्यान है कि एक बार शरद पवार जी ने जब कृषि पर भाषण दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब शुरुआत की थी, जब नया-नया सदस्य बना था, तो बारामती में स्थायी रूप से पानी और सूखे के संकट का स्थायी समाधान करने की बात की। लेकिन इसके बावजूद भी आज मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और बुन्देलखंड में हम पूरे तरीके से समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं?

सर, जब आज़ादी मिली थी, तब देश में लगभग 50 के करीब नगर निगम थे, जबकि आज हमारे यहां 156 नगर निगम हैं। मुम्बई के आसपास जितने भी बड़े जलाशय बने हैं, उनके पानी की जो ज्यादातर आपूर्ति है, वह शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के लिए होती है। तो जिस प्रकार से नगर बढ़ रहे हैं और शहरों को लगातार जलापूर्ति करनी पड़ती है, सरकार को उनमें और ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलन बनाने के लिए एक कोई सर्वे कराना चाहिए, जिसमें यह देखा जाए कि हम जो पानी को इकट्ठा करते हैं, उसकी मांग और आपूर्ति का क्या सम्बन्ध रहना चाहिए। जलाशयों में हम जितना पानी इकट्ठा करते हैं, देश के बड़े जलाशयों में, उनमें अगर 60 प्रतिशत पानी रहेगा, तभी हम वहां बिजली का उत्पादन कर पाएँगे। तो हमें जलाशयों में बिजली का उत्पादन भी जारी रखना है, ताकि सब लोगों को बिजली भी मिलती रहे। हमें शहरों के लिए भी पानी की लगातार आपूर्ति को बनाए रखना है और खेती तथा पशुओं के लिए भी आपूर्ति को बनाए रखना है। हमारे देश में पानी के संकट को...

अभी माननीय मंत्री जी कह रही थीं कि उनके मन में भी यह संशय था कि इसको केंद्रीय विषय बनाया जाए या यह राज्यों का विषय रखा जाए। एक जो सबसे बड़ा विषय है कि हमने वॉटर पंचाट बनाकर देश के न्यायालयों को यह कहा कि आप इस समस्या का समाधान करें। परन्तु जितने भी अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं, वे एक लम्बे समय से, पिछले 30, 35, 40 सालों से, सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़े हैं और अभी उन पर एविडेंस की शुरुआत भी नहीं हुई है। आखिर संसद को इस पर विचार करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में एक सकारात्मक और सक्रिय कार्रवाई करके हमने सारे अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने का यह जो एक मैकेनिज्म दिया है, यह मैकेनिज्म 30-40 सालों से अपनी मूल गति पर भी नहीं आ पा रहा है, तो इसके संकट का समाधान हम किस प्रकार से कर पाएँगे?

[श्री भुपेंद्र यादव]

इसलिए अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जल के संकट का और सूखे के संकट का सामना करने के लिए अगर कोई नीति बना सकते हैं तो देश में जितना पानी हम लोगों के पास रहता है, दोनों तरह का पानी है, सतह पर बहने वाला नदी का जल भी है और भूगर्भ का भी जल है, जो जमीन के अंदर है। लेकिन उसका जो उपयोग करने वाली क्षमता है, क्योंकि जमीन की टॉपोग्राफी ऐसी है, जमीन में पानी संशोषित भी होता है, पानी का और भी उपयोग करना होता है, केवल 60-70 प्रतिशत ही हम उपयोग कर पाते हैं। तो देश में वर्षा के जल का संचयन करने के लिए और पानी की जो यह रीचार्जिंग है, इसके लिए कोई एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए और इसके लिए संसद के द्वारा भी कोई अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या ऐसी नहीं है कि जो एक बार में या दो बार में शुरू हो सके। इस बार सरकार ने एक अच्छा काम शुरू किया है कि मनरेगा के माध्यम से देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई जल परिसम्पत्तियों का निर्माण हो, उसके लिए सरकार ने मनरेगा जैसे जो कार्यक्रम हैं, उसको पूरा करने का बीड़ा हाथ में उठाया है। आजादी के बाद 67 सालों में जितनी भी देश की सिंचाई परियोजनाएं बनी हैं, लगभग 89 सिंचाई परियोजनाएं ऐसी हैं, जो 40-40, 50-50 साल से पेंडिग पड़ी हुई हैं, उनका काम पूरा नहीं हुआ है। इस बार के बजट में भी सरकार ने एक विशेष योजना का प्रावधान करके वे जो 89 परियोजनाएं हैं, उनको पहले पूरा करने के कार्य को हाथ में उठाया है। यह तो हमारी स्थायी रूप से जल के विषयों को पूरा करने की जो कार्यवाहियां हैं, वे हैं, लेकिन इसके परिणाम के संबंध में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूं जहां हमारे देश की 10 प्रतिशत आबादी रहती है, लेकिन राजस्थान में पानी पूरे देश के जल का केवल एक प्रतिशत है। पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है, जहां पर मुख्य रूप से जो आजीविका है, वह पशुपालन के ऊपर आधारित है। देश में इस समय जो SDRF के नॉर्म्स और NDRF के नॉर्म्स हमने बनाए हैं, उसमें 90 दिन तक अगर बारिश नहीं होती है तभी वह सूखा डिक्लेयर किया जाता है। उसको कम से कम देश की जो कुछ हमारी आवश्यकताएं हैं, जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में लगातार 90 दिन या छः-छः महीने तक बारिश नहीं होती, औसत से बहुत कम बारिश होती है, वहां पर NDRF के सूखे के जो नॉर्म्स हैं, सारे देश में सूखे के नॉर्म्स एक जैसे नहीं रखे जाते। सूखे के नॉर्म्स के लिए आवश्यक है कि जो विशेष क्षेत्र हैं, जहां वर्षा का काफी ज्यादा संकट है, उसके लिए सूखे के नॉमर्स में हमें कुछ रियायत करनी चाहिए और इस प्रकार के जो राज्य हैं, विशेष रूप से राजस्थान में जो वॉटर ग्रिड बनाने की आवश्यकता है, भूगर्भ में जो पानी है उसको इकट्ठा करके जो वॉटर ग्रिड बनाने की आवश्यकता है, उसके संबंध में जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर भी मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनको विशेष सहायता देने की भी आवश्यकता है। लेकिन नदियों के जो हमारे अंतर्राज्यीय जल विवाद के विषय हैं, उसके संबंध में कोई एक समाधानकारक नीति बने, उसको न्यायालय के वाद से बाहर निकाल कर हम कोई परस्पर सहमति के आधार पर एक प्रकार की नीति विकसित करें, जिससे देश में पानी का संकट जैसे-जैसे शहर बढ़ेंगे तो पानी की मांग और आपूर्ति भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इस सबके बीच में संबंध और समन्वय बने, इसके लिए कोई वॉटर ट्रिब्यूनल और एक नए कानून की और एक समन्वय की पॉलिसी, नीति को बनाने आवश्यकता है। सरकार ने पिछले दिनों देश के सारे जल प्रबंध के विषयों की नीतियों के लिए पॉलिसी पर काफी कार्य किया है, लेकिन उनका क्रियान्वयन करने के लिए एक व्यापक सहमति पत्र और एक जल आंदोलन बनाने

की आवश्यकता है तभी हम सूखे का संकट, जो लगातार बार-बार आने वाला है उससे निपट सकेंगे। मानसून की बारिश एक बार सुलझा देती है लेकिन मानसून हमेशा एक जैसा आए, हमारे देश में इसकी गारंटी नहीं रहती। अगर मानसून नहीं भी आता है तो जो अपनी मांग और आपूर्ति है, उसका स्थायी रूप से समाधान करने के लिए जल संग्रह की नीति को हम एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता मानते हुए इसके संबंध में कोई सर्वानुमति की नीति तैयार करें, तभी हम जल संकट का स्थाई रूप से समाधान कर पाएंगे, धन्यवाद।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश)ः माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सूखे पर चर्चा के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं दो-तीन बातें रखूंगा। चूंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, वहां लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ रहा है। सूखे की स्थिति के कारण वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। किसान परेशान है। खास तौर से जो जिले हैं, उनमें 11 राज्यों में सूखा पड़ा है। झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, ये एरियाज़ विशेष रूप से सूखे की चपेट में हैं। वहां पर रबी की फसल बोई नहीं गई और खरीफ की फसल अपने आप नष्ट हो गई। मान्यवर, भारत सरकार ने खाद्यान्न गारंटी योजना लागू की है, जिसके तहत दो रुपए किलो गेहूं और तीन रुपए किलो चावल मिलता है। इसके तहत लोगों को दो किलो या तीन किलो प्रति यूनिट करके अनाज मिलता है। इस संबंध में गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि क्या पांच किलो अनाज में मेरा पूरा महीना चल जाएगा? इस संबंध में मेरा यह सुझाव है, मांग है कि इसको बढ़ा कर प्रति यूनिट दस किलो गेहूं और दस किलो चावल कर दिया जाए, जिससे किसान अपने बच्चों को महीने भर खाना खिला सके। किसान के खेत में तो कुछ उपजा नहीं और अगर उनको इतना नहीं मिलेगा, तो इससे उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि माननीय कृषि मंत्री जी ने खेत-तालाब योजना के अंतर्गत जो योजना चलाई है, इसके तहत 50 प्रतिशत अनुदान सरकार की तरफ देने की बात कही गई है और 50 प्रतिशत राशि किसान को देनी है। चूंकि किसान के पास पैसा नहीं है, वह लगातार तीन साल से सूखे की चपेट में है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि इसको शत-प्रतिशत अनुदानित कर दिया जाए, जिससे किसान को इसका फायदा मिल सके ।

महोदय, एक सोलर पम्प योजना चलाई गई है, जिसके तहत आपने पांच एचपी के लिए अलाऊ किया है। चूंकि वहां पर जल स्तर बहुत नीचे है, इसलिए मेरी यह मांग है कि आप इसको बढ़ा कर साढ़े सात एचपी या दस एचपी कर दीजिए ताकि किसान पम्प के माध्यम से पानी निकाल सके, क्योंकि पांच एचपी में वहां पर सोलर पम्प काम ही नहीं करेगा और पानी नहीं निकलेगा।

मान्यवर, वहां पर पशुओं के पानी के पीने की समस्या है। इस समय वहां पशु मर रहे हैं। अन्नाप्रथा में खास करके गायें ज्यादा हैं, हमारी माननीय मंत्री मेनका संजय गांधी जी बैठी हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वहां तमाम एजेंसियों को भेजिए, क्योंकि वहां पर खास तौर से गायें मर रही हैं। अगर देश में कहीं गाय से भरा ट्रक पकड़ा जाता है, तो उस पर हल्ला होता है। वहां पर पानी और चारे के अभाव में ज्यादातर गायें मर रही हैं। इसके लिए कोई योजना बनाई जाए। देश में तमाम एनजीओज़ हैं, उद्योगपति हैं, उनके द्वारा रिसर्च करवाई जाए। वहां पर पशुओं को बचाने के लिए पीने का पानी और चारे की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है।

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

सर, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव जी ने अंत्योदय कार्ड धारक यानी जो कि बहुत गरीब हैं, उनको 25 किलो आलू, 10 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो तेल, 1 किलो देशी घी, 1 किलो दूध पाउडर देने का काम कर रहे हैं। यह बहुत सराहनीय योजना है। हम यह चाहते हैं कि इसी तरह से भारत सरकार की तरफ से भी कोई पहल होनी चाहिए, जिससे कि अत्यंत गरीब लोगों को लाभ मिल सके।

हमारे देश में गरीबी और रोजगार गारंटी सबसे बड़ी समस्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र में रोजगार नहीं है, वहां गांव के लोग रोजगार के लिए कहां जाएंगे, वे क्या करेंगे? इसी कारण से नक्सलवाद पैदा होता है। मेरा यह सुझाव है कि जो मिनिमम वेजेज़ एक्ट है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आप विश्व स्तर पर इसका अध्ययन कराइए। जब पेट्रोलियम पदार्थ को विश्व स्तर पर जोड़ दिया गया है, तो मिनिमम वेजेज़ एक्ट को भी विश्व स्तर पर जोड़ना चाहिए। पूरे विश्व में मौजूद वेजेज़ एक्ट का अध्ययन करके विश्व स्तर पर मिनिमम वेजेज़ एक्ट में सुधार कर दीजिए ताकि अगर कोई व्यक्ति महीने भर काम करे, तो उसको इतना वेजेज़ मिल सके, जिससे वे महीने भर अपने बच्चे का पालन-पोषण कर सके, अपना मकान बना सके, अपने लड़के और लड़की की शादी कर सके। मान्यवर, यही मेरा सुझाव है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। चूंकि हमारा क्षेत्र सूखे की चपेट में है, वहां पर तालाब पूरी तरह से सूख गए हैं। माननीय मंत्री जी को मेरा एक सुझाव यह है कि वर्षा का पानी समुद्र में चला जाता है, आप तालाब योजना बना रहे हैं, अगर आप इसी योजना में इस तरह की योजना भी डाल देंगे कि अगर किसी के पास दो एकड़ खेत है, तो वह अपने खेत में एक पक्का टैंक बना ले और उसमें वह वर्षा का पानी इकट्ठा कर ले। ऐसा करने से उस टैंक में साल भर पानी रहेगा ...**(समय की घंटी)**... जिससे वह अपने खेत की सिंचाई कर लेगा। इस तरह से हम सूखे की स्थिति से निपट सकते हैं। यही हमारा सुझाव है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री संजय राउत (महाराष्ट्र): सर, देश की आबादी का एक-चौथाई हिस्सा यानी 33 करोड़ लोग सूखे का कहर झेल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं महाराष्ट्र पर आ जाऊं ? ...**(व्यवधान)**... नहीं तो आप वहां बैठे हैं न? आज महाराष्ट्र में जो सूखा है, वह आपकी ही देन है, इसलिए आप जरा चुप बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

सर, यह जो संकट है, वह एक या दो राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 10 राज्यों का संकट है, 256 जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। हर सत्र में हम सूखे में किसानों की जो अवस्था है, पानी का जो संकट है, उस पर लम्बी चर्चा करते आए हैं और सभी सम्माननीय सदस्य अपने-अपने गृह राज्य के संकट के ऊपर यहां चर्चा करते हैं। जब बजट सत्र शुरू हुआ था, तब भी हमने यह बात सुनी थी। खासकर बुंदेलखंड के बारे में के. सी. त्यागी जी ने जो बात उस वक्त कही थी, वही स्थिति आज महाराष्ट्र के मराठवाड़ा की है। उस वक्त हमने सुना था, आज भी पढ़ रहे हैं कि वहां के लोग घास की रोटी खाकर जी रहे हैं, लेकिन आज स्थिति बदल गई है, जैसा कि आप बोल रहे थे। वहां के करीब 50 परसेंट परिवार के लोग छः-छः महीने तक दाल-चावल नहीं खाते। अगर ऐसा है तो हमारा जो "खाद्य सुरक्षा कानून" बना था, उसका क्या हुआ? वह क़ानून कहां है? वहां बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, वहां का हर पांचवा परिवार एक दिन भूखा सोता है। यह आज के अखबार की मीडिया रिपोर्ट है। लेकिन यह केवल बुंदेलखंड का दर्द नहीं है, बल्कि 10 राज्यों के लगभग 200 से ज्यादा जिलों का यही दर्द है। यह बुंदेलखंड

का दर्द है, यह मराठवाड़ा का दर्द है।

जब चुनाव आते हैं, तो राजनीति में हम हमेशा घोषणाएँ करते हैं और हमारे लोगों ने भी घोषणा की थी। हमने कांग्रेस-मुक्त भारत बनाने की घोषणा की थी। यह अच्छी घोषणा है, लेकिन सबसे पहले हमको सूखा-मुक्त भारत बनाना होगा, गरीबी-मुक्त भारत बनाना होगा। जब सूखा-मुक्त भारत होगा, तो देश अपने आप कांग्रेस-मुक्त हो जाएगा, यह हमारी जिम्मेदारी है। चूंकि सूखा एक गरीबी है, यह उनकी देन है। यह 50 साल की बीमारी है, दो साल की बीमारी नहीं है। मैं पूरे देश की बात करता हूँ। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कर्णाटक हो, गुजरात हो, वे आज पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग प्यासे हैं, भूखे हैं और वे अपना घर-बार छोड़कर, पशुधन छोड़कर पलायन कर रहे हैं। ये सभी हमारी भारत-माता के सपूत हैं। उनके मन में, उनके दिल में भारत माता है, लेकिन पेट में भूख हैं, प्यास है। उनको "भारत माता की जय" बोलना है, लेकिन मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं इसको भूख से जोड़ना चाहता हूँ। जिनके पेट में भूख है, जो भूखे हैं, कंगाल हो गए हैं, आप उनसे "भारत माता की जय" की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, यह हम सबको सोचना पड़ेगा। इसलिए भारत माता के हमारे जो 33 करोड़ भूखे लोग हैं, उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम यह हमेशा मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह हमारा दुश्मन है, लेकिन उससे भी बड़ा दुश्मन आज यहां का सूखा है, गरीबी है, अकाल है, भूख है। उनके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। हम पाकिस्तान से चर्चा करते आए हैं और करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग आज घर-बार छोड़कर भाग रहे हैं, उनसे चर्चा कीजिए। उनसे खुद जाकर चर्चा कीजिए, मंत्री को चर्चा करनी चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने "पंचायती राज दिवस" पर अच्छा संदेश दिया कि हमारा देश सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि हमारा भारत गांवों में बसता है। हम भी यह मानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। भारत मुम्बई, चेन्नई, भोपाल या रांची में नहीं बसता है, लेकिन यह जो पूरा भारत गांवों में बसा है, वह भारत आज भूख से मर रहा है। आज लोगों में किसानों को मार्गदर्शन न करने की होड़ लगी है। मैं कल पढ़ रहा था, एसबीआई की चेयरमैन ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है। कोई मैडम भट्टाचार्य जी हैं, उन्होंने कहा है, 'Farmers cannot live by farming alone. There is a need to create other activities that give a farmer a regular income source. Only farming is not enough.' यह विचार अच्छा है, लेकिन यह कोई नया विचार नहीं है। आप यह जो नया इनकम सोर्स देना चाहते हैं, ये जो बड़े-बड़े लोग बात करते हैं, वह सिर्फ बोलने की बात है। आप काम करो। आज "मनरेगा" भी जब ठीक से नहीं चल रही है, तो आप क्या इनकम सोर्स देंगे? अगर आप इनकम सोर्स बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। स्टेट बैंक के 850 करोड़ रुपये लेकर माल्या भाग गया, उसको आप नहीं रोक पाए, लेकिन जो किसान 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का कर्जा लेता है, उसके घर की आप जब्ती लाते हैं और उसका घर-बार आप छीन लेते हैं। आप यह 2000-5000 रुपये के लिए करते हैं, यह कोई नीति नहीं है। अब मैं महाराष्ट्र पर आता हूँ।

अगर आप महाराष्ट्र की हालत देखेंगे तो सबसे बुरी हालत आज महाराष्ट्र की है। 17,000 गांव आज बूंद-बूंद पानी को तरस रहे हैं। लातूर जैसे जिले में आज एक-एक महीने के बाद पानी आ रहा है। वहां नहाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। यह ज़िन्दगी है या नरक है, इस बारे में हमको सोचना होगा। हम 'अच्छे दिन' की बात करते हैं, लोगों को पानी देने की ज़िम्मेदारी भी आज हम सबकी है। ...**(व्यवधान)**... जब लोग आत्महत्या करते हैं तो एक

[श्री संजय राउत]
लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। क्या लोग एक लाख रुपये के लिए आत्महत्या करते हैं? आप उसको आत्महत्या करने से रोकिए। आप एक लाख रुपये मुआवजा देते हैं, वह ठीक है, परन्तु कोई भी व्यक्ति एक लाख रुपये के लिए आत्महत्या नहीं करता। ...**(समय की घंटी)**... मैं यहां कोई महाराष्ट्र राज्य के पैकेज के लिए नहीं खड़ा हूँ — पैकेज तो आप देते रहेंगे, पैकेज मिलता है या नहीं मिलता है, यह सब बाद की बात है, लेकिन मराठवाड़ा में सैकड़ों परिवार हैं, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हमने उनकी शादियां कराई हैं। आपको यह बात मालूम होगी, उद्धव ठाकरे साहब ने बीड में 500 बेटियों की शादियां कराई हैं, जालना में कराई हैं। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में हजारों बेटियों की शादियां धूमधाम से कराई हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Sanjayji, please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय राउतः शादियां नहीं रुकनी चाहिए नहीं तो किसान फिर आत्महत्या करता है। सर, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी देश के नेता हैं, विश्व के नेता हैं, वे पूरे देश में घूमते हैं, पूरे विश्व में घूमते हैं, लेकिन मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप एक दिन के लिए बुंदेलखंड जाइए, आप एक दिन के लिए मराठवाड़ा जाइए, सिर्फ एक-एक दिन के लिए जाइए। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः वे नहीं जाएंगे।

श्री संजय राउतः वे जाएंगे, हमें मालूम है। ...**(समय की घंटी)**... आप वहां की परिस्थिति देखिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri Ahmed Patelji. ...(*Interruptions*)...

श्री संजय राउतः मुझे विश्वास है कि वहां के लोगों के हालात देखने के बाद आप हमारे सूखाग्रस्त लोगों के लिए दिल्ली की सरकार से ज्यादा देंगे। ...**(व्यवधान)**... हमारे प्रधान मंत्री से मैं आह्वान करता हूँ कि आप बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जरूर जाइए, वहां जाकर देखिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Shri Ahmed Patelji, I have called your name.

श्री संजय राउतः तभी आप हमारे दर्द को मिटाने के लिए कदम उठाएंगे, जय हिन्द।

श्री अहमद पटेल (गुजरात): उपसभापति महोदय, सूखे के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सूखा एक अजीबो-गरीब कुदरती आपदा है। मैं इसकी कैंसर के साथ तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि सूखा कोई एक या दो दिन में नहीं आ जाता, यह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ता है। धीरे-धीरे स्थिति इतनी गम्भीर हो जाती है कि वह कैंसर की तरह जानलेवा बन जाता है और बहुत ही भयानक स्वरूप धारण कर लेता है।

हमारे पूर्व-वक्ताओं ने कहा कि करीबन 33 करोड़ लोग आज सूखे से प्रभावित हैं और कम-से-कम 90 से ज्यादा ऐसे बड़े reservoirs हैं, जिनकी पानी की क्षमता घटती जा रही है। इतनी

गम्भीर स्थिति होते हुए, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए, जिनसे हम यह कह सकते हैं कि हम लोग सूखे से निपटने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस से पूछा जाता है कि साठ साल में आप लोगों ने क्या किया? बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने यह की कि जो उपग्रह तकनीक है और मौसम विज्ञान है, उसमें इतना निवेश किया कि आज हम कई महीनों पहले यह पता लगा सकते हैं कि कब सूखा पड़ने वाला है, कब कितनी बारिश होगी — ज्यादा होगी या कम होगी — यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2015 में सरकार को पता था कि सूखा आने वाला है। पिछले कई महीनों से देश की जनता सूखे से प्रभावित है, लोग परेशान हैं। यह सूखे की स्थिति सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि शहरों की स्थिति तो और भी अधिक ख़राब होती जा रही है। आज शहरों में पानी की व्यवस्था नहीं है। हम स्मार्ट सिटी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए पानी कहां से आएगा, जब पीने के लिये भी पानी उपलब्ध नहीं है? हम स्वच्छता अभियान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए पानी कहां से लाएंगे? मेरे ख्याल से सरकार को खास तौर से जिस तरह से चिंता करनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो रही है। देश की स्थिति बहुत गम्भीर है, सूखे की स्थिति भयावह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, वह स्थिति भी उतनी ही चिंताजनक है। जब यूपीए की सरकार थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी सूखे की स्थिति होती थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर यहां पर खबर करते थे तो तुरंत कृषि मंत्री शरद जी या जो भी कोई मंत्री होते थे, यहां से टीम जाती थी तथा राज्यों के साथ, प्रदेशों के साथ परामर्श होता था, बातचीत होती थी कि कितने गावों में स्थिति ख़राब है।

उसके बाद जिस तरह से मदद करनी चाहिए, उस तरह से मदद होती थी। मुझे नहीं मालूम कि कितने प्रदेशों में आपने विजिट की या प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की, उनसे परामर्श किया। यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है या सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि आपने जो भी तैयारी की है, वह सही नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, तब जाकर स्टेट गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार जाग्रत होती है और चिंता में लग जाती है। खास तौर से महाराष्ट्र की बात हुई, वहां की स्थिति गंभीर है। आईसीयू वार्ड में भी जिस तरह से पानी होना चाहिए, वहां भी पानी नहीं है। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पानी के लिए हर जगह पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। महिलाएं अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना कुछ बूंद पानी के लिए दूर तक जाती हैं। मैंने टी.वी. चैनलों पर यह भी देखा है कि बेचारी महिलाएं पानी लाने के लिए कुएं में नीचे उतरती हैं। यह सच में चिंताजनक स्थिति है। केंद्र की सरकार को इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए।

"मनरेगा" की बात होती है। उन्होंने सही बात कही। "मनरेगा" सूखे से निपटने के लिए उचित माध्यम है। इससे लोगों को रोजगार मिलता है, इससे तालाब बनाए जाते हैं, रिज़र्वायर्स बनते हैं, लेकिन आज स्थिति क्या है? "मनरेगा" के बारे में कहा यह जाता है कि इसकी राशि बहुत बढ़ाई है, जो भी राशि है, वह प्रदान की गई है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो संकट है, जिस तरह से "मनरेगा" में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वह रोजगार मिल नहीं रहा है। वर्ष 2016-17 में "मनरेगा" के तहत दिया गया काम 3.15 बिलियन व्यक्ति-दिवस के बराबर था, लेकिन इसे घटाकर 980 मिलियन व्यक्ति-दिवस कर दिया गया। आज भी बहुत सारी राशि बाकी

[श्री अहमद पटेल]
है, जिसका भुगतान करना बाकी है। "मनरेगा" सूखे से निपटने के लिए एक उचित माध्यम है। इसके बारे में भी सरकार को खास तौर से चिंता करने की जरूरत है।

केंद्र में भाजपा की सरकार है। वह समस्या को मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि सूखा पड़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि जब कहा जाता है, तो थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। जहां तक मेरे गृह प्रदेश गुजरात का सवाल है, वह जल संकट के कगार पर खड़ा हुआ है। पानी न होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। करीब 200 जलाशयों में पानी केवल 26 प्रतिशत की क्षमता तक रह गया है, 2,500 से ज्यादा गांवों में जल संकट है। जलाशयों में पानी एक पखवाड़े के लिए बाकी है। केंद्र के पास कांग्रेस की राज्य सरकारों को destabilise करने के लिए तो टाइम है, लेकिन बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूखे का जो असर है, वह काफी विस्तृत है। दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, उसका 16 प्रतिशत हमारे यहां है, लेकिन धरती के जल संसाधनों का केवल 4 प्रतिशत ही हमारे पास है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सारी चीजों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। यह बहुत ही डरावनी स्थिति है, यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर हम सही कदम नहीं उठाएंगे, तो इस समस्या से निपट नहीं पाएंगे। कहते हैं कि बारिश इस बार अच्छी होगी, लेकिन अभी बारिश आने में काफी टाइम बाकी है। ऐसे समय में सरकार को जागरूक होने की बहुत ही जरूरत है। पहले इसके बारे में प्लांनिग कमीशन चिंता करता था। उसको भी अब भंग कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार चीफ मिनिस्टरों की या मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई, कितनी बार कितनी टीमों ने वहां विजिट की या मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, इसके बारे में खास तौर से सोचने की जरूरत है।

दूसरी बात है जिस पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जिस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए उसके उलट ही काम हो रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने बताया था कि 91 बड़े जलाशयों में पानी तेजी से घट रहा है। आर्थिक सर्वे में भी बताया गया था कि कृषि की विकास दर घट रही है, लेकिन उन सूचनाओं पर कोई अमल नहीं किया गया। इसके उलट सरकार ने क्या किया, एक तरफ कृषि विकास घट रहा था और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य में कमी कर दी। पेयजल और जल संसाधन मंत्रालय के बजट में 40 प्रतिशत की कमी कर दी गई। सुश्री उमा भारती जी यहां पर बैठी हैं। मुझे नहीं मालम कि जो कमी की गई है, उससे वे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। आपकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। मैंने "मनरेगा" की बात आपसे कही है मैं खासतौर से एक बात यह कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जनता को ज्यादा ही जाग्रत होने की जरुरत है और ज्यादा जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ जनता पर डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब वे 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कई बार उन्होंने कहा था कि कई बार लगता है कि भगवान हमें पानी का मोल भुलने नहीं देना चाहते, लेकिन सरकार और जनता मिलकर इस परीक्षा में खरे उतरेंगे। कोई वजह नहीं है, हम हालात का उपयोग जल संरक्षण के संसाधन के लिए न करें, लोगों को जल के मोल और हरियाली की रक्षा के प्रति सचेत करने के लिए न करें। पशुओं के लिए करुणा जगाने और अपनी सारी ताकत को गरीब किसान की भलाई में लगाने के लिए न करें। गुजरात राष्ट्र के सामने सूखे से निपटने का मॉडल पेश करेगा। मुझे नहीं मालूम प्रधान मंत्री, वे देश के सामने जो गुजरात का मॉडल पेश करने वाले थे, उस मॉडल का क्या हुआ? मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी हमेशा अपने मन की बात तो करते हैं और हमें सुनाते रहते हैं, लेकिन आज उनको लोगों के मन की

पीड़ा को सुनने की जरूरत है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए सरकार कैसे सूखे का सामना करती थी। इस सरकार ने 2009 में किसानों का लगभग 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। हमारे कृषि मंत्री और अन्य मंत्री सूखाग्रस्त क्षेत्रों की रेगुलर विजिट करते रहते थे। वहां की प्रदेश सरकारों से परामर्श करके राशियां बढ़ाई और 12वें योजना आयोग ने जल आवंटन और भजल के प्रयोग के बारे में नीति का ढांचा तैयार किया। आज राष्ट्र के लोग परेशान हैं। यह समय राजनीति का नहीं है, मेरे ख्याल से काजनीति का भी समय है, यह तो कार्य करने का समय है। ऐसे वक्त में मेरे ख्याल से जहां-जहां सूखे की स्थिति है, उन प्रदेशों से सरकार को कंसल्ट करने की जरूरत है, परामर्श करने की जरूरत है। हम भविष्य में ख्याल रखें कि अगर जब हमारी तकनीकी पहले से हमें सूचना दे देती है कि सूखा आने वाला है, तो हमें उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। मेरे ख्याल से एडवांस प्लानिंग जिस तरीके से होनी चाहिए, सरकार ने नहीं की है। उसी की वजह से आज लोग परेशान हैं। हिन्दुस्तान की जो भी महिलाएं हैं, वे खासतौर पर काफी परेशान हैं। मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ समय बाकी है, परामर्श करने के बाद सरकार इस तरह की व्यवस्था करे, ताकि जो भी लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी हल हो, समस्याएं हल हों और उनको राहत मिले। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री राम कुमार कश्यप (हरियाणा): सर, आज सदन में सूखे की बहुत ही गंभीर समस्या पर एक सार्थक चर्चा हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि भारत में पहली बार सूखा पड़ा है। पिछले दो सौ वर्षों में यहां 44 बार सूखा पड़ा है, एक अंतर्राष्ट्रीय डाटा बेस के अनुसार पिछली शताब्दी में भारत में प्राकृतिक रूप से दस आपदाओं में सूखा पड़ा है। जिनमें अभी तक साढ़े 42 लाख व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। आज देश में पानी की गंभीर समस्या है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में लोग एक से ज्यादा शादी करने पर मजबूर हो रहे हैं। एक पत्नी घर और बच्चे संभालने का काम करती है और दूसरी पत्नी पानी लाने का काम करती है। क्योंकि इन महिलाओं को कई-कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। ...**(व्यवधान)**... सर, मैंने यह अखबार में पढ़ा है। सर, विचारणीय मुद्दा यह है कि आखिर यह सूखा क्यों पड़ता है और पानी का संकट क्यों गहराया है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से मुख्य कारण समय पर मानसून का न आना है। हम आज से पचास साल पहले देखते थे कि लगातार 15-15 दिनों तक बरसात होती थी और इतनी ज्यादा बरसात होती थी कि मकानों के ऊपर भी वनस्पति पैदा हो जाती थी। आज तो बरसात ही नहीं होती है। आज मकानों की छतों पर क्या वनस्पति पैदा होगा, खेतों में ही वनस्पति पैदा नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि आज हमने वृक्षों को भारी मात्रा में काट दिया है। आज देश के विकास के लिए शहरों का शहरीकरण हो रहा है और सड़कें बन रही हैं, जिसके कारण जंगलों के पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से इसके लिए एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। मैं रेल मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले रेल बजट में रेलवे की खाली जमीन पर पेड़ लगाने का जो प्रावधान किया था, वे उसको इम्पलीमेंट करना चाह रहे हैं।

हरियाणा में जो सोनीपत-गुहाना-जींद रेलमार्ग है, यह 79 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहां मंत्री जी ने जो पेड़-पौधे लगाने का एक निर्णय लिया है, उसको मैं मंत्री जी का एक बहुत ही सराहनीय कदम कहना चाहूंगा।

[श्री राम कुमार कश्यप]

मंत्री जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी गेहूं का सीज़न है। कई बार हमारे किसान भाई खेतों में ख़रपतवार जलाने के लिए आग लगा देते हैं। जब खेतों में आग लगती है, तो वह आग लगते-लगते सड़कों तक आ जाती है। जब आग सड़कों पर आ जाती है तो सड़कों पर खड़ी हुई जो वनस्पति है, पेड़-पौधे हैं, इस आग से वजह से कितने ही कीड़े-मकोड़े और जीव-जंतु मर जाते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस आग के ऊपर भी एक जागरूकता अभियान जरूर चलाएं, ताकि किसान जागरूक हो। क्योंकि जब किसान खेतों में आग लगाते हैं, तो उससे खेतों की उपजाऊ शक्ति तो नष्ट होती ही है, साथ ही हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है।

इसके बाद मंत्री जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा जो एनएच-1 हाइवे है, इस पर करनाल से लेकर सोनीपत के बीच में हज़ारों की संख्या में ट्री गाडर्स पेड़ों के बिना खड़े हैं। उनमें पेड़ होने चाहिए थे, लेकिन उनमें पेड़ नहीं हैं। यह जो देश की संपत्ति है, जो हज़ारों की संख्या में ट्री गाडर्स हैं, इन पर भी विचार किया जाए कि ये जो ट्री गाडर्स हैं, ये खाली क्यों हैं?

मंत्री जी, मैं इसके बाद यह बात कहना चाहूंगा कि आज पीने के पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज़ हो रहा है। यदि आज मैं हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा के कई ज़िलों में पानी की कमी है और कई ज़िलों में पानी पर्याप्त मात्रा में है। जहां पानी पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर घर-घर में टूंटी लगी है। लोगों ने टूंटी के साथ-साथ सबमर्सिबल पम्प भी लगा लिए हैं। यद्यपि सबमर्सिबल पम्प लगवाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब सबमर्सिबल पम्प चलता है, तो खुला चलता रहता है और नाली में पानी जाता रहता है, ओवरप्लो हो जाता है, जिसकी वजह से तालाब ओवरप्लो हो रहे हैं। यह एक बड़ी भारी समस्या सरकार के सामने आ रही है। पीने के पानी का भी हमें संरक्षण करना है, हमें इसके बारे में भी जागरूकता अभियान चलाना है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): समाप्त कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राम कुमार कश्यप: दूसरा, खेती में भी पानी का बहुत उपयोग होने लगा है। जब से हरित क्रांति आई है, तब से ऐसे-ऐसे बीज आ गए हैं, जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज साइंटिस्ट्स को ऐसे बीज पैदा करने चाहिए जो कम पानी लें। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आज डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है, इसलिए आप डॉक्टरों की कमी को दूर करने का काम करें। जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डॉक्टर्स होंगे, तो वे रिसर्च करेंगे और अच्छे बीज पैदा करने का काम करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिंद।

डा. संजय सिंह (असम): माननीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मुझे भागीदार बनाया। अभी संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इस गंभीर दैवी आपदा पर बहुत चिंता है। हर जगह यह बोला जा रहा है कि देश में जनता सबसे ज्यादा इस सूखे से प्रभावित है। जो प्राकृतिक आपदा है, उस प्राकृतिक आपदा का सरकार, चाहे वह केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, मिलकर मुकाबला करती है और जो भी व्यवस्था होती है, उसको उस समय पर उपलब्ध कराती है। जहां पानी की कमी हो, वहां

पानी की व्यवस्था करती है, जहां जैसी भी आवश्यकता हो, उस पर लोग मिलकर, बड़े सहयोग के साथ काम करते हैं। भारत सरकार की नेकनीयती पर कोर्टस ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया है कि इस समस्या को किस तरह से नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इसको ध्यान से नहीं देखा जा रहा है, इस पर जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था नहीं हो रही है।

माननीय महोदय, पूरे देश में 12 राज्य इस समस्या से प्रभावित हैं। इन 12 राज्यों में लगभग 50 करोड़ से ज्यादा आबादी इस सूखे से प्रभावित है। अभी माननीय शरद पवार जी कहीं पर बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में कुछ इलाकों में पानी की भी समस्या है और यह समस्या इतनी ज्यादा है कि पंद्रह-पंद्रह, बीस-बीस दिनों में केवल एक दिन ही पीने के पानी की व्यवस्था हो पा रही है। वहां पर आईपीएल की भी चर्चा हुई, उसको हटाने की बात भी आई, देश में सूखे की इस गंभीरता के बारे में हर तरह से, हर स्टेप पर चर्चाएं हुई हैं। माननीय महोदय इसके लिए "मनरेगा" जो यूपीए सरकार की देन थी, जिसमें करोड़ों लोगों को काम मिला था, उस पर भी भारत सरकार की तरफ से कमेंट किया गया कि यह कांग्रेस पार्टी का स्मारक बनने वाला है। यह कहकर उस स्कीम की तमाम गंभीरता को कम करने की बात हुई है। जब तालाब खुदते थे तो किसान मजदूर तमाम तरह से काम करते थे। प्राकृतिक पानी जो डिस्चार्ज नहीं होता है, वह उसको पूरा करने का काम करता था। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्रकृति का नीचे का पानी, जो बोरिंग से हैंड पंप से या तमाम तरीकों से बाहर निकल रहा है, वह पानी बहता हुआ नदी में और नदी से समुद्र में चला जाता है। उसके recharge की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बहुत सारा construction चल रहा है, मकान बन रहे हैं, इस देश में निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनमें यह compulsory किया जाए कि जो भी घर बनते हैं, उनको permission तभी मिलेगी, जब वहां water recharging की व्यवस्था हो। आज इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। आज इस बात की आवश्यकता है।

पहले यूपीए सरकार में किसानों की ऋण माफी हुई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम उन 12 राज्यों में, जहां तमाम लोग सूखे से प्रभावित हैं, वहां के किसानों की ऋण माफी compulsory हो, वहां पर पशुओं के चारे की व्यवस्था हो, वहां पर बच्चों की फीस माफी हो, वहां पर जिन लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है, पानी की व्यवस्था तो हो ही रही है, वहां पर मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था हो, जब तक वे लोग सूखे के प्रभाव से बाहर नहीं निकल आते।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह global warming का प्रभाव है, जिससे हमारा climate disturb हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसका एक विशेष मंत्रालय बने, ताकि आने वाले समय में इसकी study हो, इसकी research हो कि हमारे climate change की वजह से जैसे सूखा पड़ा है, वैसे हो सकता है कि कल बाढ़ आए, तीसरी और कोई समस्या आ सकती है। इसकी study के लिए सरकार गम्भीरता से एक मंत्रालय बनाए, जिसमें रिसर्च विभाग हो और भविष्य के लिए, 10-15-20 साल के लिए planning हो। अगर planning के आधार पर काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि आपदा का मुकाबला किया जा सकता है तथा आपदा को tackle करने का और अच्छा तरीका सोचा जा सकता है।

[डा. संजय सिंह]

5.00 P.M.

माननीय महोदय, हमारे प्रदेश में बुंदेलखंड है। जब ऐसी आपदा नहीं भी होती है, तब भी बुंदेलखंड में पानी की कमी है। हमारे यहां पलायन भी होता है। भारत सरकार में भी और प्रदेश सरकार में भी बहुत तरह की स्कीमें और योजनाएँ बनती हैं, लेकिन उनका implementation कितना होता है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। कैसे वहां पर इसकी व्यवस्था बनाई जा सके, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बुंदेलखंड भी उसी तरह से प्रभावित है, जैसे हमारे तमाम राज्य प्रभावित हैं।

माननीय महोदय, मैं चाहूँगा कि प्रदेश सरकार से विशेष तौर से इसके लिए आग्रह किया जाए, ताकि वहां के लिए ऐसा प्रोजेक्ट बने कि वहां गम्भीरता से पानी की व्यवस्था के लिए प्रयास किया जाए और वहां पर भी ऋण माफी के लिए सरकार विशेष तौर से कोई ऐसा पैकेज तैयार करे, जिससे इन सूखाग्रस्त राज्यों में इसकी व्यवस्था हो सके।

माननीय महोदय, मैं समझता हूँ कि आज इस गम्भीर समस्या के ऊपर संसद में सभी लोग, सभी राज्यों के लोग, हमारे सभी जन-प्रतिनिधि उतने चिंतित हैं, जितना देश में इसके प्रकोप से सारी जनता चिंतित है। मैं चाहता हूँ कि सदन जिस गम्भीरता के साथ आज चर्चा कर रहा है, सरकार भी उतनी गम्भीर हो कर इसके लिए विशेष पैकेज तैयार करे। वहां पर लोगों की ऋण माफी के लिए मैं दोबारा जोर देता हूँ कि आप उनका ऋण माफ करें और उनको जो भी सुविधा पहुँचाई जा सके, वे पहुँचाएँ, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के. सी. त्यागी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, चूँकि मेरा समय पहले हमारे नेता ले चुके हैं, इसलिए मैं संक्षेप में कुछ आवश्यक बातें आपके जरिए मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। शरद पवार जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज राजनीति करने का दिन नहीं है, यह आपदा है और इससे हम सबको मिल कर निपटना है। बहुत अच्छा होता, अगर यहां वित्त मंत्री भी होते, गृह मंत्री भी होते, Food and Consumer Affairs Minister भी होते, कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं, Commerce Minister भी होते और मुझे प्रसन्नता है कि Rural Development Minister भी यहां बैठे हैं, क्योंकि यह किसी एक विभाग से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। कृषि मंत्री की सीमाएँ हैं, Rural Development Minister के जिम्मे भी बड़ा भारी काम है। वित्त मंत्री होते, जिनको धन मुहैया कराना है, Disaster Management के लिए गृह मंत्री होते, जिनको इसे देखना है और जिस तरह से वहां पर PDS का सिस्टम effective होना चाहिए था, उसके लिए Food and Consumer Affairs Minister होते, तो अच्छा होता। खैर वे यहां नहीं हैं।

सर, मैं तकलीफ के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। जो काम हम नहीं कर रहे हैं, वह हम अदालतों से करा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वहां IPL नहीं होगा। मेरे दोस्त, राजीव शुक्ल जी शायद यहां पर नहीं हैं। उनकी और पवार साहब की चिंताएँ मुझे कष्ट देती रहती हैं। कल यह आदेश हुआ है कि वहां पर पहली मई के बाद मैच नहीं होंगे।

सर, मुझे नीरो की याद आ गई, जो रोम में बांसुरी बजाया करता था। एक बार जब रोम में बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, तो उसने एक भोज आमंत्रित किया। उसने, सूखे की वजह से जो लोग मर गए थे, उनको निकाल कर, रात में उनकी हड्डियों को जलाया और उस भोज में उजाला

किया गया। उस भोज में राजनेता, पत्रकार और सिविल सोसाइटी के लोग आमंत्रित थे। आज आईपीएल देखने का हमारा जो नज़रिया और हमारे जो इरादे हैं, उन्हें देखकर मुझे लगता है कि रोम के नीरो के जो बाराती थे, हम लोग भी उन्हीं में शामिल हो गए हैं। हमारी संवेदनाएं इतनी मर गई हैं, इतनी कमजोर हो गई हैं।

सर, मैं अन्य किसी विषय पर जाऊं, इसके बजाए मैं मंत्री जी को चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): हमारी एक समस्या है कि आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागी: मैंने इसके लिए पहले ही आपसे माफी मांग ली है। यदि आप कहेंगे, तो मैं कुछ कहे बगैर ही बैठ जाऊंगा। ...**(व्यवधान)**... I am a very obedient Member.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आपके पास पांच-छः सुझाव हैं। मेरा निवेदन यह है कि आप उनमें से केवल एक-दो बता दीजिए, बाकी मंत्री जी को लिखित में सौंप दीजिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागी: मैं बोलता ही नहीं हूं, लिखकर ही भिजवा दूंगा। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): आप बोलिए, बोलिए।

श्री के. सी. त्यागी: सर, यह इतना महत्वपूर्ण मसला है। इस तरह आप इस पर समय की सीमा क्यों लगा रहे हैं?

श्री भूंपिदर सिंह: सर, सूखे के बारे में त्यागी जी को बोलने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय): ठीक है, आप बोलिए।

श्री के. सी. त्यागी: सर, इस मुल्क में 30-40 सालों में कोई काम अच्छा हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि हम पार्टियों के दायरों में इतने अधिक बंध गए हैं कि हमारी यह धारणा बन गई है कि अगर उमा जी कोई अच्छा काम करेंगी, तो हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बीजेपी की हैं।

महोदय, अगर आज मनरेगा नहीं होता तो क्या होता! मैं एनएसी की चेयरमैन का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मनरेगा आया। आज हिन्दुस्तान के उस इलाके में भी रोजगार मिला है, जिससे लोगों के पलायन का काम रुका है। मैं मनरेगा का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

मनरेगा के अंदर केवल पांच प्रतिशत परिवारों को 50 दिन का काम मिला है। सूखाग्रसित वर्ष में मनरेगा में 50 दिन से भी कम दिन का रोजगार मुहैया करवाया गया है। मनरेगा के तहत सरकार ने इस वर्ष 3,800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उमा जी जहां से आप आती हैं, उससे ज्यादा तकलीफ में आज कोई राज्य नहीं है। अभी लातूर का जिक्र हो रहा है। On record, बुंदेलखंड से 66 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। मैंने घास की रोटी खाते हुए वहां के किसानों और मज़दूरों

[श्री के. सी. त्यागी]

के फोटो देखे हैं। घास की रोटी खाने के बाद दिन भर भूख नहीं लगती है। किसान दिन भर जमीन की तरफ देखता रहता है और खेत में आई हुई दरारों उसके चेहरे की झुर्रियों जैसी हो गई हैं। लेकिन मानवीय संवेदनाओं का यह हाल है कि देश के अंदर कोई काम नहीं रुकता है।

मंत्री महोदया जी, मैंने आपके लिए कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन ये सुझाव आलोचनात्मक नहीं हैं। राज्यों में जाकर आप हेडमास्टर की तरह जो सबको डांटते हैं, वह बंद कीजिए। यह संकट का समय है। राज्य भी आपकी मदद करें, दूसरे मंत्रालय भी आपकी मदद करें और हम सभी लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के और आपके साथ खड़े हैं, तभी इन समस्याओं के समाधान होंगे।

सबसे पहले मेरा कहना यह है कि किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। ये जो पीले अखबारों वाले हैं, जैसे Business World, Business Standard, Economic Times, जिन्हें आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, वे हमारे कर्जे के खिलाफ बहुत लिखते रहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्जे आपने माफ किए हैं। यूपीए की सरकार ने भी 3-4 लाख करोड़ रुपये की कीमत के कई राहत पैकेज दिए। आज किसानों पर 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के कर्जे हैं। आप उन्हें माफ करने के लिए अपना मन बनाइए। इसमें ये भी मदद करेंगे और हम भी मदद करेंगे।

महोदय, आज वहां हर जगह मवेशी मरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको खिलाने के लिए उनके पास चारा नहीं है। Rural Affairs Editor of the Hindu के एक पत्रकार, श्री पी. साईनाथ की एक किताब मैंने देखी है कि जब सूखा पड़ता है, तो किस तरह कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं और उन लोगों के मजे आ जाते हैं। मुम्बई के बाजार में चीनी 40 रुपये किलो से भी ज्यादा दाम पर बिक रही है। वहां पल्सेज़ के दाम दोगुने हो गए हैं। इसमें दो-चार hoarders के नाम भी आए हैं। जब इन्दिरा गांधी जी व्यापारियों पर अंकुश लगाती थीं, तो कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते थे कि व्यापारियों पर क्यों अंकुश लगा रही हैं। अंकुश व्यापारियों पर नहीं, भ्रष्ट व्यापारियों पर लगाए जाते हैं, जो hoarders होते हैं, marketeers होते हैं, profiteers होते हैं और जो खाने के सामान के ब्लैक पर बेचते हैं। यह सूखा हम लोगों के लिए तो नरक है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोगों के लिए यह वरदान न बने, इसका इंतजाम भी आपकी सरकार को करना होगा।

सर, अब वक्त आ गया है— मोदी जी की सरकार कई नूतन और अच्छे प्रयोग करती है मैं उसका विरोधी नहीं हूँ लेकिन वे साहस दिखाएँ। जैसे उन्होंने गंगा के लिए किया है, वैसे ही disaster management का एक अलग मंत्रालय बनना चाहिए। यह किसी के अन्डर में न रहे। कभी यह कृषि मंत्रालय में चला जाता है और जब यहां से कोई ताकतवर मंत्री गृह मंत्री बनता है, तो यह गृह मंत्रालय में शिफ्ट हो जाता है। तो जो shuttle cock की तरह यह इतना बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय घूम रहा है, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से बाकायदा ऊँचे पैमाने पर फंड्स का एलोकेशन होना चाहिए। मनरेगा के अंदर, जो लाइफलाइन है— जब हम जनता पार्टी में थे, तब मोरारजी भाई ने 'काम के बदले अनाज योजना' शुरू की थी। मेरे मित्र श्री रवि शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। ये उस समय एक युवा नेता थे। ...**(समय की घंटी)**... इसलिए 'काम के बदले अनाज' की तर्ज पर कम से कम 150 दिनों का काम मनरेगा के तहत उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसानों के बच्चे, जो पढ़ाई के लिए कर्जा लें ...**(व्यवधान)**... उनका कर्जा माफ होना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

श्री के. सी. त्यागीः सूखे से पीड़ित किसानों को मुफ्त में बीज, खाद और खेती से जुड़ी अन्य सुविधाएँ ...**(समय की घंटी)**... बस, दो चीज़ें और हैं, सर। किसानों को मुआवजे की राशि का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। अभी कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हैं। National Food Security Act के तहत सूखा पीड़ितों को PDS से राशन उपलब्ध कराया जाए। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई है। मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन रवि शंकर जी, 20 प्रतिशत से भी कम किसान बीमा कराते हैं। आपकी योजना अच्छी होगी, लेकिन आपकी बीमा योजना उस तक नहीं पहुँची है। राजस्थान के किसानों को बीमा का पैसा मिला है, राहत कोष के रूप में, किश्त के रूप में, उससे 6 गुणा ज्यादा जो प्राइवेट प्लेयर्स बीमा कम्पनीज़ हैं, वे खा गई हैं, वे ले गई हैं। तो जो बीमा योजना है, उसका इस्तेमाल गरीब किसानों के लिए हो, बजाए जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आपने FDI में भी 49 परसेंट कर दिए हैं, उसके भी नतीजे आ रहे हैं, उनके लिए न हो।

सर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए दो बातों पर फिर स्ट्रेस देना चाहता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग मंत्रालय बने। मोदी जी नूतन प्रयोग करने के आदी हैं, तो एक प्रयोग यह भी करें। दूसरा, किसानों के सारे कर्जे माफ हों। वरना, जैसे महलों की रोशनी तब तक सलामत है, जब तक झुग्गी में चिराग जलता है। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's all.

श्री के. सी. त्यागीः झुग्गी का चिराग जलना बन्द हुआ, तो महलों की रोशनी सलामत नहीं रह पाएगी। उपसभापति महोदय, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Shri Balvinder Singh Bhunder.

श्री हुसैन दलवईः सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

श्री हुसैन दलवईः सर, मैंने भी इस पर बोलने के लिए नोटिस दिया था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

श्री हुसैन दलवईः सर, मैंने भी सूखे पर बोलने के लिए नोटिस दिया था। मेरा नाम लिस्ट में है, लेकिन मेरा नाम आपने नहीं लिया। ...**(व्यवधान)**... मुझे थोड़ा तो टाइम दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is correct that you have given notice, but your party has not forwarded it.

श्री हुसैन दलवईः ठीक है, सर। लेकिन मैंने नोटिस तो दिया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मैं क्या करूँ?

श्री हुसैन दलवईः आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You sit down. After disposing all the names, let me see.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब)ः सर, यह जो सूखे की प्रॉब्लम है, यह ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है और यह प्रॉब्लम इंडिया की ही नहीं, बल्कि यह वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। मैं पिछले दिनों अमेरिका-कनाडा गया था। वहां हफ्ते में एक दिन पार्कों को पानी अलाऊ किया गया था। कैलिफोर्निया में चार सालों से बारिश नहीं हुई है। मैंने देखा है कि वहां सूखा पड़ा हुआ है। इंडिया में यह जो प्रॉब्लम है, सदियों से है। हमारा यह देश किसानों का देश है। यहां कभी 80 परसेंट लोग खेती करते थे, अब वे 60 परसेंट के करीब आ गए हैं। सूखे की जो प्रॉब्लम है, बार-बार इसके फिगर देना, किसी से कहना कि ऐसा हो गया, तो मैं फिगर में नहीं जाऊँगा। मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि यह जो सूखा बार-बार आता है। इसके लिए हम पहले से ही इंतजाम करें। एक तो कुदरत की बात है, जिसका हमारे पास तो कोई इंतजाम नहीं है। नेचर का तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन हमारे पास जो साधन हैं, जैसे रेन वॉटर है, ग्राउंड वॉटर है, उसको कैसे सेव करना है और जब ज्यादा बारिश हो जाती है, तब बाढ़ आ जाती है, उससे कैसे सेव करना है?

ताकि जो बुरे दिन हैं, जब ड्राउट आता है, तब उसके लिए वह काम आ सके। इसके लिए मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ दो-तीन मिनट ही हैं। पहले तो मैं यह बात कहूंगा कि जो सब्सिडी है, वह उसको देनी चाहिए कि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है, तो कैसे कम से कम पानी से ज्यादा पैदावार ली जाए। सिंप्रकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, इस पर ज्यादा से ज्यादा 80 परसेंट तक सब्सिडी देनी चाहिए। सेकंड, जो हमारे तालाब वगैरह हैं, जिसके बारे में सभी ने कहा है, उनके लिए मैक्सिमम सब्सिडी देनी चाहिए। यह पूरे कन्ट्री में, हर स्टेट में हो। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टेट वाले कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा ज्यादा पानी यूज़ करता है। हमारी प्रॉब्लम है कि हम जो राइस और व्हीट पैदा करते हैं, कभी तो हमारे लिए कहा जाता है ये बहुत अच्छे स्टेट हैं, लेकिन अब यह हमारी प्रॉब्लम बन गई है और कन्ट्री भी कहता है कि आप क्या बीजते हैं? हमारे शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार को एक दिन का व्रत रखिए। तब हमने जब लाल पैदा किया तब तो हमारा "जय जवान" था, "जय किसान" था। अब हमारा किसान जब मुश्किल में आ गया और सुसाइड कर रहा है, तो कोई हैल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए एक तो सिंप्रकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम पर ज्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देना चाहता हूं। हमारी जो क्रॉप्स हैं, वह राइस और व्हीट के बजाए ऑयल सीड और पल्सेज भी हैं। हर साल हम इतना इम्पोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे किसानों को सब्सिडी दी जाए और कोशिश की जाए कि डाइवर्सिफिकेशन हो, ताकि हमारा पानी भी बचे। तीसरा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, वह बहुत ज्यादा नीचे चला गया है, रिवर वाटर पहले ही हमारी स्टेट से 76 परसेंट बाहर चला गया है। इसलिए जो मनरेगा स्कीम है, उसको इसके साथ लिंक करना चाहिए, ताकि जो मनरेगा का पैसा है, कैसे उसको इरिगेशन सिस्टम के साथ जोड़ें, ताकि हम उसको सेव कर सकें। चौथा, जो त्यागी जी ने कहा है, हम वह कहना चाहते हैं कि जो कर्जा है, मल्टीनेशनल कम्पनियां तो हमारे बैंकों के खरबों रुपए लूटकर ले गईं। लेकिन किसानों के पास तो तकरीबन सौ करोड़ का कर्जा होगा। एक मल्टीनेशनल कम्पनी के कर्जे के बराबर भी नहीं होगा। इसलिए अब समय आ गया है और अगर किसान को बचाना है तो उनके कर्जे को माफ करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा यह सूखा पड़ा है, अगर किसानों

का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। एक सूखे से वह किसान दो-तीन साल तक खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसका कर्जा भी माफ करें तथा नेक्सट क्रॉप के लिए, सीड के लिए और वस्तुओं के लिए किसानों को लोन बगैर इंटरेस्ट के दिए जाएं। मेरे ये तीन-चार प्वाइंट्स हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहता था। हमारे पंजाब की तो कहीं गिनती नहीं है। हम अपना ग्राउड वाटर यूज़ करते हैं, अपना कैनाल वाटर यूज़ करते हैं और देश को हम पैदा करके देते हैं, लेकिन हमारे यहां बारिश 40 परसेंट ही हुई है। इसलिए हमने बिजली ज्यादा दी, पानी ज्यादा दिया, देश के लिए हमने अनाज पैदा कर दिया। लेकिन हमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसके लिए ड्रिप सिस्टम में और सिंप्रकल सिस्टम में सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे देश के बाकी हिस्से में ड्राउट के लिए देते हैं, ताकि उसकी भरपाई हो सके। सेकंड, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम चाहते हैं, हमारे लिए बीजों वगैरह के लिए सब्सिडी दी जाए, ताकि हम और क्रॉप डेवलप कर सकें। इसलिए ये हमारे सजेशंस हैं, माननीय मंत्री जी इनका ध्यान रखेंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Darda, are you speaking?

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA (Maharashtra): Yes, Sir, but why are you asking me whether I am speaking or not?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I asked you because there is no time left with your party.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: But I have already given notice and my name is there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is there, but some Members from your party have taken more time. But you can take four-five minutes.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा: सर, आज हम लोग एक अत्यंत गंभीर विषय पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कभी मानूसन पर चर्चा करते हैं, कभी सूखे पर चर्चा करते हैं, कभी बारिश पर चर्चा करते हैं, कभी ओलावृष्टि पर चर्चा करते हैं। हम लोग समय-समय पर अलग-अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। क्या सचमुच हम लोग इस विषय पर इतने गंभीर हैं कि इसके लिए एक ऐसा समग्र प्लान बनाया जाए, जिससे हम पूरे देश के अंदर आने वाली जो स्थितियां हैं, उनसे लड़ सकें? पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं सूखा पड़ा है या कहीं पीने के पानी की किल्लत हो रही है, मगर आज एक ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। देश के अंदर करीब-करीब दस राज्य ऐसे हैं, जो पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। कई ऐसे भी राज्य हैं, जिस राज्य में काफी बारिश होती है, जैसे नॉर्थ-ईस्ट में ऐसे राज्य हैं, इसके बावजूद भी वहां पर पानी का बहुत अकाल है। देश में मानसून की स्थिति तीन साल में बहुत खराब हो गई है और इसके कारण महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा भयावह स्थिति निर्मित हो गई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र की हालत बहुत खराब है। हम लोग कई वर्षों से किसानों की समस्या को लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं, पर इस साल करीब-करीब 3,500 किसानों ने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में सबसे गंभीर बात यह है कि लातूर के अंदर ऐसे विद्यार्थी थे, जो पानी लाने गए और वहां पर वे डूब गए। एक परिवार के दो बच्चे थे, वे डूब गए। यहां तक हुआ है कि वहां पर एक एमएलए

[श्री विजय जवाहरलाल दर्डा]

का भाई कुएं से पानी लेने के क्रम में डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। विदर्भ के अंदर एक हसबैंड एण्ड वाइफ के साथ भी इसी तरह की घटना हुई। यहां तक हो रहा है कि पानी के लिए रात-रात भर लाइनें लगी रहती हैं। वहां पर धारा 144 लगाई गई। वहां पर मांद्रा सूख जाने के कारण हर रोज 25 लाख लीटर पानी नीरस से ट्रेनों से आ रहा है। वहां पर परिस्थितियां इतनी गंभीर हो चुकी हैं कि वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर की situation निर्मित हो गई है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए एक लांग-टर्म प्लानिंग की आवश्यकता है। आज हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो बीयर की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री, पेप्सी, कोक, कोका कोला की फैक्ट्री को पानी दिया जा रहा है और दूसरी तरफ किसान सिंचाई तथा पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। क्या यह संभव नहीं है कि जब तक हम लोग इस समस्या से उबर न जाएं, तब तक इनको पानी नहीं दिया जाए? आज वहां पर करीब-करीब 80 प्रतिशत उद्योग-धंधे बंद पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल्स में आईसीयू बंद पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में वहां के जो चार लाख मजदूर थे, वे वहां से बाहर जा चुके हैं। करीब-करीब 34 हजार मजदूर ऐसे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। वे लौट कर भी नहीं आए हैं। इन सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को बहुत गंभीर होना चाहिए। पानी के संकट से निपटने के लिए देश के अंदर धीमी सिंचाई की जो परियोजनाएं चली हैं, मैं उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाया था। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सूखे के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है, विदर्भ और मराठवाड़ा में अकाल पड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर करीब-करीब 3,50,000 किसानों ने आत्महत्या की। वह आत्महत्या की बात और थी। किसानों के लिए जो पैकेज की बात हुई थी, वह अभी तक नहीं दिया गया है। पिछले सत्र में भी मैंने माननीय कृषि मंत्री जी से विनती की थी कि वे विदर्भ और मराठवाड़ा में आएं, वहां का दौरा करें और वहां की स्थिति को देखें। पर, हमें अभी तक कोई खबर नहीं है कि वहां पर कौन-सी टीम आई, वहां पर कौन गए। सरकार ने पिछले बजट में 86,500 करोड़ की राशि पूरे देश में सिंचाई परियोजना के लिए मंजूर की थी, लेकिन अब तक सिंचाई परियोजना के टारगेट का सिर्फ 28 फीसदी ही कंप्लीट हुआ है और Accelerated Irrigation Benefit Scheme का किसी भी प्रकार का फायदा महाराष्ट्र को नहीं मिला है। इस परिस्थिति के कारण वहां पर किसान अपना पशु धन बेचने के लिए विवश हो गए हैं। वे अपने पशु धन को कौड़ियों के भाव में बेच रहे हैं। वहां पर पशु धन बेचने के लिए कैम्प लगे हैं।

ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरी सरकार से विनती है कि वह उसके लिए कुछ करे। शरद यादव जी ने जो बात उठाई, वही बात मैंने इससे पहले भी उठाई थी और अब मैं फिर उसको उठाना चाहता हूँ कि देश की नदियों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पानी राष्ट्रीय विषय होना चाहिए, न कि यह राज्यों का विषय हो। आज हम देख रहे हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए इस ढंग से लड़ रहा है, जैसे दो दुश्मन और उसके सिपाही आपस में लड़ते हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं एक-दो मिनट और लेना चाहूँगा। मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ और वॉर्न करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि इस पर गृह युद्ध हो जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी। महोदय, इसके साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए— सर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नासिक जिले में एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएँ में उतरी, क्योंकि उसके यहां बारात में ज्यादा लोग आने वाले थे। आज हमारे देश के अंदर यह परिस्थिति निर्मित हो गई है। हम एक तरफ मार्स पर पहुँचने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर हमारी

यह स्थिति है। ...**(समय की घंटी)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, आप जब तक नहीं थे, तब तक ...**(व्यवधान)**... यानी, लोगों को बोलने का मौका मिल रहा था, मगर अब ...**(व्यवधान)**... सर, मैं अपनी बात का अंत भी करना चाहता हूँ। मैं सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ ...**(व्यवधान)**... सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः श्री संजीव कुमार ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, मैं गन्ने के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजीव कुमार (झारखंड): सर, मैं झारखंड से हूँ और झारखंड इस आपदा से worst affected है। ...**(व्यवधान)**... सर, झारखंड पर आपकी कृपा दृष्टि बराबर रही है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप पांच मिनट लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजीव कुमारः आप सात मिनट कर दीजिए, सर। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, मुझे एक मिनट और दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; you have taken more time. ..*(Interruptions)*.. I have called him.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called him.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः महाराष्ट्र के बारे में माधव चिताले की अध्यक्षता में बनी एक कमिटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि जहां-जहां पर गन्ने की क्रॉप होती है, उसके नीचे वह ज्यादा पानी खींचता है, उसके लिए क्रॉप पैटर्न बदलना चाहिए। आप कृपा करके उस पर ध्यान दें। किसानों के ऊपर जो कर्ज है, आपने उद्योगों की जिस प्रकार से restructuring की है, उसी प्रकार उनकी भी restructuring की जानी चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद, सर।

श्री संजीव कुमारः सर, देश में लोहा, कॉपर, कोल और अन्य माइंस का जितना रिज़र्व है, उसमें झारखंड सबसे ज्यादा देता है, लेकिन आज झारखंड की स्थिति ऐसी है कि वहां लोग बूँद-बूँद पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं।

मैं आज सुबह शरद पवार जी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि झारखंड में इस सूखे से जितने लोग affected हैं, उनकी संख्या 3 करोड़ 17 लाख है, जबकि झारखंड की टोटल आबादी करीब 3 करोड़ 30 लाख है। इसका मतलब यह है कि झारखंड में लगभग सभी लोग पानी के लिए परेशान हैं और वहां की स्थिति देश में सबसे ज्यादा भयावह है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इस ओर पिछली बार भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और उन्होंने सदन में जवाब भी दिया था। मैंने बताया था कि वहां पिछले साल खरीफ, रबी और दूसरी फसल बिल्कुल बरबाद हो गई है। वहां नदी, डैम, झील, तालाब, कुएँ आदि सब

[श्री संजीव कुमार]

सूख गए हैं। तब मंत्री जी ने बहुत कृपा की थी और उन्होंने झारखंड में एक टीम भेजी थी, जो यह assess करने गई थी कि वहां क्या सिचुएशन है और कितना डैमेज हुआ है। लेकिन बहुत दुःख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमें किसी भी किसान से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि वहां पर आज तक किसी को कोई मदद मिली हो।

महोदय, दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि अभी झारखंड की स्थिति ऐसी है कि वहां के टोटल 24 जिलों में से 22 जिलों को सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, वहां लोगों के जानवर मर रहे हैं और मैं यह पूरे सदन को दिखाना चाहता हूँ कि यह आज का फोटो है। यह बोकारो स्टील सिटी के नजदीक बसे एक गांव का फोटो है, जहां पर एक ट्रक बालू लेकर जा रहा था और उस ट्रक के बालू में से जो पानी की बूँद टपक रही थी, उसको लोग बाल्टी और गिलास में लेकर पी रहे थे। जो राज्य सबसे ज्यादा लोहा देता है, जो राज्य सबसे ज्यादा तांबा देता है, जो राज्य सबसे ज्यादा अल्युमीनियम देता है और जो राज्य सबसे ज्यादा खनिज देता है, वहां की आज यह स्थिति है।

महोदय, कोयलांचल, जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां की स्थिति बहुत भयावह है और मैंने इस सदन को बार-बार यह बताया था कि open-cast mines में या कोयला खनन के दौरान जो पानी निकलता है, उसको दामोदर नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन आज तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी कि कोयला खनन के दौरान जो पानी निकलता है, उसके लिए वॉटर फिल्ट्रेशन या कोई और संयंत्र वहां पर लगाया जाए, ताकि इस तरह की स्थिति में उस पानी को संचित करके लोगों तक पहुंचाया जाए।

महोदय, आज कोयला मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं, मैंने बार-बार यह आग्रह किया था कि Corporate Social Responsibility Fund से कोयलांचल क्षेत्र में जो काम होना चाहिए, वह किसी नेता के स्कूल-कॉलेज खोलने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए नहीं, बल्कि तालाब बनाने के लिए या नदी में पानी संचित करने के लिए या कोई water reservoir बनाने के लिए खर्च करना चाहिए, लेकिन मैं इस सदन को बहुत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि मैंने बार-बार गांवों के सरकारी तालाबों को रिकमंड किया कि उन्हें Corporate Social Responsibility Fund से बनाया जाए, लेकिन तीन साल हो गए हैं, आज तक सिर्फ चार या पांच तालाब ही बने हैं। महोदय, कोयलांचल के अलावा कोलहान, जहां पर हमारी जादूगोड़ा माइन्स हैं, यूरेनियम माइन्स हैं, वहां की स्थिति यह है कि एक तो वहां पर पानी की कमी है और जो पानी है भी, जब यूरेनियम लीक करता है तो वहां से जो pollutant radioactive substances निकलते हैं, वे हमारे जल, जंगल और जमीन को खराब करते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह बात हमारी किसी agency ने नहीं बतायी है, हमारे Atomic Energy Commission ने नहीं बतायी है, बल्कि अमेरिका के एक पेपर में छपी है। मैंने यह बात सदन में उठायी थी। एक तो वहां पानी की कमी होती है और जो पानी है भी, उसको इस टाइप के खनन से नुकसान पहुंचता है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर)** *पीठासीन हुए*]

मैंने इस बाबत प्रधान मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी थी। मैंने सदन में ज़ीरो ऑवर में भी यह सवाल उठाया था, लेकिन न तो उसका कोई जवाब आया है और न ही उस क्षेत्र में कोई कदम उठाया गया है।

महोदय, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो संथाल परगना क्षेत्र है, वहां भी स्थिति बहुत भयावह है। वहां पर जो कोल कम्पनियां हैं, चाहे सीसीएल हो या ईसीएल हो, Corporate Social Responsibility Fund से उनको चाहिए था कि गांवों में, जहां पर पानी की कमी है, क्योंकि खनन के दौरान पानी बहुत अधिक बरबाद होता है, इसलिए मैंने बार-बार इस सदन को यह बात बतायी थी और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि Corporate Social Responsibility Fund से गांवों में तालाब, डैम, झील आदि के रख-रखाव की व्यवस्था होनी चाहिए, कुएं खोदे जाने चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि कोयलांचल या दूसरे क्षेत्रों में, जहां पर कोयला निकाला जाता है या खनन किया जाता है, वहां पर 900 फुट तक गहरा खोदा जाता है, लेकिन बोरिंग से या दूसरे किसी कारण से वहां पर पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैंने दो-तीन मिनट के लिए परमिशन ली थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): इसीलिए मैं आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं।

श्री संजीव कुमार: मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि पहले तो कृषि मंत्री जी ने वहां पर जो टीम भेजी थी, मैंने उनका ध्यान भी आकर्षित किया था, उस टीम की रिपोर्ट के बाद भी, पिछले साल जो सूखा पड़ा था, आपने आश्वासन दिया था और जो टीम झारखंड गयी थी, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि किसी किसान को कोई फायदा हुआ हो। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि झारखंड worst-affected है, वहां पर लगभग सभी लोग affected हैं, इसलिए झारखंड के सभी किसानों का ऋण माफ कीजिए। हम लोगों को यहां पर इस technicality में नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा State subject है और कौन सा Central subject है? वहां शराब की बिक्री तो धड़ल्ले से चल रही है। मैं यह चाहता हूं कि हर आदमी को इस technicality से ऊपर उठना चाहिए कि यह State subject है या Central subject है। झारखंड में अविलम्ब पानी पहुंचाया जाए क्योंकि हम पूरे देश को सबसे ज्यादा कोल और मिनरल से compensate करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you very much. Now, Natchiappanji. You are not speaking. ...(*Interruptions*)... You would not speak. Okay. Now, Mr. A.V. Swamy.

SHRI A. V. SWAMY (Odisha): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I come from Odisha and live in a place which has supplied rice and food during Bengal famine. Everybody may have known this that the area, from which I come, is now nationally known as the worst place from where about three lakh people migrated. An area, from where food was being supplied to a famine-affected area, is now subjected to migration of three lakh people and that area is very well-known as Kalahandi. I have lived there for forty years now. I am an engineer by profession. I am not talking nonsense about local issues and social responsibility.

Sir, in 1949, 50 per cent of the supplementary irrigation was in Kalahandi area was through the indigenous technology that they were making. They had the technology to conserve water. And the manner in which water was stored was supplementing the effort whenever there was a drought situation or something like

[Shri A. V. Swamy]

that. Today, what has happened to that? As of now, twelve districts are affected by drought and scarcity of water. Previously, it was a drought prone area. I am a Member of the Committee on Water Resources. I have warned about it more than once. We have forgotten one thing. The traditional knowledge, which the people were using to manage their affairs, is ignored. It is sad. Even in this severe drought throughout the country, if you go to the interior villages, you will find that water is being stored for drinking purposes through indigenous technology. Friends, I wanted to say that water conservation is not merely structural; it is ecological. It is only the local people who know how to maintain the balance and what type of structures you need. Friends, I have got some specific suggestions to make out of my own experience with the tribals who know how to store water and how to use it. I was an engineer fifty years ago. I used it as a small background to understand whatever was happening. Whenever you plan a project with modern technology and knowledge, please also assess the local and indigenous technology that is there. You undertake an investigation into what damage you are doing to that technology plus the confidence that the people have. You suggest a technology which is beyond their competence and comprehension. You take modern technology there and ask them to solve the problem. This will not work.

Another dangerous thing which I want our hon. Minister to know about is this. The Government of India has assessed our water resources. Sir, I want two more minutes. Everybody must know about this danger. Because there is water scarcity, out of desperation, people are going in for deep tubewells and the rate at which the Government is asking ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): I request for silence in the House, please.

SHRI A. V. SWAMY: Sir, I need half a minute more. I am concluding it. I would suggest to the MPs to go through the *Dying Wisdom* written by the Centre for Science and Environment (CSE). You should read that book. It will give you new ideas as to how to use the local knowledge and how to make it adjustable to the present day needs. If we forget this, we are going to face a danger. I am inspired by my friends in the Ministry of Water Resources. Even now desperately the Odisha Government is also doing it. There is no water for somebody to dig tubewells. There is only little water left below the surface of the earth. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you very much. Dr. T. Subbarami Reddy. Only two minutes for you. Please put your questions.

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, इसके बाद बिल लिया जाएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): वह बाद में होगा। पहले रेप्लाई हो जाए, इसके बाद में क्या होगा, हाउस जो चाहेगा, वही होगा। रेड्डी जी, आपके पास दो मिनट हैं।

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I know that all of us are very much tired. I only want to bring to the notice of the Government two points. Today, on the one side we are suffering from heavy floods, and on the other side, we are suffering from drought. Of course, this year we are suffering from unprecedented drought in States like Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh and Telangana. Even in important river flowing States there is drought. Now, the hon. Minister, Sushri Uma Bharati, is here. She is a very dynamic Minister. She has taken up the issue of connecting rivers with a challenge. What she must do is this. When floods come, the water is going into the sea. The Government must make an effort to see that water doesn't go into the sea and it must be preserved. The Government of India should make efforts to preserve water in the rainy season. Nobody has brought this point to your notice. It is very important. In other words, if you really want to solve the drought situation, on the one side the Water Resources Minister, on the other side the Rural Development Minister, both the Ministers in coordination with the Home Minister should be able to do it.

Therefore, in conclusion, I would like to say that every district in Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Bundelkhand in U.P., is suffering from drought. I want to know from the hon. Minister what is the future plan to tackle the drought situation? How are you going to solve it in the long run and short run? That is all. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Thank you. Now, the hon. Minister.

सुश्री उमा भारती: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई है। हम लोग यहां बैठे हैं, हमें यहां AC की सुविधा है और पीने का पानी भी आराम से मिल रहा है। हम सब संवेदनशील लोग हैं और अच्छी तरह से अवगत हैं कि देश की लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आबादी गर्मी की मार झेल रही है और उसके सामने पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। हम इस संकट से बहुत पहले से अवगत थे। **...(व्यवधान)...**

एक माननीय सदस्य: सर, डा. नजमा ए. हेपतुल्ला जी का नाम आ रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): We will change it. इसको बदला जाएगा। छोटी-मोटी गलतियां तो आप माफ कर दीजिए।

सुश्री उमा भारती: सर, इसको चेंज़ करा दीजिए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): प्लीज़, आप सुनिए।

सुश्री उमा भारती: सर, इस पर कृषि मंत्री जी को सम्पूर्ण जवाब देना है और उन्होंने जवाब की पूरी तैयारी की हुई है। मेरा भी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप भी सुनने की तैयारी में रहिएगा। मुझे केंद्रीय जल आयोग ने आज जल उपलब्धता की जो रिपोर्ट दी है, वह यह है कि एक बार सूखा 2004 में आया, दूसरी बार सूखा 2009 में आया और अब 2014 से इसकी निरंतरता बनी हुई है। इस साल 2016 में 91 जलाशयों में 34.8 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। हमारे जो केंद्रीय जल आयोग द्वारा 91 मॉनिटर्ड वाटर बॉडीज़ हैं, बड़े reservoirs हैं, उनमें 45.1 बिलियन क्यूबिक मीटर औसत मात्रा थी। इस हिसाब से इस साल 2016 में इन जलाशयों में जो अभी जल उपलब्ध है, 11 बिलियन क्यूबिक मीटर कम है। यह केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है। अभी सदन में जो बहस चली, उसी दरम्यान एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है, मैं उसको पहले contradict कर दूं, मतलब उसका जवाब दे दूं।

विजय जी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने एआईबीपी में महाराष्ट्र को पैसा ही नहीं दिया, जबकि महाराष्ट्र की स्टोरी यह है कि हमने महाराष्ट्र को एआईबीपी स्कीम में अभी तक जो पैसा दिया है, 1996 से, जब से एआईबीपी स्कीम शुरू हुई है, हम तब से 10,364 करोड़ रुपये महाराष्ट्र को एआईबीपी स्कीम के अंतर्गत दे चुके हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स, जो उन्होंने हमें पूरे करने के लिए दिए थे, अगर ये 66 प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए होते तो हम वहां पर 6 लाख हेक्टेयर तक के एरिया का इरिगेशन कर चुके होते। सर, असल में मुझे पढ़ने और बोलने में दिक्कत आती है और मैं फिगर पढ़े बिना बोल नहीं सकती हूं। मैं बताना चाहूंगी जो घोषीखुर्द की कहानी है, वह यह कह रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होने के बाद भी वहां के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स समय पर कम्पलीट नहीं हो सके। इस कारण से प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट डबल हो गई, टाइम भी बढ़ गया और जितना पोटेंशियल यूटेलाइज़ होना था, वह नहीं हो पाया। महाराष्ट्र को हम एआईबीपी योजना में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा दे चुके हैं। अब यह जो सूखे की चुनौती सामने आई है, इसके लिए पूरे देश में तीन उदाहरण हैं। एक उदाहरण वह है, जहां पर सूखा स्वाभाविक था और उस राज्य ने उसको पार कर लिया। दूसरा है, जहां सूखा पड़ता था, लेकिन उस राज्य ने अपने आपको इस लायक बना लिया कि अब वह उसका मुकाबला कर लेगा। तीसरा है, वह राज्य मुकाबले की तैयारी कर रहा है। यद्यपि दस से ज्यादा राज्य सूखे से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन मैं यहां इन तीन राज्यों का उदाहरण दूंगी। एक गुजरात है, जिसका एक बहुत बड़ा इलाका हमेशा सूखा रहता था। जब हमारे प्रधान मंत्री वहां मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक प्रॉपर वॉटर मैनेज़मेंट के जरिए पानी की कमी का मुकाबला कर लिया था। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश था, जो सूखे की मार झेलता था, लेकिन बेहतर कुशल जल प्रबधन से ही उनकी कृषि की ग्रोथ हुई है। कुछ दिनों पहले, जब मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को फोन करके पूछा कि मध्य प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है, आप उसका कैसे मुकाबला कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमारी वॉटर बॉडीज़ में इतना पानी है कि हम इसका मुकाबला कर लेंगे, यदि हमें केंद्र से भी सहयोग की आवश्यकता लगेगी, तो हम आपसे मांगेंगे। तीसरी स्टोरी तेलंगाना की है। उन्होंने काकतिया डायनेस्टी के टाइम के हज़ारों तालाबों की एक सूची बनाई है। वे अपनी अधिकतम धनराशि उन तालाबों पर खर्च कर रहे हैं और हमसे भी सहयोग मांग रहे हैं। वे छोटी-बड़ी वाटर बॉडीज़ को तैयार कर रहे हैं, जिसमें इतना पानी एकत्रित हो जाए कि जब भी पानी का संकट आए, इरिगेशन के लिए हो, ड्रिंकिंग वॉटर के लिए हो, जब भी कोई संकट हो, उसका मुकाबला कर सकें।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी के बारे में भी बताना चाहूंगी, मैंने कैबिनेट की सीक्रेसी की ओथ

ली हुई है, लेकिन मैं जिस प्रसंग का जिक्र कर रही हूं, वह कैबिनेट में नहीं होता। एक प्रेजेन्टेशन हुआ था, उन्होंने हमें, वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री को सितम्बर, 2014 में बुलाया था। उन्होंने कहा कि इसका प्रेजेन्टेशन दो। मुझे मंत्री बने हुए तीन-चार महीने ही हुए थे। उन्होंने हमारे मंत्रालय को पानी के विज़न के लिए प्रेजेन्टेशन देने के लिए कहा। जब हमने उनके सामने उसका प्रेजेन्टेशन दिया तो 2004 और 2009 के बाद वर्ष 2014 सूखे का तीसरा वर्ष था, जिसका प्रारंभ था। उन्होंने हमसे जो बातें कहीं, हमने उनका आज तक पालन किया। हमारे मंत्रालय ने उसी पर अपनी कार्य योजना बनाई। इसमें उन्होंने हमसे मुख्य बात यह कही कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उनके रास्ते चूक रहे हैं, तो उनके रास्ते खोल लो, यदि नई वाटर बॉडीज़ का निर्माण हो सकता है, तो उसको कर लो, जो वाटर बॉडीज़ ठीक से काम कर रही हैं, उनकी और उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, तो उसको भी बढ़ा लो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का जो चुनाव हुआ है, वह डेवलपमेंट के कांसेप्ट पर हुआ है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी हमेशा विभाजन के कांसेप्ट पर चुनाव लड़ती थी। ...**(व्यवधान)**... यह चुनाव पूरी तरह से डेवलपमेंट के कांसेप्ट पर हुआ है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः आप ये सब चीजें मत कहिए ...**(व्यवधान)**... हम उनका नाम सुनने के लिए नहीं बठे हैं। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः यह गलत बात है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Silence, please. ...(*Interruptions*)... Silence please. ...(*Interruptions*)....

सुश्री उमा भारतीः उनका जो डेवलपमेंट का कांसेप्ट था ...**(व्यवधान)**... Development का उनका जो concept था, वह गुजरात का मॉडल था। गुजरात का जो मॉडल था ...**(व्यवधान)**... गुजरात का जो मॉडल था, उसकी success story की जो baseline थी, वह पानी था। किस प्रकार से थोड़े-बहुत बरसे हुए पानी को रोकना, रोके हुए पानी का किस-किस प्रकार से उपयोग करना, rain water harvesting करना, ground water recharge करना, surface water को साफ रखना और एक प्रकार से गुजरात के development ...**(व्यवधान)**... सर, असल में बात यह है कि दो साल हो गए, लेकिन इनके दिल से हार का दर्द नहीं जाता, जो हार का दर्द है ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादवः उमा जी, ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): She is not yielding. ...(*Interruptions*)... She is not yielding. ...(*Interruptions*)... मंत्री जी, क्या आपका जवाब पूरा हो गया? ...**(व्यवधान)**...

सुश्री उमा भारतीः नहीं, सर, वे बोलना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादवः सर, यह बात ठीक नहीं है, आप यहां चेयर पर बठे हैं। मैं आपसे यह विनती करना चाहूँगा कि मंत्री जी के yield करने के बाद आप उनको कह रहे हैं कि फिर खड़े होइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद यादव: मैं नहीं बोलूंगा। ...**(व्यवधान)**... मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप चेयर पर बैठे हैं, मैं आपसे विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसा कभी मत करिए, यह ठीक बात नहीं है। यह संसद बोली से चलती है, यह बहस से चलती है। मैं जो बात कहने वाला था, वह देश के हित की बात थी, लेकिन आपने जो बात कही ...**(व्यवधान)**...

सुश्री उमा भारती: सर, मैं yield करने को तैयार हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): क्या आप yield करने के लिए तैयार हैं?

सुश्री उमा भारती: मैं yield कर रही हूँ, आप बोलिए। मैं बैठ गई हूँ।

श्री शरद यादव: मैं यह निवेदन कर रहा था कि गुजरात के मामले का जो समाधान हुआ है, वह नर्मदा के सरदार सरोवर डैम से हुआ है, लेकिन उमा जी, जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि हम बड़े डैम बनाते हैं, लेकिन उसके चलते जो विस्थापन होता है, वे विस्थापित होने वाले लोग इतनी तबाही और बरबादी में चले जाते हैं कि अब बड़े डैम बनाने के पहले बहुत बड़े आन्दोलन होने लगे हैं। मेरा सरकार से यह कहना है कि आप पानी के मामले में जो विकास के काम आगे बढ़ाने वाले हैं, उनसे जो विस्थापित होने वाले लोग हैं, उनकी जिन्दगी जहां बसेगी, अगर उसे बेहतर नहीं बनाएँगे, तो बात नहीं बनेगी। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): आप relocation की बात कर रहे हैं।

सुश्री उमा भारती: सर, माननीय सदस्य इतने वरिष्ठ हैं कि मैं उनके सम्मान में बैठ ही गई, तो आपको शायद यह लगा होगा कि मैंने बोलना बंद कर दिया। मैं समझ गई थी।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी. पी. सिंह बदनौर): मैं आपसे पूछ रहा था कि आप yield करना चाहती हैं या नहीं?

सुश्री उमा भारती: अब आगे की तैयारी करने के लिए हमें कहा गया कि प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमें 46 प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं। 2017 में 23 और 2020 में 23, ऐसे वे 46 प्रोजेक्ट्स पूरे करने हैं, जिनसे 8 मिलियन हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। उनसे पीने के लिए भी पानी निकलेगा, सिंचाई के लिए भी पानी निकलेगा और कहीं-कहीं power generation भी होगा और हम इस टारगेट को पूरा करेंगे। इसके लिए राज्यों के साथ हमारी बैठक हुई और उस बैठक में हमने कुछ फैसले लिए। हमने राज्यों से कहा कि जो Government funding होगी, वह तो होगी ही, innovative funding में हम भी इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस्तेमाल करिए और हम इन लक्ष्यों को पूरा करें।

सर, इसके साथ ही साथ हकीकत तो यह है कि आज आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यगणों से एक अपील कर सकती हूँ। पिछले दो-तीन दिनों के अंदर एक खबर आई है कि असम में बाढ़ आ गई। एक तरफ लातूर की कहानी है, एक तरफ बुंदेलखंड की कहानी है और एक तरफ असम में बाढ़ आ जाने की कहानी है। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का नदियों को जोड़ने का जो सपना था, वह बाढ़ और सुखाड़ के बीच संतुलन बनाने का सपना था। जो पानी बाढ़ में आता है, वह विनाशकारी हो जाता है। अगर interlinking of rivers की योजना के

माध्यम से हम उस पानी को सूखे इलाकों में भेजेंगे, जिसकी हमने तैयारी की है, तो यह एक अच्छा काम होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह सूचना दे रही हूँ कि केन-बेतवा पहला लिंक होगा और शायद इसी वर्ष हम उसकी launching कर देंगे, उसका प्रारम्भ कर देंगे। इससे दोनों तरफ के बुंदेलखंड की सिंचाई की, पीने के पानी की और power generation की समस्या का निदान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो गोदावरी-महानदी लिंक होगा, वह ओडिशा में जो सूखे का संकट है, जिन KBK जिलों की चर्चा हो रही थी, जिनमें मैं कई बार गई हूँ, वह वहां की समस्या का निदान करेगा। ओडिशा एक ऐसा राज्य है, जिसमें एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़ होता है। मैंने ओडिशा के चीफ मिनिस्टर से खुद जाकर इसके लिए मुलाकात की थी। मैंने उनके कई इल्यूज़ंस को, भ्रमों को दूर किया है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वे महानदी-गोदावरी लिंक के लिए तैयार हो जाएं।

सर, यह जो 80,000 करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट की बात मैंने अभी बताई है, आपके माध्यम से मैं सदन के सामने और सदन के माध्यम से पूरे देश के सामने घोषणा करके यह बता देना चाहती हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह तय किया है कि वे आने वाली परिस्थितियों में सूखे का मुकाबला करेंगे। हम इस देश के लोगों को सूखे से प्रभावित नहीं होने देंगे और इसकी तैयारी हमने 80,000 करोड़ रुपये से की है। इसमें हम AIBP को लेंगे, PMKSY को लेंगे, Surface Minor Irrigation Schemes को लेंगे, RRR को लेंगे, जिसके तहत तेलंगाना में Kakatiya Dynasty का प्रोजेक्ट चल रहा है।

(**श्री उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

कुल मिलाकर हम उस स्थिति को ले आएंगे, जहां हर खेत के लिए पानी और हर प्यासे के लिए पानी होगा। इस लक्ष्य को हम अवश्य पूरा करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय सदन से एक अपील करना चाहती हूं। एक स्टोरी आ रही है। जहां लातूर की स्टोरी आ रही है, उसके साथ एक स्टोरी और भी आ रही है, हेवड़े बाजार की स्टोरी। हेवड़े बाजार की स्टोरी यह है कि किस प्रकार से पानी को बचाने के लिए जन-आंदोलन हुआ और उस जन-आंदोलन में किस-किस प्रकार के प्रयोग हुए हैं।

हमारे आदरणीय भाई साहब, शरद पवार जी बहुत लम्बे समय तक कृषि मंत्री रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गुरु हैं और हमारे आदर्श हैं, लेकिन मुझे आज तक यह समझ में नहीं आया कि वे महाराष्ट्र के लातूर जिले में फसलों के उस पैटर्न को क्यों एलाऊ कर रहे थे, जो पानी को सोख रही थीं। उनको अच्छी तरह से यह पता था कि यह वह इलाका है, जो water deficit zone के अंतर्गत आता है। यहां की धरती में हमेशा से पानी की कमी रही है और ऊपर से भी यहां कम पानी ही आता है। यह पैटर्न क्यों नहीं बदला गया? हमें इस पैटर्न को बदलने के बारे में विचार करना ही पड़ेगा। हेवड़े बाजार के लोगों ने जो प्रयोग किया, उसमें एक प्रयोग यह भी हुआ है कि कौन सी जमीन में किस प्रकार की फसल होनी चाहिए। सूखा तो ऊपर से आएगा, लेकिन नीचे धरती पर मिलजुल कर हम उस सूखे का मुकाबला कैसे करेंगे, हेवड़े बाजार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है।

सर, इस देश में इस प्रकार के और भी कई उदाहरण हैं। आप आश्चर्य करेंगे, अभी 5-7 दिन पहले मैं गंगोत्री गई थी और उस दिन हिमालय के पहाड़ों को देखकर मुझे विश्वास ही

[सुश्री उमा भारती]

नही हुआ। आज वे ऐसे लगने लगे हैं, जैसे राजस्थान के पहाड़ हैं, यानी हिमालय पर भी संकट खड़ा हो गया है। प्रधान मंत्री जी ने पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच में, जो उनकी मेडन स्पीच थी, यह कहा था कि इस देश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो जन-आंदोलन बने बगैर सफल नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा था कि आजादी की लड़ाई तभी सफल हुई, जब वह जन-आंदोलन में बदल गई। इसी प्रकार विकास की लड़ाई भी तभी सफल होगी, जब वह जन-आंदोलन में बदलेगी।

महोदय, मैं यहां उपस्थित सभी माननीय सदस्यगणों से यह अनुरोध करूंगी कि राज्य सभा का जो फंड है, उसे वे इस कार्य में लगाएं। मैंने स्वयं मेरी लोक सभा की जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि है, वह पूरी की पूरी इस कार्य के लिए दे दी है। मैंने अपने दोनों कलेक्टर्स से कह दिया है कि कि सबसे पहले आप पीने के पानी के संकट के लिए इस पैसे को लगाइए और जहां आप इसे लगाएं, वहां पशु-पक्षियों तक का ध्यान भी रखें, ताकि उनके लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। इसमें मनरेगा के द्वारा तो मदद मिलेगी ही, साथ ही सूखा पीड़ित लोगों को फसल बीमा योजना योजना का जो लाभ मिल सकेगा, वह भी दिया जाएगा और PMKSY के द्वारा भी हम उनकी मदद करेंगे।

हमें प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि तुम लोग अपना पसीना बहाओ, इसके लिए वहां जाकर चाहे अपने आप को सुखा दो, लेकिन लोगों को सूखे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पीने के पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने यह तैयारी की हुई है और इसके लिए प्रधान मंत्री जी ने हमें पूरी छूट दे दी है।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, जल संसाधन मंत्री होने के नाते पूरे सदन से यह अनुरोध करूंगी कि हमारे दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिसमें आप सब हमारा साथ दीजिए। एक तो नदियों को जोड़ने की हमारी जो योजना है, वह मूलतः सूखे के समाधान के लिए ही है। बाढ़ का पानी जब तक सूखे के इलाकों में नहीं पहुंचेगा, तब तक सूखे का पूर्णतया समाधान नहीं हो सकेगा, जैसा हम करना चाहते हैं।

दूसरा, भले ही हम PMKSY, AIBP, RRR, Surface Minor Irrigation Schemes के माध्यम से निदान निकालेंगे, लेकिन जब तक पानी को बचाना एक जन-आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा, तब तक यह कार्य संभव नहीं सकेगा। इसके लिए मैंने देश की सभी मैम्सर्ब ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखी थी और उनसे पूछा था कि कौन-कौन से प्रदेशों के कौन-कौन से जिले और इलाके ऐसे हैं, जो डार्क ज़ोन में बदल गए हैं। दुःखद कहानी तो यह है कि जहां केवल राजस्थान इत्यादि राज्य परम्परागत रूप से सूखे की मार झेलते थे, वहां अब उनमें नये राज्य भी शामिल हो गए हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि। यह विपदा बहुत बड़ी है, जो हम सभी के सामने मुंह बाए खड़ी है। सिर्फ इस साल के लिए ही नहीं, आगे के लिए भी प्रधान मंत्री जी ने जल संसाधन मंत्रालय को जैसी तैयारी के लिए कहा है, मुझे यकीन है कि उससे हम सूखे का मुकाबला कर सकेंगे।

महोदय, अम्बेडकर साहब सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने पानी को सहेजने का सपना देखा था और उसके लिए एक पूरी की पूरी कार्य योजना बनाई थी। आज मैं उनको याद करूंगी, क्योंकि उनकी ही बनाई हुई कार्य योजना पर कार्य किया गया और बाद में वही हमारा केंद्रीय जल

आयोग कहलाया। पहले यह बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा ही स्थापित हुआ था। इसका नाम बाद में बदल कर CWC (Central Water Commission) किया गया, लेकिन इसके जो मूल संस्थापक थे, वे बाबा साहेब अम्बेडकर थे। मेरे पास एक कागज है, जो अभी नीचे रखा है, लेकिन उसे मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। ...**(व्यवधान)**... नहीं-नहीं, मेरे पास लिख कर रखा हुआ है। मुझे उसे ढूँढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। उसकी स्थापना अम्बेडकर साहब ने की थी। ...**(व्यवधान)**... मैं उसका नाम बता देती हूँ। सर, मेरा यह कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का एक सपना था। उन्होंने 1942 और 1946 के बीच में जिस Commission की स्थापना की थी, उसका नाम Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission था। वे इसके अध्यक्ष थे। इसके द्वारा उन्होंने पूरे देश के जल संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से समन्वय करके किया जाए और हर आदमी को पानी किस प्रकार मिले, गरीब वर्गों को भी पानी मिले, खेतों को भी पानी मिले, गरीब वर्गों के खेतों को भी पानी मिले, इसकी व्यवस्था की थी। तो मूलतः भारत को सूखा-मुक्त बनाने का जो सपना था, वह बाबा साहेब अम्बेडकर का था। भारत को सूखा-मुक्त भारत बनाने का सपना जो अम्बेडकर साहब ने देखा था, वह मोदी जी पूरा करेंगे। भारत को कांग्रेस-मुक्त बनाने का सपना भी मोदी जी ने पूरा किया है। तो ये दोनों ही सपने मोदी जी ने पूरे किए हैं। इसको हम सूखा-मुक्त बनाने का भी सपना पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ।

श्री नरेंद्र बुढानिया (राजस्थान)ः सर, ...**(व्यवधान)**... मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः माननीय मंत्री जी, मैंने जो प्रश्न आपके सामने उपस्थित किए थे कि नदी जोड़ने का जो कार्यक्रम है, इसे आप ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आपका point of order क्या है? ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः जो प्रभु जी ने पहले इस बात को कहा था ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, ...**(व्यवधान)**... मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the point of order?

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः दूसरा मैंने आपसे यह पूछा था कि यह जो राज्यों का पानी है, उसको केंद्र में लाने की दृष्टि से आप क्या करेंगे? ...**(व्यवधान)**... आपने दोनों का जवाब नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र बुढानियाः सर, ...**(व्यवधान)**... मैं यह कहना चाहता हूँ कि ...**(व्यवधान)**... उसके बारे में क्या व्यवस्था हो रही है, कितना पैसा दिया गया, यह ग्रामीण विकास मंत्री जी बताएँगे। यह डिपार्टमेंट उनके पास है। ...**(व्यवधान)**... पीने के काम में आने वाला पानी ...**(व्यवधान)**... इन्होंने यहां पर बड़ा भाषण दिया। ...**(व्यवधान)**... गुजरात मॉडल, प्रधान मंत्री मॉडल ...**(व्यवधान)**... यह मॉडल, वह मॉडल ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, No.

6.00 P.M.

श्री नरेंद्र बुढानियाः इससे काम नहीं चलता। ...**(व्यवधान)**... वहां पानी पहुँचाना है। ...**(व्यवधान)**... तब गला ठीक होगा। ...**(व्यवधान)**...

डा. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश)ः सर, माननीय मंत्री जी ...**(व्यवधान)**... उत्तराखंड के बारे में बताइए। ...**(व्यवधान)**... अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There is no need. ...(*Interruptions*)... I will reply to the point of order.

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, उन्होंने मेरा नाम लिया था, इसलिए वे मेरी बातों का जवाब दें।

श्री उपसभापतिः उन्होंने किसलिए आपका नाम लिया?

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः मैंने पूछा है, उसका वे जवाब दे रही हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to know?

श्री विजय जवाहरलाल दर्डाः सर, मैंने यह पूछा था कि नदियों को जोड़ने का काम कब शुरू करेंगे और दूसरा, राज्यों का जो विषय पानी का है, उसे ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः डिप्टी चेयरमैन सर, ...**(व्यवधान)**... उसे आने दीजिए, उसके बाद बात करनी है, तो वे कह सकते हैं।

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः सर, ...**(व्यवधान)**... अपने क्षेत्र के बारे में तो बताइए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do you want to know? ...(*Interruptions*)... Now, the Agriculture Minister.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं सदस्यों द्वारा लोगों और विशेष रूप से किसान समुदाय के प्रति दशार्यी गई चिन्ता के लिए भी उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं सबसे ज्यादा इस बात के लिए आभारी हूँ कि हम सब लोगों ने अपने राजनीतिक मैसेज को लाने के साथ-साथ बड़े निर्दोषपूर्ण तरीके से किसानों की समस्या को रखने की कोशिश की। आदरणीय पवार साहब ने तो बिल्कुल इस मामले में निर्दोषपूर्ण मागदर्शन इस सदन को दिया है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि विषय राज्य का हो या केंद्र का हो, इस चक्कर में नहीं पड़ कर हम सबको मुस्तैदी से काम करना चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं है। इससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र और राज्यों की जो भूमिका है और जिम्मेवारी है, वह हमारे सूखा प्रबंधन के लिए जो मन्युअल बना है, उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है। अब तत्काल आज तो हम और आप उसको नहीं बदल सकते हैं। उसमें राज्य सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से है और केंद्र सरकार की भी भूमिका उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित है। राज्य और जिला प्रशासन सूखा राहत और प्रशमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। सूखा घोषित

करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। सूखा प्रबंधन हेतु जो मैन्युअल है, उसमें यह स्पष्ट है। महोदय, मौसम की जो स्थिति है ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद पवारः सर, हाउस का समय बढ़ाया जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let us extend the time. The House agrees.

श्री राधा मोहन सिंहः सर, भारत मानसून विज्ञान ने 12 अप्रैल, 2016 को दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा के लिए एक पूवार्नुमान जारी किया है। जिसमें यह बताया है कि सर्व भारतीय स्तर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा इस वर्ष साधारण वृष्टिपात की 106 प्रतिशत होगी। भारत मौसम विभाग के इस पूवार्नुमान के मॉडल की त्रुटि माइनस-प्लस फाइव परसेंट है। मानसून 2016 के पहले चरण का यह पूवार्नुमान है। मानसून के दूसरे चरण का पूर्वानुमान मई के अंत में जारी होगा। 15 मई के आस-पास केरल में कब मानसून पहुंचेगा, इसके बारे में पूर्वानुमान किया जाएगा।

महोदय, तिवारी जी अभी नहीं हैं, पिछली बार जब उन्होंने चर्चा शुरू की थी, तब उन्होंने कहा था कि लगातार सूखे पड़ रहे हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, तो मुझे ध्यान में आ गया कि जब सम्मानीय सुब्रमण्यम जी कृषि मंत्री थे, तब सूखे का भारी संकट आया था। अगर उस समय तिवारी जी होते, तो वे उनको सुझाव देते, तो वे वहां चले जाते, लेकिन उस समय भी जब सूखा आया था, तब वे भी किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए थे। वे आईसीएआर के पास गए थे और उस समय स्वामीनाथन एक युवा वैज्ञानिक थे। वे उनके पास गए थे, ज्योतिषी के पास नहीं गए थे। यदि शायद इस प्रकार की सलाह का कुछ लोगों ने पालन किया हो, कहीं उसके पाप का प्रायश्चित तो हम नहीं भोग रहे हैं? हमें यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन जो सूखे की स्थिति है, वह हम सबको पता है। देश में 2015-16 में रबी और खरीफ की जो खेती थी, सूखे के कारण उसमें कम बुआई हुई, लेकिन 2015-16 की खरीफ के समय या इस सरकार के आते यानी 2014-15 में, उस समय भी सूखा था, उस समय माइनस 10 या 12 था और इस वर्ष माइनस 12 है। पिछला जो सूखा पड़ा था, उसके पहले भी तैयारी थी और माननीय शरद पवार जी मंत्री थे और हर साल खरीफ और रबी की तैयारी के लिए उसके पहले बैंठकें होती हैं, योजना बनती है। इसके लिए हम लोगों ने जो योजना बनाई, 2015-16 के लिए जो योजना बनाई, उसमें बुआई कम हुई, लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं, जो द्वितीय अग्रिम अनुमान आया है, 15.02.2016 के अनुमान के अनुसार 2015-16 में खाद्यान्न का उत्पादन 253.16 मिलियन टन होगा। यह उत्पादन 2014-15 की तुलना में 1.14 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है। यह अनुमान है, जबकि बुआई कम हुई है, लेकिन उसमें मौसम ने भी साथ दिया। इस बार रबी की फसल के समय उतनी भारी ओलावृष्टि नहीं हुई, जितनी भारी ओलावृष्टि पिछली रबी की फसल के समय हुई थी। यह जो द्वितीय अनुमान है, उसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन ज्यादा होगा। अभी तीसरा और चौथा अनुमान आएगा।

महोदय, 600 जिलों के लिए contingency plan बना कर राज्यों को उपलब्ध कराया गया था। यह शुरू में ही उपलब्ध कराया गया था। यह जो आईसीएआर द्वारा contingency plan बनाया जाता है, उसको केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान विकसित करता है। यह हैदराबाद में स्थित है। राज्यों के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, जो राज्य सरकारें हैं और जो आईसीएआर के संस्थान हैं, उनके सहयोग से contingency plan बनता है और इसको वे हमेशा डेवलप करते रहते हैं। यह कंटिजेंसी प्लान 600 जिलों को उपलब्ध कराया गया है और इससे भी लाभ मिला

[श्री राधा मोहन सिंह]

है। इसमें फसल चक्र की स्थिति बताई गई है कि कौन-सी फसल कब लगानी है और उसकी बुआई की क्या विधि है, यह भी बताया गया है। जितने दिन सूखा आता है, यानी यदि 15 दिन सूखा है तो उसके बाद कौन सी फसल किस विधि से लगानी है, इसमें यह भी बताया गया है। ये सारी precautions सभी राज्यों को मुहैया कराई जाती हैं और उनकी मॉनिटरिंग होती रहती है। अभी अगर वर्षा भी ज्यादा आती है तो उसके लिए भी इस कंटिजेंसी प्लान के माध्यम से मागदर्शन राज्यों को मिलता है।

हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चल रहे "चारा विकास कार्यक्रम" के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर योजना के तहत आंध्र प्रदेश को 2.41 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 7.97 करोड़ रुपये, राजस्थान को 4.84 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 12 करोड़, कर्णाटक को 12.5 करोड़, उत्तर प्रदेश को 1.92 करोड़, छत्तीसगढ़ को 0.96 करोड़, ओडिशा को 14.40 करोड़...

श्री नीरज शेखरः मंत्री जी, आप यह क्या बता रहे हैं? यह समझ में नहीं आ रहा है। क्या केवल 50 करोड़ रुपये पूरे देश के लिए हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः यह "चारा विकास कार्यक्रम" की बात है। मैं एक-एक राज्य का नाम बोल रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**... चारे के लिए सभी राज्यों को जो राशि दी गई, वह मैं बता रहा हूँ। ...**(व्यवधान)**...

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश): उत्तर प्रदेश के साथ हुई नाइंसाफी को आप खुद ही बयां कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

†**چودھری منوّر سلیم:** اتّر پردیش کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو آپ خود ہی بیاں کر رہے ہیں ---**(مداخلت)**---

श्री राधा मोहन सिंहः भाई, राज्यों के प्रस्ताव आते हैं, जिसके आधार पर उनको रुपए दिए जाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मंत्री जी, प्रस्ताव कितना आया था और कितना सेंक्शन हुआ? आप जो यह 50 करोड़ के बारे में फरमा रहे हैं, तो 50 करोड़ का चारा तो एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कम है। ...**(व्यवधान)**...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** منتری جی، پرستاؤ کتنا آیا تھا اور کتنا سینکشن ہوا؟ آپ جو یہ 50 کروڑ کے بارے میں فرما رہے ہیں، تو 50 کروڑ کا چارا تو ایک ڈسٹرکٹ کے لئے بھی کم ہے ---**(مداخلت)**----

श्री राधा मोहन सिंहः हमारा "चारा विकास कार्यक्रम" चलता है और इन राज्यों के प्रस्ताव आने के बाद उनको इतने पैसे जारी किए गए। ...**(व्यवधान)**...

† Transliteration in Urdu script.

श्री गुलाम नबी आज़ाद: जो स्टेट चारे के लिए लोन मांगती है, वह स्टेट एक रुपया भी डिज़र्व नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि दो करोड़ रुपये में क्या चारा आएगा?

†جناب غلام نبی آزاد : جو اسٹیٹ چارے کے لئے لون مانگتی ہے، وہ اسٹیٹ ایک روپیہ بھی ڈزرو نہیں کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کروڑ روپے میں کیا چارا آئے گا؟

श्री राधा मोहन सिंह: यह "चारा विकास कार्यक्रम" ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ाद: चारे से क्या विकास होगा?

†جناب غلام نبی آزاد: چارے سے کیا وکاس ہوگا؟

श्री राधा मोहन सिंह: यह योजना तो आपको बनानी ही नहीं चाहिए थी। यह आपके समय की बनी हुई योजना है। यह "चारा विकास योजना" आपको बनानी ही नहीं चाहिए थी। ...**(व्यवधान)**... लेकिन इस योजना की जरूरत है। यह एक अच्छी योजना बनी है और इससे लाभ होता है। ...**(व्यवधान)**... मैं यह बता रहा हूँ कि क्या किया गया है, आप पहले इसको सुनिए। जब आप इसी को नहीं सुनिएगा तो बाकी बातों को सुनना और कठिन होगा।

जो लैंडलेस किसान हैं, उनके लिए भी एक योजना तब शुरू की गई थी, जब आपकी ही सरकार थी। यानी, वर्ष 2006-07 से एक योजना शुरू की गई थी, जो भूमिहीन किसानों का एक समूह बनाकर उनको खेती के लिए कर्ज देने के लिए बनाई गई थी। इसको भी आप कहिएगा कि यह ठीक नहीं है, जबकि यह आपके समय की ही है। लेकिन आपको इतना जरूर सुनना पड़ेगा कि वर्ष 2006-07 से 2013-14 तक करीब सात साल के अंदर जो लैंडलेस किसान थे, उनके छः लाख ग्रुप्स बनाए गए। इधर दो वर्ष के अंदर उनके सात लाख से ज्यादा ग्रुप्स बनाए गए हैं और उनको 7,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सामान्यतया पांच किसानों का एक ग्रुप बनता है, जिसे 20,000 रुपये तक दिये जाते हैं। सात वर्ष में ऐसे 6 लाख ग्रुप्स बनाए गए, जबकि दो वर्ष के अंदर 7 लाख ग्रुप्स बनाए गए हैं और उनको 7,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह तो आपको सुनना ही पड़ेगा।

कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना— हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। ये चीज़ें पहले से हो रही हैं। हम स्पीड बता रहे हैं कि आप जैसा बोल रहे थे कि आपने बहुत कुछ किया। हमने तो कुछ कहा नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, देश देख रहा है, लेकिन कृषि उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देने के लिए भी 29 राज्यों में अभी तक पांच लाख किसानों के लगभग 428 एफपीओज़ बने हैं और दो लाख किसानों के 266 एफपीओज़ के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। अब आप इस पर जरूर कमेंट करेंगे कि यह एफपीओ क्या है? इसके द्वारा किसानों का इनपुट मूल्य संवर्धन और मार्केटिंग संबंधी सुविधा मुहैया करायी जाती है इसलिए FPO (Farmer Producer Organisation) का निर्माण होता है और इस काम में भी सरकार बड़ी तेजी से लगी हुई है।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश): सर, landless क्या होता है? What is landless kisan?

†جناب جاوید علی خان: سر، لینڈ- لیس کیا ہوتا ہے؟ واٹ از لینڈ-لیس کسان؟

† Transliteration in Urdu script.

श्री राधा मोहन सिंहः डी. राजा साहब उस सवाल को बहुत उठाते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री जावेद अली खानः एक खेतिहर मज़दूर होता है, जो उसकी टर्म है। अब सरकार की यह स्थिति है कि वह landless किसान और खेतिहर मज़दूर में फर्क नहीं कर पा रही है।

†جناب جاوید علی خان: ایک کھیتی- ہر مزدور ہوتا ہے، جو اس کی ٹرم ہے- اب سرکار کی یہ حالت ہے کہ وہ لینڈ-لیس کسان اور کھیتی- ہر مزدور میں فرق نہیں کر پا رہی ہے-

श्री वी. पी. सिंह बदनौरः जो दूसरों की खेती को करता है, जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः जो मज़दूर है, उसको यदि भूमिहीन किसान कहेंगे, तो उसको सम्मान मिलेगा। आप मज़दूर को सम्मान भी नहीं देना चाहेंगे! आप मज़दूर से इतनी दूरी बढ़ाएंगे! आप मज़दूर बोलेंगे तो गौरवान्वित होंगे, लेकिन हम गौरवान्वित तब होंगे, जब मज़दूर को हम landless और भूमिहीन किसान बोलेंगे, क्योंकि कृषि और किसान उसी के कारण ज़िंदा है। उसको सम्मान देने पर आपको एतराज़ होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ...**(व्यवधान)**... मेरे लिए नहीं, आपके लिए है।

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): मंत्री जी, सूखे में सूखा सम्मान ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः 2015-16 में 815 करोड़ रुपए के कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसे बढ़ाते हुए 2016-17 में सरकार ने कृषि ऋण का लक्ष्य 9,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। भारत सरकार द्वारा फसल ऋण के संबंध में जो ब्याज में छूट दी जाती है, हम तीन प्रतिशत की देते हैं और किसानों को चार प्रतिशत देनी पड़ती है। यदि हम ईमानदारी से यहां चर्चा कर रहे हैं तो चार-पांच राज्य ऐसे हैं कि चार प्रतिशत अपने खजाने से रुपए निकालते हैं और किसान को ज़ीरो प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। जो देश का किसान टैक्स देता है, हम उस दिशा में ज्यादा नहीं जाना चाहेंगे, वह भारत सरकार के खजाने में आता है, राज्य के खजाने में जाता है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी राज्य को जाती है और राज्य सरकार के खजाने में भी उसके सोर्सेज़ से पैसा आता है। हम जिन-जिन राज्यों के रहने वाले लोग हैं, किसान के लिए हम इतने आंसू बहा रहे हैं। उसमें इतने आंसू नहीं बहाने हैं। चार राज्य जो यह काम कर रहे हैं कि अपने खजाने से चार प्रतिशत की राशि देकर शून्य ब्याज दर पर किसानों को ऋण दे रहे हैं, क्या हम इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर सकते हैं? राजनीति हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी राजनीतिक बात बोलेंगे क्योंकि आपने राजनीतिक बात रखी है, लेकिन मेरा आग्रहपूर्वक निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर अपने-अपने राज्यों में जाकर कुछ ऐसी बातें तो जरूर करें कि किसानों को उनका लाभ मिल सके। जो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 13 सूखाग्रस्त राज्यों में 26 अप्रैल, 2016 तक कुल 2,172 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। उन राज्यों को पैसा गया था।

श्री के. सी. त्यागीः इसमें से लातूर में कितनी पहुंची?

श्री राधा मोहन सिंहः हम जिलों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, राज्यों का बता रहे हैं। जो

† Transliteration in Urdu script.

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से आया है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2016-17 के लिए 819 करोड़ रुपए की राशि प्रथम किश्त में, इस वर्ष का भी, बिना Vote on Account हुए, राज्यों को यह राशि प्रथम किश्त में दे दी गयी है। आप तैयारी पूछ रहे हैं तो पूरे देश की तैयारी का ही तो पूछ रहे हैं।

श्री के. सी. त्यागीः मंत्री जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। शरद जी, उमा जी और चंद्रपाल यादव जी, वहां के तीनों नेता बठे हुए हैं। बुन्देलखंड पैकेज राशि में से जल संवर्धन कार्यों पर 863 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस राशि से 6 जिलों में ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tyagiji, what are you doing? ...(*Interruptions*)... What are you doing?

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। इस राशि में से 6 जिलों में 45,000 कुएं और 2,646 तालाब खोदे गए हैं। जल सरक्षण के नाम पर 774 stop dams बनाए गए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आप ऐसे समय में ऐसी बात उठाइए कि सबको सुनने में ठीक लगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tyagiji, I have not permitted you. You cannot speak now. Okay. Mr. Minister, please continue.

श्री राधा मोहन सिंहः मैं बता रहा हूं कि सरकार ने क्या किया, इसको तो थोड़ा सुन लीजिए। इससे रिलेटेड उसका enlargement है और अगर आप जिला वाइज़, गांव वाइज़ कहेंगे, तो उसके लिए आप कल चर्चा रखिए, वह भी हम बताते हैं कि किस जिले में, किस गांव में कितना पैसा गया, लेकिन आप इस सदन के पुराने सदस्य हैं और पुराने के साथ-साथ देश के बड़े नेता हैं। भविष्य में भी आप एक पार्टी की कमान संभालने वाले हैं इसलिए आप थोड़ा इसको सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**... राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत प्रथम किश्त जारी की गयी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत Flexi-Fund head में 26, अप्रैल 2016 तक 217 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध थी। यह 50 प्रतिशत होता है और उसमें राज्य भी 50 प्रतिशत देता है। पेयजल संकट से 299 जिलों में 4,41,390 पोंड प्रभावित हुए हैं।

इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ कदम उठाए गए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। फिर से कृपा करके अपने जिले के विषय में नहीं पूछिएगा। करीब 7,38,650 हैड पम्प रिपेयर किए गए हैं, 13,332 बोरवैल्स को किराए पर देकर पानी उपलब्ध कराया गया है। हैड पम्पों का जल स्तर घटने पर 10,76,991 राइज़र पाइप्स जुड़ गए हैं, इसका मतलब है कि नीचे और पाइप जोड़कर उसको गाड़ा गया है। इसी तरह से 44,998 नये बोरवैल बनाए गए हैं, 1,398 नई अस्थाई पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाएं इस बीच में बनाई गई हैं, 46,110 टैंकरों के फेरों से 15,345 ट्रेनों में पानी उपलब्ध कराया गया है — यह मैं जानकारी दे रहा हूं। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 26 अप्रैल, 2016 तक कुल 390.88 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध थी। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत फ्लैक्सी फंड में भी उनको 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में पेय संकट से 33 जिलों में 19,469 कुएं प्रभावित

[श्री राधा मोहन सिंह]

हुए हैं। इस संकट से निपटने हेतु महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों के 2,306 गांवों में 2,908 टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। इसमें से लातूर जिले के 193 गांवों में 240 टैंकर्स चल रहे हैं। मराठवाड़ा क्षेत्र के जिलों में 367 पशु केंद्र चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक 18 घंटे में 25 लाख क्यूसेक पानी वाली ट्रेन भेजने की योजना वहां बनाई गई है। यह सब जानकारी है, लेकिन बहुत सारे सवाल कृषि से संबंधित उठे। हमारे कई माननीय सदस्यों ने, अहमद साहब यहां पर नहीं हैं, उन्होंने यह विषय उठाया और कहा कि सरकार को पता नहीं है, पता नहीं है। जो क्वोट किए थे, उसकी जानकारी थी और बाकी के संबंध में उन्होंने बताया कि जानकारी नहीं है। जो राज्य आपदा राहत कोष है, एस.डी.आर.एफ. है, उसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का पैसा होता है और यह दो किश्तों में जाता है। जब कहीं आपदा आती है, तो राज्य सरकार के पास जो एस.डी.आर.एफ. का पैसा होता है, वह उसे खर्च करती है। उदाहरण के लिए, अभी गुजरात के पांच जिलों में संकट आया। अब वहां की सरकार ने यहां से पैसा नहीं मागा, क्योंकि उनके पास एस.डी.आर.एफ. के तहत 3,000 करोड़ रुपए हैं। कुछ राज्यों के पास इस मद का पैसा नहीं भी है, तो कैबिनेट की मीटिंग करके, जैसे झारखंड के हमारे साथी बता रहे थे, कैबिनेट की मीटिंग करके खर्चा किया। बिहार की सरकार ने भी यहां अपना memorandum नहीं भेजा, केबिनेट मीटिंग की, उसके पास कुछ एस.डी.आर.एफ. का पैसा रहा होगा या contingency का पैसा रहा होगा, तो वे उसको इस्तेमाल करते हैं और खुद आपदाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा होता है, तो वह उनके बरदास्त के बाहर होता है। पुरानी परिपाटी के अनुसार वे memorandum देते हैं । यह बराबर बदलता रहता नहीं है। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष गृह मंत्रालय के अधीन रहता है और सिफ जो चार बातें हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः पहले यह कृषि मंत्रालय में था। शरद पवार साहब यहां बठे हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः शरद पवार साहब भी बता रहे हैं कि यह वहीं रहता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः माननीय मंत्री जी, वह पैसा तो राज्य सरकार को मिलना चाहिए। चाहे सूखा पड़े या नहीं पड़े राज्य सरकार को तो पैसा मिलना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप एक-एक लाइन पर पूछेंगे, तो कैसे होगा? हम पूरी बात बोल देते हैं, उसके बाद आप पूछिए। हम रात भर बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, आप रात भर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।

श्री राधा मोहन सिंहः जब मोदी सरकार आई, तो ये जो 12 राष्ट्रीय आपदाएं हैं, इन्हीं में राष्ट्रीय आपदा कोष के पैसे भी खर्च होते हैं और NDRF से भी इन्हीं में जाते हैं। इस सरकार ने यह किया कि जो स्थानीय आपदाएं जैसे बिजली गिरना, तूफान आना, भारी वर्षा, नाव, दुर्घटना, सर्पदंश आदि हैं, राज्यों से कहा कि अब आप इन आपदाओं को भी स्थानीय आपदा मानकर SDRF के पैसे में से 10 प्रतिशत राशि इन पर खर्च कर सकते हैं। राहत के मानकों में यह एक परिवर्तन की शुरुआत हुई। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी। जब SDRF में पैसा कम पड़ता है या समाप्त

हो जाता है, उनके कंट्रोल से बाहर होता है, तो वे ज्ञापन भेजते हैं। 15 मई से 30 दिसम्बर तक हमें राज्यों से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसमें दस राज्यों में 251 जिलों को सूखा घोषित किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में कौन आता है, यह अधिकार राज्य सरकार को है। इसको भारत की सरकार घोषित नहीं करती है। यदि इसको भी समझने में परेशानी होगी, तो बाद में बता दिया जाएगा। वैसे अभी समय नहीं है। हमारी केंद्रीय टीम ऐसे क्षेत्रों में तुरंत गई। अभी अहमद साहब बोल रहे थे कि टीम पहले भी जाती रही है। हमारी टीम भी गई और इस पर बैठक करके, उसने जो रिपोर्ट दी, उसके आधार पर जो रिलीज़ हुए हैं, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो 251 जिले हैं, इनके अलावा भी अभी जो पेयजल संकट आया है ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रजनी पाटिलः आपकी टीम को हमारे यहां पत्थर मारे गए।

श्री राधा मोहन सिंहः टीम भारत सरकार की जाती है, 60 वर्ष आपकी टीम को लोगों ने पत्थर मारे हैं और दो वर्ष हमारी टीम को भी पत्थर मारे, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आपकी टीम को 60 वर्ष लोगों ने पत्थर मारे हैं। पीड़ित लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिनको पीड़ा है, वे कुछ भी कर सकते हैं। यह खरीफ की फसल में आपदा आई थी और रबी की फसल में सिर्फ कर्णाटक जिले में दिया है। जो उन्होंने मांग की थी, उसमें उनको 723 करोड़ की राशि न सिर्फ मंजूर हुई, बल्कि रिलीज़ भी हो गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान से 15 जिलों के लिए ओलावृष्टि के लिए कल ज्ञापन प्राप्त हुआ है। मैं अहमद साहब को बता दूं कि कल ज्ञापन प्राप्त हुआ है और आने वाले कल को वहां टीम जाएगी। हमने ओलावृष्टि के समय भी ऐसा किया था। यह ठीक है कि हम प्रकृति के प्रकोप को नहीं रोक सकते, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाला जो कष्ट है, उसको कम करना और भरपूर राहत देना किसी भी सरकार का दायित्व है। पहले राहत देनी है, इसके बाद की मदद बाद में हो। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि राहत के मानकों में परिवर्तन किया गया है। अभी यहां एक सदस्य बोल रहे थे कि दो हेक्टेयर तक है। पहले तो दो साल तक एक हेक्टेयर पर ही मिलता था। एक हेक्टेयर पर 50 फीसदी नुकसान होगा, तभी मिलता था, लेकिन इस सरकार ने दो हेक्टेयर किया है। यदि 33 per cent तक नुकसान होगा तब भी मिलेगा। यह इस सरकार ने किया है। इतना ही नहीं पहले प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की मृत्यु होती थी, डेढ़ लाख रुपया मिलता था। इस सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर चार लाख रुपए किया है।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पहले प्रति एकड़ जो राशि मिलती थी, वर्षा सिचिंत, साढ़े चार हजार रुपए प्रति हेक्टेयर था, उसे बढ़ाकर 6,800 रुपए किया गया है। इसी प्रकार जो असिचिंत क्षेत्र थे, उनके लिए 9 हजार प्रति हेक्टेयर राशि थी, अब उसको बढ़ाकर 13,500 रुपए किया गया है। बारहमासी फसलों के लिए 12,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया। मैं कुछ राज्यों को बधाई देना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि उन राज्य सरकारों ने भी उसमें पैसा लगाया। यदि हम महाराष्ट्र में देखें तो पिछली बार, जब ओलावृष्टि हुई और अंगूर की खेती का नुक़सान हुआ था, तो 25-25 हजार रुपये तक देने का काम किया था। ...**(व्यवधान)**... मैंने बोल दिया है। यह हमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा। अब हमारा भी दायित्व बनता है कि राज्यों के अंदर भी थोड़ा समय देकर ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा): ओडिशा को भी ...**(व्यवधान)**... मिनिमम सपोर्ट प्राइस ...**(व्यवधान)**...ज्यादा दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मेरी विनती है, मेरा यह आग्रह है कि सभी राज्य सरकारें पैसा लगाएं। उनको भारत सरकार भी देती है। ...**(व्यवधान)**... उसके बाद राज्य का जो आपदा कोष है, उसमें पहले क्या राशि जाती थी? पहले जो राशि जाती थी, जो लोग चर्चा कर रहे थे कि इधर तो लोग सोए हुए हैं, यदि सोया हुआ आदमी जगे हुए आदमी से कहे कि सोये हुए हैं, तो यह अपने आप में आठवां आश्चर्य होगा। आप इन पांच वर्ष के अंदर देखिए कि राज्य आपदा कोष में सरकार की ओर से पांच बरस में 33,580 करोड़ रुपये गए हैं। अभी पांच बरस के लिए, 15-16 से बढ़ाकर, 61, 219 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया गया है। यह लगभग पौने दो गुना किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्मा (राजस्थान)ः सर, मेरा इसी पर प्रश्न है। मेरा सीमित प्रश्न है ...**(व्यवधान)**... हर चीज़ पर झगड़ा नहीं किया करो। ...**(व्यवधान)**... मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से प्रश्न है कि आपने अभी यह जो आंकड़ा दिया है कि इतने पैसे का आवंटन कर दिया गया है, तो इस साल के बजट के अंदर यह जो 15,000 करोड़ रुपया बढ़ा हुआ दिखाया गया है, वह रेवेन्यू हेड से हटाकर, वह जो राहत का पैसा था, आपने उसको शिफ्ट कर दिया। जब बजट पर चर्चा होगी, तो आप कृपया इस पर जवाब दें। यह पैसा बढ़ा नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आप विषयांतर कर रहे हैं। आपका विषय है ...**(व्यवधान)**... हमने ...**(व्यवधान)**... जो बजट बढ़ाया है, आप उस विषय में बोल रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः आप यह बताने की भी कृपा करें। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं उसी पर कह रहा हूं, आप सुनिएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः आप मेरी बात सुन लें। ...**(व्यवधान)**... आप यह भी बताने की कृपा करें कि हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत, बजट का कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर के लिए है? आप परसेन्टेज बताइए।

श्री राधा मोहन सिंहः मेरा जो विषय है और आप जो विषय लाए हैं, जब मैं उस पर बोलूंगा, यह उस समय का विषय है। अभी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पांच वर्ष तक राज्य आपदा कोष में 33,000 करोड़ रुपये गए और अब इस वर्ष से पांच बरस के अंदर 61,000 करोड़ रुपये जाएंगे। इस विषय को टालने के लिए आप जो तीसरा विषय उठा रहे हैं, उसके लिए यह उचित समय नहीं है। जब मैं वह विषय लाऊंगा या जब मेरी बात समाप्त हो जाएगी, आप तब बोलिएगा। दूसरा, इसको और भी ठीक से ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, आपको और कितने मिनट चाहिए? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः दूसरा, इसको और भी ठीक से ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आज़ादः भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही एक राष्ट्रीय आपदा थी, तो आप अपने साथ आपदा ...**(व्यवधान)**... लाए तो हम क्या करें? ...**(व्यवधान)**...

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد):** بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے آپ میں ہی ایک راشٹریہ آپدا تھی، تو آپ اپنے ساتھ آپدا **---(مداخلت)---** نہیں لائے تو ہم کیا کریں؟ **---(مداخلت)----**

† Transliteration in Urdu script.

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, आपको और कितने मिनट चाहिए? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं पिछली बार भी उत्तर नहीं दे पाया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः मंत्री जी आप आराम से बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः सर, ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी इम्पॉर्टेन्ट बात रख रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हमने एक बात तो कही थी कि आपको इस मुद्दे पर सुनना पड़ेगा। वे कितनी देर बोलेंगे, यह अलग बात है, लेकिन इसको जल्दी ही खत्म करेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपिंदर सिंहः सर, यह पिछली बार भी रह गया था। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः हम वह सब लाए हैं, आपको उत्तर देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः मंत्री जी आप जवाब दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री भूपिंदर सिंहः उपसभापति जी, हम सुनना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**... हमारा जवाब दे दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप हम लोगों की बात पर कुछ बोल दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः भूपिंदर जी बैठिए। ...**(व्यवधान)**... No, please don't do that. ...*(Interruptions)*...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हम सामान्य रूप से यह बताना चाहेंगे कि 2015-16 में 11,000 करोड़ रुपये का आवंटन राज्यों को किया गया था। यह जो 2015-16 का आवंटन था, यह दो किश्तों में जाता है। किसी सदस्य ने कहा कि पैसा नहीं गया, मैं बताना चाहता हूं कि दोनों किश्तों का पैसा चला गया है। इतना ही नहीं, बल्कि 2016-17 का राज्य आपदा कोष का जो 11,374 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, उसमें भी जो ये 10 सूखा प्रभावित राज्य हैं, उन 10 राज्यों की प्रथम किश्त की राशि भी बिना vote on account के भेज दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है।

महोदय, राज्यों से ये जो पैसे मांगे जाते हैं, हम उसको ठीक से नहीं दे रहे हैं, ऐसे आँकड़े हमारे कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे। वे बता रहे थे कि राष्ट्रीय आपदा कोष से पैसे मांगे जाते हैं और हमारी सरकार ठीक से वह पैसा नहीं दे रही है। वे जितना मांगते हैं, हम उतना नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सदन के भी और देश के किसानों के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में देश के विभिन्न राज्यों ने राष्ट्रीय आपदा कोष से 4 साल में एक लाख करोड़ रुपए की मांग की थी। हम अभी राज्यवार और जिलावार डिटेल्स नहीं बता पाएँगे, इन 4 वर्षों में देश के राज्यों ने जो मांगा ...**(व्यवधान)**...

श्री के. सी. त्यागीः 'पैसे मांगे जाते हैं' के बजाय 'राहत राशि आवंटित की जाती है', यह कहना ज्यादा अच्छा होगा और यह parliamentary भी है।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं बता रहा हूँ। 4 वर्षों के अंदर एक लाख करोड़ रुपए की मांग की गई थी और राज्यों को 13 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। यह 4 साल का रिकॉर्ड है कि NDRF से 13,762 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। वर्ष 2014-15 में जब मोदी सरकार आई, तो इसी तरह से राज्यों ने कुल मिला कर NDRF से 42 हजार करोड़ रुपए की राशि मांगी, तो मोदी सरकार ने राज्यों को 9,017.99 करोड़ रुपए दिए। अब आप बताइए कि 4 साल में एक लाख करोड़ के बदले 13 हजार करोड़ और इस सरकार में 42 हजार करोड़ के बदले 9 हजार करोड़! अब उस

[श्री राधा मोहन सिंह]

बात को छोड़ दीजिए, वह बात पुरानी हो गई। इस 2015-16 में हमने अभी तक खरीफ में 10 राज्यों के लिए 12,773 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और ज्यों कर्णाटक में सूखे का संकट आया, तो उसके लिए भी 723 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नीरज शेखरः मंत्री जी, इसका मतलब है कि हमारे देश में दो साल में ज्यादा दैवी आपदाएँ आ गईं।

श्री राधा मोहन सिंहः मैं जब 4 साल की चर्चा कर रहा था, तो उसी में 2009-10 में जो आपदा आई थी, वह भी शामिल थी। वह एक भीषण आपदा थी। उसके कारण आवंटन ज्यादा नहीं बढ़ा है, बल्कि यह ज्यादा इसलिए बढ़ा है, क्योंकि इस सरकार ने मानकों में परिवर्तन किया है। आप इसको ध्यान में रखिए कि मानकों में परिवर्तन किया गया है।

अभी जैसे कर्णाटक की बात हो रही थी। कर्णाटक ने 2011-12 में 6,200 करोड़ रुपए की मांग की थी, जबकि उस समय उसको 469 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। इसी प्रकार उसने 2012-13 में 7,672 करोड़ रुपए मांगे, तो केंद्र ने 526 करोड़ रुपए दिए। जब मोदी सरकार के समय 2015-16 में 3,800 करोड़ रुपए की मांग की गई, तो उसको 1,500 करोड़ रुपए दिए गए। अब आप इस आँकड़े को देखिए। पुनः 2015-16 में रबी के सूखे के लिए कर्णाटक सरकार ने 824 करोड़ रुपए की मांग की थी, जबकि उसको 723 करोड़ रुपए मिले हैं। यदि हम इन आँकड़ों को देखें, तो हमें स्थिति का पता चलेगा। हम सभी राज्यों के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हमारे कुछ माननीय सदस्य इस विषय को उठा रहे थे, जैसे तेलंगाना के माननीय सदस्य यह विषय उठा रहे थे, उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य भी यह विषय उठा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यों के ज्ञानवर्द्धन की भी कोशिश करूँगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अंतर बहुत साफ नजर आता है। सूखे और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश ने जितना मांगा, उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार ने उसकी भरपूर मदद नहीं की थी। उदाहरण के लिए 2009-10 में सबसे बड़ा सूखा पड़ा था और उस समय आपने मांगे थे 12,133 करोड़ रुपए, जबकि आपको 515 करोड़ रुपए मिले थे। 2015-16 में सूखा पीड़ितों के लिए आपने 2,057.79 करोड़ रुपए मांगे थे, जबिक हमने 1,304 करोड़ रुपए दिए।

2013-14 में ओलावृष्टि और 2014-15 में अतिवृष्टि आई थी, उस समय 2,801 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। आज तक के इतिहास में राष्ट्रीय आपदा कोष से उत्तर प्रदेश को जितनी राशि दी गई है, उतनी कभी नहीं दी गई। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेंद्र बुढानियाः आप जो चार साल के आँकड़े बता रहे थे। ...**(व्यवधान)**... चार साल पहले पैसे की जो वैल्यू थी, उसके मुकाबले आज कितनी वैल्यू रह गई है?

श्री राधा मोहन सिंहः अब मनरेगा की चर्चा होगी। ...**(व्यवधान)**... आपको अब मनरेगा के बारे में सुनना होगा। ...**(व्यवधान)**... जहां तक मनरेगा का सवाल है, सब देशवासी और हम सब लोग इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि आजादी के बाद एक लम्बे कालखंड के अंदर देश में एक तरफ अमीरों की अमीरी बढ़ी और दूसरी तरफ गरीबों की गरीबी भी बढ़ी, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। इस बीच में गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारे नारे भी लगाए गए, लेकिन उसका परिणाम इस रूप में हमारे सामने आया कि हमको मनरेगा शुरू करना पड़ा।

श्री आनन्द शर्माः क्या हमने गलत काम किए थे? ...**(व्यवधान)**... क्या मनरेगा गलत है? ...**(व्यवधान)**... मंत्री महोदय, आप कहना क्या चाहते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः जब आप सुनिएगा, तभी तो मेरा कहना समझिएगा। ...**(व्यवधान)**...जब आप सुनेंगे, तभी मेरे भाव को समझेंगे। ...**(व्यवधान)**... जब आप सुनेंगे, तभी मेरी बात समझेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः आप मोदी सरकार के कामों का हिसाब दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं हिसाब दे रहा हूं, आप सुनिए तो सही। ...**(व्यवधान)**... जो नारे दिए गए ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः आप चुनाव का भाषण दे रहे हैं या चर्चा का उत्तर दे रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः अगर उस समय निष्ठा से काम किया गया होता, तो मनरेगा की जरूरत ही न पड़ती। ...**(व्यवधान)**... मनरेगा बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जितने नारे लगाए गए, उस निष्ठा से अगर वह काम किया गया होता, तो मनरेगा की जरूरत ही नहीं पड़ती। ...**(व्यवधान)**... यह निश्चित रूप से हमारी विफलताओं का परिणाम है कि हमको मनरेगा चलाना पड़ा। ...**(व्यवधान)**... यह अच्छी योजना है और यह बात आपको पता है कि यह सरकार किसी भी कीमत पर इसे बंद करने वाली नहीं है। देश में जितने भी सूखे से प्रभावित जिले हैं, वहां पर हमने इसे 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। अगर हमें इसे बंद करना होता, तो हम इसके दिन क्यों बढ़ाते?

श्री आनन्द शर्माः सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार को आदेश दिया था। ...**(व्यवधान)**... आपने रोजगार नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**... आपने राज्यों को पैसा नहीं दिया। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः आप सुनिए। ...**(व्यवधान)**... पहले आप पूरी बात तो सुनिए। मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister complete the reply. ...(*Interruptions*)... After he completes the reply, ...(*Interruptions*)... Now, please listen. ...(*Interruptions*)... It is now like a market. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रमोद तिवारीः आपके प्रधान मंत्री ने क्या किया? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप लोग बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैंने अभी जो बोला है, वह बात भी प्रधान मंत्री जी बोले थे। ...**(व्यवधान)**... मैंने कहा कि गरीबी हटाओ के नारे अगर निष्ठा से लगाए गए होते, तो मनरेगा की जरूरत ही न पड़ती।

श्री उपसभापतिः मंत्री साहब, आपको जो रिप्लाई देना है, चेयर को एड्रेस करते हुए दीजिए। Don't listen to anybody. ...(*Interruptions*)... After he completes the reply, if you want to ask I will allow. ...(*Interruptions*)...

श्री के. सी. त्यागीः सर, मेरा एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: After he completes the reply, if you are very particular, I will allow one or two people. ...(*Interruptions*)... Now it is like a market. I don't want it to be like that. Hon. Minister, address the Chair. ...(*Interruptions*)... You address the Chair. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार से पहले, 2012-13 में 33,000 करोड़ रुपये और 2013-14 में भी 33,000 करोड़ रुपये आवंटित हुए। 2014-15 में, मोदी सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 2015-16 में 34,699 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया। 2006 के बाद पहली बार, RE के स्तर पर जितना बजट एलोकेशन था, उसे बढ़ाकर इसे 37,088 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह रुपया लगभग खर्च हो चुका है। मोदी सरकार के आने के बाद मनरेगा अधिनियम में भी संशोधन किया गया है। यह संशोधन 21 जुलाई, 2015 को किया गया और राज्यों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तर पर मनरेगा के तहत लागत के हिसाब से किए जाने वाले कार्यों का 60 प्रतिशत खर्च कृषि और संबधित गतिविधियों पर किया जाए। मनरेगा के अधिनियम के जो मास्टर परिपत्र हैं और उनमें इसका विस्तार से वर्णन करने से कृषि कार्य पर उसका परिणाम हुआ कि कई राज्यों ने इस वर्ष 62-63 प्रतिशत पैसा कृषि कार्यों पर खर्च किया है और वित्तीय वर्ष 2016-17 में 38,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह साबित करता है कि मनरेगा— पिछले 30-40 वर्षों में यदि गरीबी हटाने के लिए युक्तिसंगत काम किए गए होते, तो इस सरकार को इतना ज्यादा खर्च इस पर नहीं करना पड़ता या आप भी रहते अथवा दूसरा भी कोई रहता, तो उसे इतना खर्च नहीं करना पड़ता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Minister, tell me how much more time will you take because if you take more time, then the Bill will not be taken up. There is, at least, one Bill to be taken up. So, try to conclude.

श्री राधा मोहन सिंहः जी, सर। महोदय, बुन्देलखंड पैकेज एक इम्पॉटेंट विषय है। इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे। यह बुन्देलखंड पैकेज पुराना है। मैं इतनी ही विनती करूँगा कि बुन्देलखंड पैकेज दो राज्यों को गया और उसके जिले भी नोटिफाइड थे। जरा आंकड़ा देख लें कि पड़ोसी राज्य को यह जो पैकेज गया, तो उसके जितने जिले थे, उनमें सिंचाई का एरिया कितना बढ़ा और उत्पादन कितना बढ़ा तथा उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्पादन कितना बढ़ा और सिचिंत एरिया कितना बढ़ा? यह साबित कर देगा कि बुन्देलखंड पैकेज का किस प्रकार से इन्होंने दुरुपयोग किया। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, दूसरी बात, मेरी विनती आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से यही होगी कि इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश के लिए 321 करोड़ रुपए का पैकेज गया है। वह पड़ोसी राज्य से सबक ले और जिस प्रकार से उस पैसे का वहां दुरुपयोग होता है, उसको कम करे। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, अब मैं एक ही विषय पर अपनी बात कह कर समाप्त करूँगा। ...**(व्यवधान)**... मैं एक विषय पर अपनी बात कह कर समाप्त करूँगा। अभी आदरणीय अहमद पटेल साहब कुछ

बोल रहे थे। आपके माध्यम से मैं यह जानकारी जरूर चाहूँगा कि ये माननीय सदस्य गुजरात से आते हैं, वहां पर आज से 8 वर्ष पहले नर्मदा बांध का काम पूरा हुआ। 6 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री भारत सरकार के पास दौड़ते रहे कि उसकी growth का काम हो जाए और किसानों को पानी मिल जाए, लेकिन यह काम 6 वर्षों तक नहीं हुआ, इसकी अनुमति नहीं मिली। जब से नयी सरकार दिल्ली में आई है, तो 13 दिन के अन्दर वह काम हुआ है, तैयार होने को है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, ये जो सिंचाई की परियोजनाएँ हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः क्या नर्मदा का पानी पहले गुजरात नहीं पहुँचा था? ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं तो चेयर की तरफ मुखातिब हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री आनन्द शर्माः उपसभापति महोदय, आप इनसे पूछिए कि क्या नमर्दा का पानी पहले गुजरात में नहीं पहुँचा था? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रमोद तिवारीः वहां पानी का संकट है और आप पानी पीकर बैठे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री मुख्तार अब्बास नक़वीः आपको पानी पी-पीकर जवाब मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, उमा जी अभी बात कर रही थीं। आदरणीय पवार साहब ने भी एक विषय को रखा है और एक माननीय सदस्य ने भी कहा है कि 20-25 वर्षों तक योजनाओं को पूरा न करने का पाप माफ नहीं किया जा सकता है। किसी सदस्य ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं वैसी भाषा बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ कि ये जो 89 परियोजनाएँ हैं, ये वृहत् और लघु परियोजनाएँ हैं। ये 15, 20, 25 वर्षों से पड़ी हुई हैं। आखिर क्या कारण है कि इस सरकार ने इस वर्ष उनमें से 30 योजनाओं को इसी वर्ष पूरा करने के लिए 12,700 करोड़ का अलग से बजटीय प्रावधान किया है? 12,700 करोड़ रुपए का अलग से बजटीय प्रावधान किया गया है और 89 परियोजनाओं में 2018 तक हम 40 को पूरा कर सकें, इसके लिए नाबार्ड के सहयोग से 20,000 हजार करोड़ रुपए के कॉरपस फंड का भी निर्माण किया गया है। क्या यह काम पहले नहीं हो सकता था? "पर उपदेश कुशल बहुतेरे!" यह काम खुद करना चाहिए था।

महोदय, आदरणीय पवार साहब के किसी भी सवाल का उत्तर मैं इसलिए नहीं दे सकता, क्योंकि उनका जो मागदर्शन था, वह सौ प्रतिशत देश के हित में था। इसमें कहीं किसी का मतभेद नहीं हो सकता है और उसमें कहीं भी राजनीति नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... हमने लोक सभा में जो उत्तर दिया था, उस उत्तर में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो अखबारों में खबरें आ रही हैं कि राजस्थान के अंदर कुछ इलाकों में बारिश सबसे कम हुई, उससे ज्यादा मिलीमीटर बारिश मराठवाड़ा, कोंकण आदि इलाकों में हुई है। सूखे का बड़ा कारण वर्षा कम होना है, लेकिन अखबार लिखता है कि यदि यही कारण होता, तो जिन इलाकों में उससे कम बारिश हुई, वहां इस प्रकार की भयावह स्थिति होती। अखबार इसके दूसरे कारण बता रहे हैं। अखबार में बताया जा रहा है कि वहां पर जो बाधों के निर्माण किए गए, जो बड़े-बड़े बांध हैं, जिनको 'तीर्थ' बोलते हैं, वे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हैं। यह हमने अखबार में पढ़ा था। मैं गन्ना उत्पादक हूँ, आज़ादी के पहले चम्पारण में 52 चीनी मिलें थीं और आज भी यदि सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं, तो चम्पारण में हैं और ध्यान में होगा कि जब यह सरकार आई थी, तब उसने गन्ना किसानों को 21,000 करोड़ रुपए बांट थे। कितने उपक्रम किए गए हैं, तब जाकर वह बकाया

[श्री राधा मोहन सिंह]
एक हजार करोड़ रुपए से नीचे आया है। मेरी गन्ना किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। हम खुद एक किसान हैं, लेकिन गन्ना मिलों के हितों को ध्यान में रखते हुए बाधों का निर्माण किया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय संतुलन नहीं रहा। किसानों की सबसे ज्यादा असिंचित भूमि उसी इलाके में रही, यह अखबार का कहना है। सर, अखबार में गलत खबर भी आती है। ...**(व्यवधान)**... मैंने ही वहां पर मांग की थी कि इस पर अलग से एक बार चर्चा हो जाए। चूंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं, इसलिए इस पर अलग से एक बार चर्चा हो जाए। मेरा गन्ना मिल और गन्ना किसान के प्रति कोई विक्षोभ नहीं था और आज भी मैं आदरणीय पवार साहब को इसके लिए कहना चाहूंगा कि मेरा विषय सिर्फ इतना है कि इसमें असलियत क्या है, इस पर एक बार चर्चा हो। इसका कारण यह है कि हम सब लोगों को मिल कर किसान का भला करना है। अपनी राजनीति का भला आड़ में जरूर करें, लेकिन जब पोल खुलती है, तब भारी नुकसान होता है। जब किसान के बीच पोल खुल जाएगी कि आप राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका नुकसान होता है। हम सब लोग राजनीति करने वाले हैं। देश तब समृद्ध बनेगा, जब देश का किसान समृद्ध बनेगा, इसी भाव से हम सब बोल रहे हैं। जब हम सब इसी भाव से बोल रहे हैं, तो इस भाव से करने में क्यों दिक्कत आती है या इतने दिनों तक ऐसा करने में क्यों दिक्कत आई?

अब 'प्रधान मंत्री सिंचाई योजना' है। मैं आदरणीय शरद जी से विनती करना चाहूंगा कि जल का कम से कम उपयोग हो, per drop, more crop. अब चार-पांच ऐसे राज्य हैं, आदरणीय शरद जी को भी अनुभव होगा, इनके समय में भी हुआ होगा, लेकिन हम तो दो साल से उसको माइक्रो इरिगेशन के लिए पैसा दे रहे हैं, वह पैसा खर्च नहीं हो रहा है। अब राज किस पार्टी का है, यह अलग विषय है। अगर हम राज्य का नाम ले लेंगे, तो फिर वह पोलिटिकल हो जाएगा। हम एक कॉपी आप सबके पास भेजते हैं। यहां पर सवाल पैसे का नहीं है। माननीय सदस्य ओडिशा की चर्चा कर रहे थे। मैं वहां गया, बैठक की। अब वहां RKVY का पैसा ही खर्च नहीं हुआ, मुझको नहीं लगता है कि पैसे का सवाल है। सवाल पैसे का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि जो पैसा जा रहा है, उसका उपयोग हो और राज्य सरकार भी अपने-अपने खजाने से किसान के हित में खर्चा करे। हम सब लोग जिस राज्य में भी जाएं, राजनीतिक काम से भी जाएं, तो राज्य सरकार के साथ बैठ कर बात करें। हम अपने यहां से सब जानकारी सबको उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी की बहुत साफ सोच है कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। इसी सपने को पूरा करने में सरकार लगी हुई है। मेरा यह अनुरोध है कि आप सब आइए, मिलिए और हम सब मिल कर किसान को मजबूत बनाएं। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री शरद यादवः महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने विस्तार से यह तो बताया है कि क्या किया जा रहा है या क्या नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से राधा मोहन जी से फिर यह कहूँगा कि आज देश भर में आधी आबादी सूखे से प्रभावित है। आज का सबसे बड़ा मुद्दा पीने के पानी के संकट का है। आपसे मेरी विनती है कि भारत सरकार के बहुत लम्बे हाथ हैं। सूखे के मामले में ऐसे कई इलाके हैं, जहां स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं झारखंड के लोगों से बात कर रहा था, वहां के लोग आए हुए थे। लातूर में जो स्थिति है, उससे ज्यादा विकट स्थिति झारखंड में है, बुंदेलखंड में है। मैं कहूँगा कि देश भर के

सारे मामलों को इकट्ठा कर एक बयान दिया जाना चाहिए कि भारत सरकार उन मामलों से किस प्रकार निपटेगी, ताकि पानी का संकट दूर हो। इंसान को पीने का पानी तो हर घंटे चाहिए। पानी ही एक ऐसी चीज़ है, जिसके लिए हिन्दुस्तान के गांवों के किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत और त्रासदी होती है। वह जब कभी किसी से मिलता है, कहीं उठता है या बैठता है, तो उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी पानी ही होती है, लेकिन आज उसके लिए पीने के पानी की त्रासदी हो गई है। आपने जो कहा है, उस पर मैं ज्यादा विवाद नहीं करता, क्योंकि ये हार गए हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया था, इसलिए ये यहां आ गए हैं। ये बार-बार इसको न उठाएँ। यहां पीने का पानी तो सिर्फ आज का मामला था। मैं चेयर के माध्यम से कहूँगा कि आप फिर से एक बड़ा *suo motu* बयान दीजिए, जिससे पता चले कि सभी जगहों पर आप पीने के पानी के मामले में क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या प्रबंध कर रहे हैं। यह मेरी आपसे विनती है।

श्री गुलाम नबी आज़ादः सर, दो माननीय मंत्रियों ने यहां जवाब दिए हैं। 25 एमपीज़, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ के थे, जिनमें से 14 कांग्रेस पार्टी के थे और बाकी 11 दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ के थे, उन्होंने ही यह मांग की थी कि देश में जो सूखा है और पीने के पानी की जो कमी है, उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन बहुत निराशा हुई कि सूखे पर और पीने के पानी पर भी राजनीति ज्यादा हुई। मेरी बहन ने तो 20 दफा मोदी सरकार और माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 50 दफा मोदी सरकार कहा है। ...**(व्यवधान)**... मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मोदी साहब हम सब के प्रधान मंत्री हैं, लेकिन उस नाम को रिपीट करने से सूखे की स्थिति ठीक नहीं होगी, पानी की स्थिति ठीक नहीं होगी। शायद आप अंदाजा लगा चुके हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर दुनिया ने यह कहा है कि जमीन में पानी कम होने का सबसे बड़ा कारण ग्लोबल वॉर्मिंग है। यहां उसका सबसे बड़ा खतरा है और अगर वॉटर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो पूरी दुनिया एक डेज़र्ट बन जाएगी। जब आप यह चर्चा कर रहे थे कि वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 में पैसा कम दिया गया, तब आपको यह भी गिनना था कि तब शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी और हमने वर्ष 2011, 2012 और 2013 में भी रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन किया और उसका एक्सपोर्ट भी किया। आपने वर्ष 2014, 2015 और 2016 में पैसा इसलिए बढ़ाया, क्योंकि आप आपदा अपने साथ ले आए। यह सबसे बड़ी आपदा थी। ...**(व्यवधान)**... आप अपने साथ वर्ष 2014 और 2015 में सूखा लाए और पूरे देश को सूखा कर दिया, तो आपको पैसे ज्यादा देने ही पड़ेंगे। हमारे वक्त में यह स्थिति, यह आपदा नहीं थी।

मैं माननीय वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर से तीन-चार सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका कोई प्लान है? यह पैसे बढ़ाने से नहीं हुआ है। क्या आपका कोई शॉर्ट-टर्म, मीडियम-टर्म या लाँग-टर्म प्लान है? अब दो महीने के बाद बरसात आने वाली है। उसके लिए क्या माननीय मंत्री जी को यह नहीं कहना चाहिए था कि दो महीने के बाद जब जुलाई-अगस्त में monsoon आएगा और दक्षिण में तो जून से ही आएगा तो उस समय water conservation के लिए हमने यह short-term programme लिया है और इन दो महीने में हम इतने तालाब खोद रहे हैं, ताकि जब जून, जुलाई और अगस्त में बारिश आएगी तो इतना water conserve होगा। Irrigation projects के speedy completion के लिए आपने क्या योजना बनायी है? Minor and medium irrigation projects के लिए क्या योजना बनायी है? आज देश में सूखे से लोग मर रहे हैं, पानी के बगैर मर रहे हैं। क्या माननीय प्रधान मंत्री जी को सभी पार्टियों की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी?

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]
क्या माननीय प्रधान मंत्री जी को देश के सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए थी? क्या इसको national crisis के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए था? क्या इसका समाधान नहीं करना चाहिए था? क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में Finance Minister, Agriculture Minister, Rural Development Minister और Irrigation Minister की एक कमेटी, होम मिनिस्ट्री की एक Water Crisis Management Committee नहीं बननी चाहिए थी? क्या मुख्यमंत्रियों के अंडर, चीफ मिनिस्टर्स के अंडर जो Finance Minister, Irrigation Minister और जो concerned Ministers हैं, उनकी मीटिंग नहीं होनी चाहिए थी? यह राष्ट्रीय आपदा है। आप इसको मंत्रियों, सेक्रेट्रीज़ और फाइलों के बीच में मत लीजिए। अपोजिशन आपके साथ इस राष्ट्रीय आपदा में बराबर खड़ा रहेगा। प्लीज़ इसको राजनीति मत बनाइए और इसको मंत्रालयों की चारदीवारी और अफसरों तक सीमित मत रखिए। आप लोग जरा जाग जाइए क्योंकि आज देश में स्थिति बहुत भयंकर है।

†**قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)**: سر، دو مانئیے منتریوں نے یہاں جواب دیئے ہیں۔ 25ایم پی، جو کہ اپوزیشن پارٹیز کے تھے، جن میں سے 14 کانگریس پارٹی کے تھے اور باقی 11 دوسری اپوزیشن پارٹیز کے تھے، انہوں نے ہی یہ مانگ کی تھی کہ دیش میں جو سوکھا ہے اور پینے کے پانی کی جو کمی ہے، اس پر بحث ہونی چاہئے۔ لیکن بہت مایوسی ہوئی کہ سوکھے پر اور پینے کھے پانی پر بھی سیاست زیادہ ہوئی۔ میری بہن نے تو بیس دفعہ مودی سرکار اور مانینے ایگری کلچر منسٹر نے پچاس دفعہ مودی سرکار کہا ہے۔ ...(مداخلت)... مجھے اس پر کوئی اپتی نہیں ہے۔ مودی صاحب ہم سب کے پردھان منتری ہیں، لیکن اس نام کو دوہرانے سے سوکھے کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، پانی کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ شاید آپ اندازہ لگاچکے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل لیول پر دنیا نے یہ کہا ہے کہ زمین میں پانی کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ یہاں اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور اگر واٹر منیجمنٹ نہیں ہوا تو پوری دنیا ایک ڈیزرٹ بن جائیگی۔ جب آپ یہ چرچہ کررہے تھے کہ سال 2009, 2010, 2011 اور 2012 میں پیسہ کم دیا گیا، تب آپ کو یہ بھی گننا تھا کہ تب شرد پوار جی کرشی منتری تھے، یوپی اے کی گورنمنٹ تھی اور ہم نے سال 2011, 2012 اور 2013 میں بھی ریکارڈ فوڈ پروڈکشن کیا اور اس کا ایکسپورٹ بھی کیا۔ آپ نے سال 2014, 2015 اور 2016 میں پیسہ اس لیے بڑھایا، کیوں کہ آپ آپدا اپنے ساتھ

† Transliteration in Urdu script.

لے آئے۔ یہ سب سے بڑی آپدا تھی۔ ---(مداخلت)--- آپ اپنے ساتھ سال 2014 اور 2015 میں سوکھا لائے اور پورے ملک کو سوکھا کردیا، تو آپ کو پیسے زیادہ دینے ہی پڑیں گے۔ ہمارے وقت میں یہ حالت، یہ آپدا نہیں تھی۔

میں مانیئے واٹر ریسورس منسٹر سے تین چار سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا کوئی پلان ہے؟ یہ پیسے بڑھانے سے نہیں ہوا ہے۔ کیا آپ کا کوئی شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم پلان ہے؟

اب دو مہینے کے بعد برسات آنے والی ہے۔ اس کے لیے کیا مانیئے منتری جی کو یہ نہیں کہنا چاہیئے تھا کہ دو مہینے کے بعد جب جولائی اگست میں مانسون آئے گا اور دکشن میں تو جون سے ہی آئے گا تو اس وقت واٹر کنزرویشن کے لیے ہم نے یہ شارٹ ٹرم پروگرام لیا ہے اور ان دو مہینے میں ہم اتنے تالاب کھود رہے ہیں، تاکہ جب جون، جولائی اور اگست میں بارش آئے گی تو اتنا واٹر کنزرو ہوگا۔ اِرّیگیشن پروجیکٹ کے اسپیڈی کمپلیشن کے لیے آپ نے کیا یوجنا بنائی ہے؟ مائنر اینڈ میڈیم اِرّیگیشن پروجیکٹ کے لیے کیا یوجنا بنائی ہے؟ آج دیش میں سوکھے سے لوگ مررہے ہیں، پانی کے بغیر مررہے ہیں، کیا مانیئے پردھان منتری جی کو سبھی پارٹیوں کی میٹنگ نہیں بلانی چاہیئے تھی؟ کیا مانیئے پردھان منتری جی کو دیش کے سبھی مکھیہ منتریوں کی میٹنگ نہیں بلانی چاہیئے تھی؟ کیا اس کو نیشنل کرائسز کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیئے تھا؟ کیا اس کا سمادھان نہیں کرنا چاہیئے تھا؟ کیا پردھان منتری کی ادھیکشتا میں فائننس منسٹر، ایگری کلچر منسٹر، رورل ڈیولپمنٹ منسٹر اور اِرّیگیشن منسٹر کی ایک کمیٹی، ہوم منسٹری کی ایک واٹر کرائسز منیجمنٹ کمیٹی نہیں بنّی چاہیئے تھی؟ کیا مکھیہ منتریوں کے انڈر جو فائننس منسٹر، اِرّیگیشن منسٹر اور جو کنسرنڈ منسٹر ہیں، ان کی میٹنگ نہیں ہونی چاہیئے تھی؟ یہ راشٹریہ آپدا ہے۔ آپ اس کو منتریوں، سکریٹریز اور فائلوں کے بیچ میں مت لیجئے۔ اپوزیشن آپ کے ساتھ س راشٹریہ آپدا میں برابر کھڑی رہے گی۔ پلیز اس کو راجنیتی مت بنائیے اور اس کو منترالیوں کی چہاردیواری اور افسروں تک محدود مت رکھیئے۔ آپ لوگ ذرا جاگ جائیے کیوں کہ آج دیش میں حالت بہت خطرناک ہے۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri K. C. Tyagi. ...(*Interruptions*)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you. ...(*Interruptions*)... त्यागी जी, सिर्फ प्रश्न पूछिएगा।

श्री के. सी. त्यागीः सर, मैं एक ही मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। **...(व्यवधान)...**

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tyagiji, put only questions. ....(*Interruptions*)...Put only questions. ...(*Interruptions*)... सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री के. सी. त्यागीः उपसभापति महोदय, मैंने अपने संबोधन में अपने आपको राजनीति से ऊपर उठाकर **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. ...(*Interruptions*)... Put only questions. सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री के. सी. त्यागीः मंत्री जी सारे सवालों के जवाब राजनीति में दे रहे थे। सबसे बड़ा सवाल जो सदन में उठकर आया और इधर से, अकाली दल के लोगों से लेकर उधर तक, सब लोगों ने कहा कि जो किसान प्रभावित हैं, उनके कर्जे माफ होने चाहिए। इनके वक्तव्य में उसका ज़िक्र तक नहीं है। दूसरा, उन इलाकों के किसानों के बच्चे, जो सूखा प्रभावित हैं, उनके बच्चों की जो पढ़ाई है, उसके लिए उन्होंने जो कर्जा लिया है, वह माफ होना चाहिए। हमने उनसे इस बात का ज़िक्र किया था। उसका भी कोई जवाब नहीं है। मनरेगा में कम से कम डेढ़ सौ दिन का काम इन affected areas में होना चाहिए, उसके लिए कोई राहत नहीं है। पीड़ित किसानों को मुफ्त बीज, खाद **...(व्यवधान)...** इनकी सहयोगी पार्टी है, अकाली दल के सदस्यों ने सवाल उठाया **...(व्यवधान)...** उसका कोई जिक्र नहीं है।

श्री उपसभापतिः त्यागी जी, प्रश्न पूछिए। No time for discussion.

श्री के. सी. त्यागीः सर, यह प्रश्न ही है। **...(व्यवधान)...** नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सूखा पीड़ितों को पीडीएस से राशन तुरंत रिलीज़ किया जाए। मंत्री जी गैरहाज़िर हैं, सवाल किससे पूछें? यह सवाल पीडीएस से जुड़ा हुआ है। **...(व्यवधान)...**

SHRI PRAMOD TIWARI: Mr. Deputy Chairman, Sir, ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I told you I will call. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... He is speaking. ...(*Interruptions*)... Are you not seeing? ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Are you not seeing he is speaking? ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)...

7.00 P.M.

SHRI PRAMOD TIWARI: After him, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will decide. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... I will decide. ...(*Interruptions*)... Sit down. ...(*Interruptions*)... No, no. ...(*Interruptions*)... Your Leader spoke. ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)...

श्री के. सी. त्यागीः सर, शरद जी कुछ कहना चाहते हैं इसलिए मैं बैठना चाहता हूं लेकिन मैं घोर निराश हुआ हूं। ये तीन बार पहले भी जवाब देना चाहते थे, तब भी इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Fine.

श्री के. सी. त्यागीः अब इनका जवाब **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right.

श्री के. सी. त्यागीः राजनीति से जुड़ा हुआ है, जबकि हमारे सुझाव **...(व्यवधान)...** के साथ दिए गए थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sharad Pawar.

श्री शरद पवारः उपसभापति जी, मुझे दो सवाल पूछने हैं। सूखे की समस्या हल करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, सदन के सामने यह बात आती है। जब सूखा आता है तो फसल जाती है, चाहे ज्वार की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, एक पूरी फसल जाती है, नुकसान होता है तो एक सीज़न का होता है। भारत सरकार ने Horticulture Mission नाम की एक स्कीम दी हुई है। Horticulture के लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को बहुत मदद की है। Horticulture की जो क्रॉप है, चाहे आम की हो, चाहे सपोटा की हो, चाहे स्वीट लाइम हो, यह बागवानी की क्रॉप खत्म हो जाएगी क्योंकि आगे के 20 सालों का नुकसान किसानों को होता है। इसलिए तीन साल पहले जब ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, तो भारत सरकार ने बागवानी की फसल बचाने के लिए मदद दी थी, उसकी सही फिगर मुझे याद नहीं है, हर हैक्टेयर को खाली टैंकर से पानी देकर बागवानी, बगीचा बचाने के लिए राज्य सरकार को दिए थे। इस समय इस बारे में कुछ सोचने की तैयारी इस सरकार की है क्या? यह मेरा पहला सवाल है।

दूसरी बात यह है कि अभी एक-दो महीने सूखे की परिस्थिति है। बारिश के बारे में जो predictions हैं, वे अच्छे हैं। अगर जून महीने में अच्छी बारिश देश में आ गयी, तो जो सूखाग्रस्त किसान हैं, ये सब defaulter हो गए, चाहे cooperative bank हो, चाहे nationalised bank हो। उन्होंने जो पैसा लिया है, उसे वापस नहीं कर सकते, इसलिए वे defaulter हो गए। जून में अच्छी बारिश आने के बाद उनको crop loan नहीं मिलेगा, तो न seed उनके पास आएगा, न उनके पास खाद होगी, न मेहनत करने की परिस्थिति होगी। ऐसी परिस्थिति में जो आज उनके ऊपर बोझ है, उसको आप चाहे तो माफ करो, नहीं तो कम से कम reschedule करो। क्या आप उनका crop loan मिलने का आगे का रास्ता खोल सकते हैं? इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। क्या इस बारे में सरकार ने कोई विचार किया है?

श्री संजीव कुमारः सर, सरकार का सर्वे बताता है कि झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछली बार भी वहां पर सुखाड़ हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप वहां के किसानों को compensate कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके लोन माफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप तुरंत वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Those who did not speak...(*Interruptions*)...

SHRI BHUPINDER SINGH: Sir, I have given a notice.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You did not speak. That is enough. Shri Pramod Tiwari. That will be the last question. No more questions after this.

श्री प्रमोद तिवारीः सर, मेरा एक सीधा सा सवाल माननीय मंत्री जी से है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर किसानों ने आत्महत्या की है और रिकार्ड में भी है कि सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। **...(व्यवधान)...**

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः सर, हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। **...(व्यवधान)...**

श्री प्रमोद तिवारीः सर, देश में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। **...(व्यवधान)...** मैं आपको याद नहीं दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल से सदन में बैठे हुए बहुत से लोगों को याद होगा **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, I am asking the question. सवाल यह है कि उस समय किस मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि किसान फसल की वजह से आत्महत्याएं नहीं कर रहे हैं, बल्कि और कारणों से आत्महत्याएं कर रहे हैं। **...(व्यवधान)...** प्यार संबंधों की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं, प्यार में असफलता की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह आपकी संवेदनहीनता किसानों के लिए है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. ...(*Interruptions*)...

श्री प्रमोद तिवारीः मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या किसानों का कर्जा केंद्र सरकार माफ करेगी? ये आत्महत्याएं रुक सकें, जो परिवार पीड़ित हैं, उनकी जान बचाई जा सके, तो क्या आप यहां पर घोषणा करेंगे कि जो केंद्रीय कर्ज है, उसको माफ किया जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the end. ...(*Interruptions*)...

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने भाषण के दौरान बताया कि साढ़े सात हजार करोड़ रुपया बुदेंलखंड पैकेज का दिया गया था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. ...(*Interruptions*)...

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः लेकिन बीच में उस पैसे को रोक दिया गया। बुंदेलखंड पैकेज का जितना पैसा मिलना चाहिए था, वह पैसा पूरा नहीं मिला है, वह पैसा रुका हुआ है। मैं आपके

माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे उस रुके हुए पैसे को फिर से बुंदेलखंड के लिए रिलीज़ करेंगे या और पैसा बढ़ाकर बुंदेलखंड क्षेत्र को देंगे? बुंदेलखंड में तमाम समस्याएं हैं...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramakrishna. ...(*Interruptions*)...

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसानों का कर्जा माफ करने की सरकार की कोई योजना है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is over. ...(*Interruptions*)...

डा. चंद्रपाल सिंह यादवः दूसरी बात यह है कि हमने अपने भाषण के दौरान कहा था कि वहां तालाबों को बनाने के लिए सरकार को तुरंत पैसा उपलब्ध कराना चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else will go on record.

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA (Karnataka): I have one suggestion to make. Internationally drought is recognised as a disaster. Now, the UNDP has a regular Disaster Management Group which considers drought. Why can't we also give this work to the National Disaster Management Authority?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Bhupinder Singh, this will be the last question and then the Minister will reply.

SHRI BHUPINDER SINGH: Our hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik has written, time and again, to the Prime Minister and to the Finance Minister that we are giving ₹ 1,300 crores. NABARD has to support us for the kharif loan.

Until summer holidays for the students, the Odisha Government has decided to provide mid day meals to all the school children; and ₹ 55 extra is being given to the workers in the entire 27 drought affected districts under the MGNREGA scheme. Will the Government extend support to the Odisha Government? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Bhupinder Singh, please sit down. Let the Minister reply.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, जैसा कि आदरणीय शरद जी ने कहा है कि बागवानी विषय या चारा विकास कार्यक्रम, जो पहले से चल रहा है, जब भी सूखा आता है, तो उसके तहत जो विशेष मदद की जाती है, वह आज भी चल रही है। हम बीज पर जो राज्य सहायता देते थे, वह पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विषय के तहत देश के 14 राज्यों में या 16 राज्यों में लागू थी, अब उसे देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। अब सभी राज्यों में सूखा आने पर बीज पर भी 50 फीसदी की राज्य सहायता बढ़ाई जाएगी। अभी झारखंड के तथा अन्य सदस्यों ने जो पीने के पानी का सवाल उठाया है, तो मैंने पहले भी कहा है कि क्रियान्वयन राज्य सरकारों को करना है और मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि झारखंड के पास unspent balance

[श्री राधा मोहन सिंह]

21st April, 2016 तक 76 करोड़ रुपया उनके पास पड़ा हुआ है और हमने इस साल का 20 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीज़ कर दिया है। मेरे पास एक सूची है। उसको पूरा पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास 12-13 राज्यों के नाम हैं, जो सूखे से प्रभावित हैं। उनके पास जो 2015-16 की राशि है, उसको भी वे 21st April तक खर्च नहीं कर पाए हैं। बावजूद इसके 2016-17 की किश्त भी राज्यों को जारी की गई है। जहां तक प्रमोद तिवारी जी का सवाल है कि किसानों के विषय में किस मंत्री ने इस पर जवाब दिया था कि किसानों की आत्महत्या प्रेम प्रसंग के कारण भी होती है। यहां पवार साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने तीन-तीन बार जवाब दिया है। इससे पहले इसी सदन में आपके दो मंत्रियों ने जवाब दिया है, वे ठीक से बता पाएंगे। मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। तिवारी जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No intervention. ...(*Interruptions*)... No intervention. ...(*Interruptions*)... Sit down. Let him finish the reply.

श्री प्रमोद तिवारीः *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not going on record. ...(*Interruptions*)... This can't be done. ...(*Interruptions*)... Only what the Minister is saying will go on record. You ignore that.

श्री राधा मोहन सिंहः किसानों के संबंध में जो जवाब कांग्रेस के मंत्री आदरणीय शरद जी ने दिया, इस सरकार के मंत्री ने भी दिया है। इसमें न शरद जी की गलती है, न कांग्रेस के दो मंत्रियों की गलती है और न यहां के मंत्री की गलती है। चूंकि जो पहले सरकार चल रही थी, वह राज्यों से जो रिपोर्ट मांगती थी, उसमें किसानों की आत्महत्या के अलग से कारण नहीं मांगती थी। उसका परिणाम यह होता था कि जो सुनियोजित हैं, उनकी आत्महत्या के जो कारण होते थे, वे एक साथ आते थे। इसके कारण आदरणीय शरद पवार जी हो या कांग्रेस के दो मंत्री हों... आप पूरी बात सुन लें। **...(व्यवधान)...** वे हों या बीजेपी के मंत्री हों, वे ऐसा जवाब नहीं देते थे, लेकिन मैं आज की सरकार को बधाई दूंगा कि इस सरकार के आने के बाद किसान की आत्महत्या के कारणों को अलग किया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Simply give the reply. Don't look at them. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंहः कारणों को अलग किया है। **...(व्यवधान)...** वे इस पर जो बयान देते थे, वह गलत था। **...(व्यवधान)...** यहां से जो बयान दिया गया, वह गलत था। **...(व्यवधान)...**राज्य सरकारों से भारत की सरकार उसी प्रोफॉर्मा में जवाब मांगती थी। **...(व्यवधान)...** यह मजबूरी थी। **...(व्यवधान)...** पिछली सरकार की भी थी, लेकिन हम आज की सरकार को बधाई देंगे कि उसने प्रोफॉर्मा अलग किया है कि किसान की आत्महत्या का कारण अलग बताओ। अब वे कारण राज्यों से नहीं आ रहे हैं। **...(व्यवधान)...** इसमें राज्य का भी कसूर नहीं था, किसी मंत्री ने भी जो बयान दिया है, उसका भी कसूर नहीं है। उस समय देश में जो सरकार चल रही थी, जो

---

*Not recorded.

प्रोफॉर्मा राज्यों को पच्चीस वर्ष पहले भेजा था, यह उस प्रोफॉर्मा का दोष था, लेकिन आज इस सरकार ने उस विसंगित को दूर कर दिया है। **...(व्यवधान)...**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Over, over. ...(*Interruptions*)...

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we are not satisfied with the reply of the hon. Minister. It is the most unsatisfactory reply that we have got. ...(*Interruptions*)... So, we are walking out. ...(*Interruptions*)...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

GOVERNMENT BILLS

The Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015

and

The Repealing and Amending (Third) Bill, 2015 — *Contd.**

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, let us take up The Appropriation Bills. ...(*Interruptions*)... I think, the Minister has moved both the Bills. So, those who want to speak may speak. Shri Ananda Bhaskar Rapolu; not there. Shri Veer Singh. ...(*Interruptions*)... Shri Veer Singh, are you speaking on the Appropriation Bills? ...(*Interruptions*)... I have taken up The Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015 and The Repealing and Amending (Third) Bill, 2015 for further consideration. These have already been moved yesterday. So, I am taking up further consideration of the Bills. I called Mr. Ananda Bhaskar Rapolu; he is not available. The next is, Shri Veer Singh. Are you speaking? ...(*Interruptions*)...

SHRI VEER SINGH (Uttar Pradesh): No, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Shri Bhupinder Singh. Are you speaking on this Bill?

SHRI BHUPINDER SINGH (Odisha): No, Sir. Members are not there. ...(*Interruptions*)... Let us take it up tomorrow, Sir. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not my point. ...(*Interruptions*)... That is not my point. Members are free to be here. I never asked anybody to go out.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति जी, इसको कल रखिए। **...(व्यवधान)...**

SHRI BHUPINDER SINGH: Please, Sir. Let us take it up tomorrow.

---

* Further discussion continued from 26th April, 2016.